



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

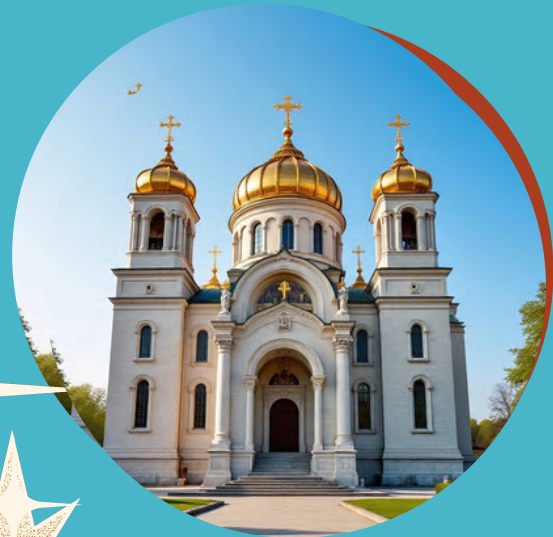


WEEKLY CURRENT AFFAIRS

15 - 21 FEB 2026

3RD WEEK OF FEBRUARY

150+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- National
- International
- Sports





Ques: As per RBI's draft directions, what action must banks take if mis-selling is established?

RBI के ड्राफ्ट निर्देशों के अनुसार, यदि गलत बिक्री (Mis-selling) साबित होती है तो बैंक को क्या करना होगा?

- A) Issue warning to employee only / केवल कर्मचारी को चेतावनी देना
- B) Pay 10% penalty to RBI / RBI को 10% जुर्माना देना
- C) Refund full amount and compensate for loss / पूरी राशि वापस करना और नुकसान की भरपाई करना
- D) Close customer's account / ग्राहक का खाता बंद करना
- E) No action required / कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

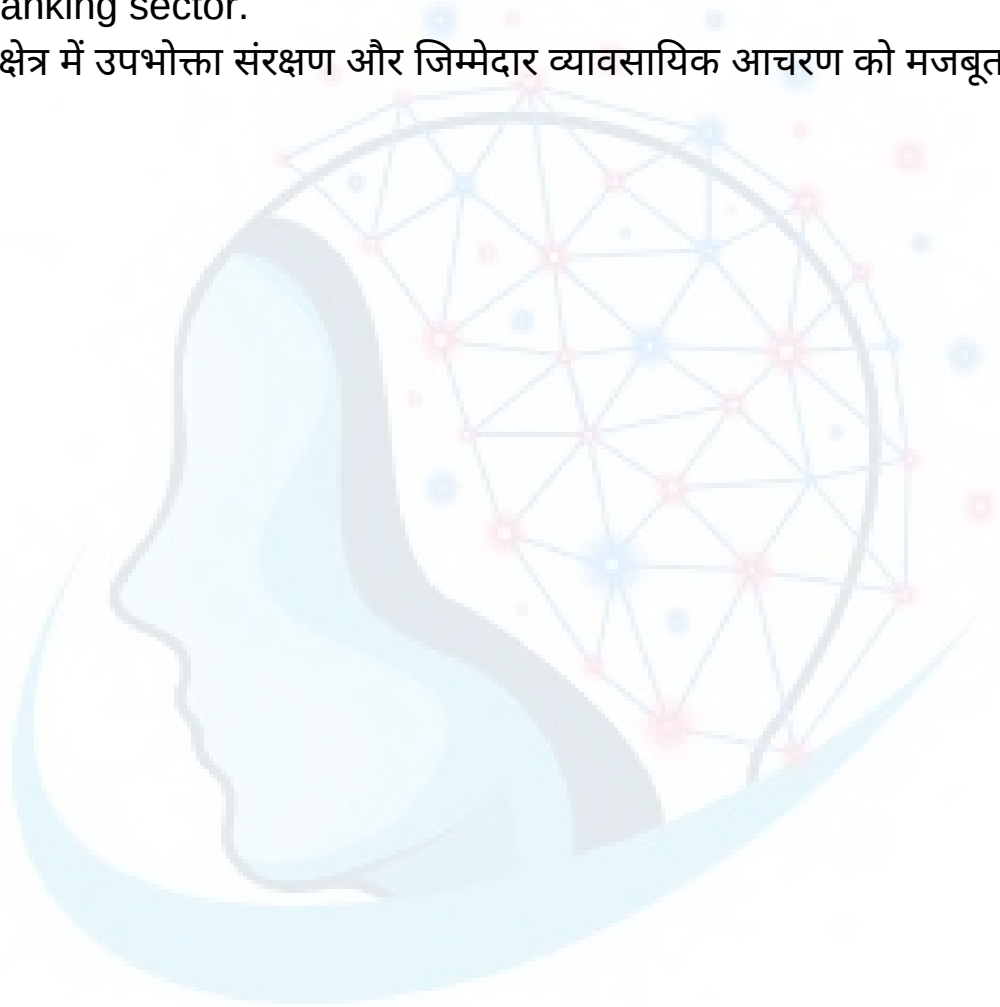
- The Reserve Bank of India (RBI) has issued comprehensive draft directions on advertising, marketing, and sales of financial products and services by banks.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री से संबंधित व्यापक ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं।
- The objective of these directions is to prevent mis-selling and compulsory bundling of financial products.
- इन निर्देशों का उद्देश्य गलत बिक्री (Mis-selling) और जबरन बंडलिंग को रोकना है।
- As per the Draft RBI (Commercial Banks – Responsible Business Conduct) Amendment Directions, 2026, banks must seek customer feedback within 30 days of sale.
- ड्राफ्ट RBI (वाणिज्यिक बैंक – जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) संशोधन निर्देश, 2026 के अनुसार, बैंकों को बिक्री के 30 दिनों के भीतर ग्राहक से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा।
- The new directions are scheduled to come into effect from July 1.
- ये नए निर्देश 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
- If mis-selling is established, banks must refund the entire amount paid by the customer.
- यदि गलत बिक्री साबित होती है, तो बैंक को ग्राहक द्वारा चुकाई गई पूरी राशि वापस करनी होगी।
- In addition, banks must compensate customers for any financial loss arising due to





mis-selling.

- इसके अलावा, गलत बिक्री के कारण हुए किसी भी वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति भी बैंकों को करनी होगी।
- These provisions aim to strengthen consumer protection and responsible business conduct in the banking sector.
- ये प्रावधान बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं।



EXAM
Genius





Ques: Which international financial institution approved a USD 182 million loan to Assam to strengthen resilience against flooding and riverbank erosion?

असम में बाढ़ और नदी तट कटाव से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने स्वीकृत किया?

- A) World Bank / विश्व बैंक
- B) International Monetary Fund (IMF) / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- C) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
- D) Asian Development Bank (ADB) / एशियन डेवलपमेंट बैंक
- E) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) approved a USD 182 million loan to Assam.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम को 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है।
- Objective: To expand support for strengthening Assam's resilience to chronic flooding and severe riverbank erosion along the Brahmaputra River.
- उद्देश्य: ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगातार बाढ़ और गंभीर नदी तट कटाव से निपटने की असम की क्षमता को मजबूत करना।
- ADB supports sustainable, inclusive, and resilient development across Asia and the Pacific.
- ADB एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत, समावेशी और लचीले विकास को समर्थन देता है।

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
- HQ : Manila, Philippines
- Members : 69
- Chief Economist : Albert Park
- President : Masato Kanda





Ques: Which two institutions signed an MoU to deepen financial inclusion by providing access to mutual fund products in rural and semi-urban areas?

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता (MoU) किया है?

- A) Department of Posts and BSE / डाक विभाग और बीएसई
- B) Department of Posts and NSE / डाक विभाग और एनएसई
- C) RBI and NSE / आरबीआई और एनएसई
- D) SEBI and India Post Payments Bank / सेबी और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- E) LIC and NSE / एलआईसी और एनएसई

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

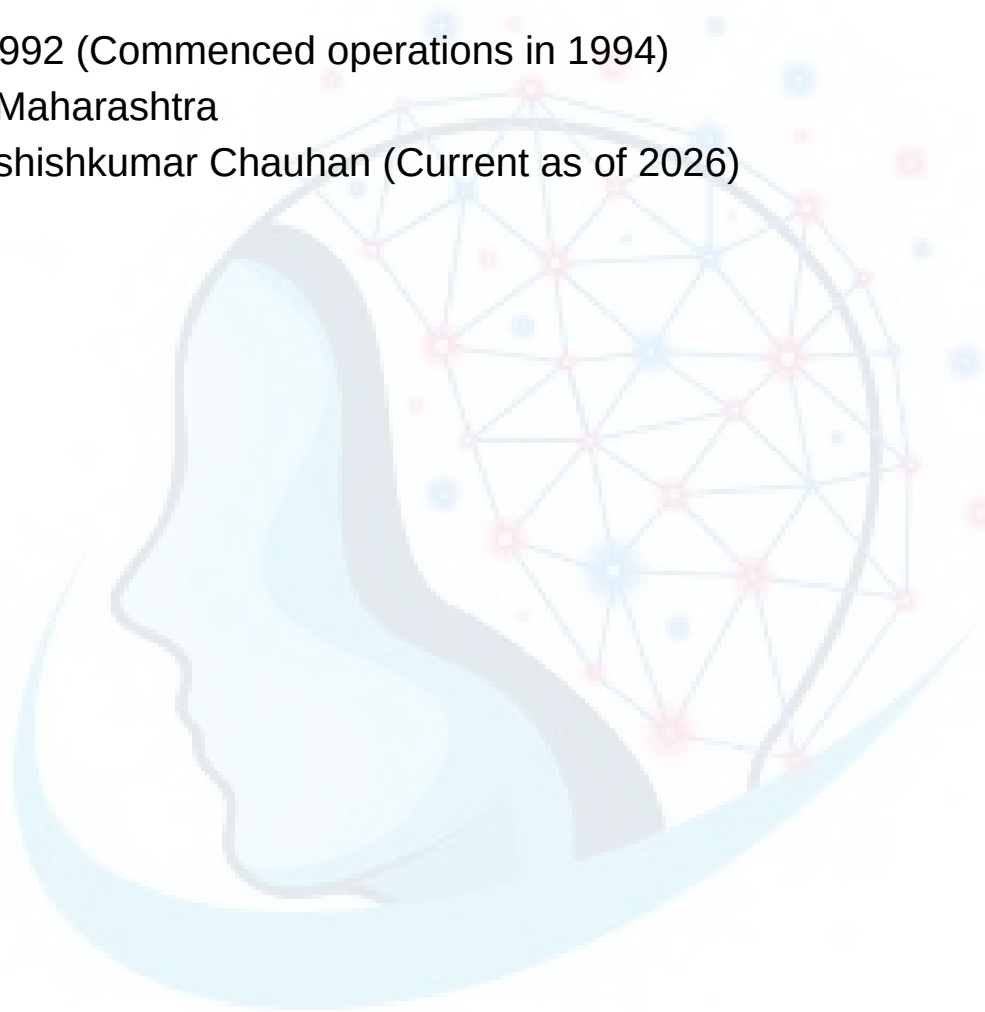
- The Department of Posts, Ministry of Communications, and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) signed a Memorandum of Understanding (MoU) to deepen financial inclusion.
- संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता (MoU) किया है।
- The initiative aims to provide access to mutual fund products in rural and semi-urban areas.
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- The partnership will leverage India Post's vast network of over 1.64 lakh post offices across the country.
- इस साझेदारी में इंडिया पोस्ट के 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।
- The objective is to promote transparency, investor literacy, and participation in capital market-linked products.
- इसका उद्देश्य पारदर्शिता, निवेशक साक्षरता और पूंजी बाजार से जुड़े उत्पादों में भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- The MoU is valid for three years and can be renewed by mutual consent of both parties.
- यह समझौता तीन वर्षों के लिए वैध है और आपसी सहमति से नवीनीकृत किया जा सकता है।





National Stock Exchange :

- Established : 1992 (Commenced operations in 1994)
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : Ashishkumar Chauhan (Current as of 2026)



EXAM
Genius





Ques: What was the value of the RBI Digital Payments Index (RBI-DPI) for September 2025?

सितंबर 2025 के लिए RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) का मान क्या था?

- A) 493.22
- B) 465.33
- C) 516.76
- D) 445.50
- E) 395.57

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has been publishing the RBI–Digital Payments Index (RBI-DPI) since 1 January 2021, with March 2018 as the base year (Index = 100).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 जनवरी 2021 से RBI–डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI-DPI) प्रकाशित कर रहा है, जिसका आधार वर्ष मार्च 2018 (इंडेक्स = 100) है।
- The RBI-DPI for September 2025 stood at 516.76, rising from 493.22 in March 2025.
- सितंबर 2025 में RBI-DPI 516.76 रहा, जो मार्च 2025 के 493.22 से अधिक है।
- This increase reflects significant growth in digital payment adoption and performance across India.
- यह वृद्धि देशभर में डिजिटल भुगतान के उपयोग और प्रदर्शन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को दर्शाती है।
- RBI-DPI measures the extent and depth of digitisation of payments over time.
- RBI-DPI समय के साथ डिजिटल भुगतान के विस्तार और गहराई को मापता है।
- The index is based on five broad parameters with assigned weights:
- यह इंडेक्स पाँच व्यापक मानकों और उनके निर्धारित भार पर आधारित है:
 - Payment Enablers – 25% / पेमेंट एनेबलर्स – 25%
 - Payment Infrastructure (Demand-side) – 10% / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (डिमांड साइड) – 10%
 - Payment Infrastructure (Supply-side) – 15% / पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सप्लाय साइड) – 15%
 - Payment Performance – 45% / पेमेंट परफॉर्मेंस – 45%
 - Consumer Centricity – 5% / कंज्यूमर सेंट्रिसिटी – 5%





Ques: What major regulatory change has the RBI introduced for Real Estate Investment Trusts (REITs)?

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) के लिए RBI ने कौन-सा महत्वपूर्ण नियामकीय बदलाव किया है?

- A) RBI has allowed foreign banks to directly own REITs / RBI ने विदेशी बैंकों को REITs का प्रत्यक्ष स्वामित्व लेने की अनुमति दी है
- B) RBI has permitted banks to lend directly to REITs with prudential safeguards / RBI ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को सीधे ऋण देने की अनुमति दी है
- C) RBI has removed listing requirements for REITs / RBI ने REITs के लिए लिस्टिंग आवश्यकताएँ समाप्त कर दी हैं
- D) RBI has merged REIT regulations with mutual fund norms / RBI ने REIT नियमों को म्यूचुअल फंड नियमों के साथ विलय कर दिया है
- E) RBI has restricted REIT funding only to NBFCs / RBI ने REIT फंडिंग को केवल NBFCs तक सीमित कर दिया है

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has allowed banks to lend directly to Real Estate Investment Trusts (REITs) with prudential safeguards.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सावधानीपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को REITs को सीधे ऋण देने की अनुमति दी है।
- This move aims to deepen credit access for the real estate sector and address long-term funding needs.
- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाना और दीर्घकालिक फंडिंग की समस्या को हल करना है।
- Earlier, banks were barred from lending to REITs, though lending to Infrastructure Investment Trusts (InvITs) was permitted.
- पहले बैंकों को REITs को ऋण देने की अनुमति नहीं थी, जबकि InvITs को ऋण देना अनुमत था।
- Existing InvIT lending norms will now be harmonised with safeguards applicable to REITs.
- मौजूदा InvIT ऋण मानदंडों को अब REIT सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जाएगा।





- Currently, India has five listed REITs:
 - Brookfield India Real Estate Trust
 - Embassy Office Parks REIT
 - Mindspace Business Parks REIT
 - Nexus Select Trust
 - Knowledge Realty Trust
- Earlier, REITs largely relied on short-term bonds (3–5 years) subscribed by mutual funds, NBFCs, and others, leading to long-term funding challenges.
- पहले REITs मुख्यतः अल्पकालिक बॉन्ड (3–5 वर्ष) पर निर्भर थे, जिससे दीर्घकालिक वित्तपोषण की समस्या उत्पन्न होती थी।

EXAM
Genius





Ques: Which organisations signed an agreement to enable UPI-based cross-border merchant payments between India and Malaysia?

भारत और मलेशिया के बीच UPI-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेट भुगतान सक्षम करने के लिए किन संगठनों ने समझौता किया?

- A) RBI and Bank Negara Malaysia / आरबीआई और बैंक नेगारा मलेशिया
- B) NPCI and Maybank / NPCI और मेबैंक
- C) NPCI International Payments Limited and Payments Network Malaysia (PayNet) / NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया (PayNet)
- D) SEBI and CIMB Bank / सेबी और सीआईएमबी बैंक
- E) SBI and RHB Bank / एसबीआई और आरएचबी बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments Limited (NIPL) has signed an agreement with Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet).
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया Sdn Bhd (PayNet) के साथ समझौता किया है।
- The agreement aims to enable QR-based cross-border merchant payments between India and Malaysia.
- यह समझौता भारत और मलेशिया के बीच QR-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मर्चेट भुगतान को सक्षम बनाने के लिए है।
- In the first phase, Indian travellers visiting Malaysia can scan DuitNow QR codes using Unified Payments Interface (UPI) enabled apps.
- पहले चरण में, मलेशिया जाने वाले भारतीय यात्री UPI-सक्षम ऐप्स से DuitNow QR को स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे।
- This will allow seamless merchant payments directly through UPI apps at DuitNow QR acceptance points.
- इससे DuitNow QR स्वीकार करने वाले व्यापारियों को सीधे UPI ऐप के माध्यम से सहज भुगतान संभव होगा।
- The move strengthens India's global digital payments footprint and promotes UPI as a cross-border payment solution.





Ques: Which two institutions signed an agreement to enable cashless Ayurveda treatment under general health insurance in India?

भारत में सामान्य स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस आयुर्वेद उपचार सक्षम करने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता किया?

- A) Ministry of AYUSH and IRDAI / आयुष मंत्रालय और IRDAI
- B) AIIMS New Delhi and General Insurance Council / एम्स नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- C) AIIA New Delhi and General Insurance Council / अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल
- D) NITI Aayog and LIC / नीति आयोग और एलआईसी
- E) National Health Authority and GIC / राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और GIC

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi and the General Insurance Council (GIC) signed an agreement to integrate Ayurveda into India's mainstream health insurance ecosystem.
- अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) ने आयुर्वेद को भारत की मुख्यधारा स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था में शामिल करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- The agreement enables cashless treatment facilities for eligible Ayurveda-based healthcare services across all 32 general insurance companies in India.
- इस समझौते के तहत देश की सभी 32 सामान्य बीमा कंपनियों में पात्र आयुर्वेद आधारित उपचारों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी।
- This move is a major step toward mainstreaming traditional medicine and improving patient access to alternative healthcare systems.
- यह पहल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में लाने और रोगियों की पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- AYUSH stands for Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy.
- AYUSH का अर्थ है — आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
- The Ministry of AYUSH was established on 9 November 2014 to promote education,





research, and development of India's traditional systems of medicine.

- आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- For the first time, the Government of India(GoI) has launched a dedicated Ayush Health Insurance Helpline '1800-11-0008' to support beneficiaries
- भारत सरकार ने पहली बार आयुष स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थियों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन '1800-11-0008' शुरू की है।

About All India Institute of Ayurveda :

- Established : 2015
- HQ : New Delhi
- Director : Pradeep Kumar Prajapati

About General Insurance Council :

- Established : 1957
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Tapan Kumar Singhel

EXAM
Genius





Ques: Which initiative was flagged off to promote AI awareness under the National AI Literacy programme “Yuva AI for All”?

राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम “युवा एआई फॉर ऑल” के तहत एआई जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई?

- A) DigiShakti / डिजीशक्ति
- B) Kaushal Rath / कौशल रथ
- C) AI Pathshala / एआई पाठशाला
- D) Bharat AI Bus / भारत एआई बस
- E) Tech Saksham / टेक सक्षम

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), in collaboration with All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), flagged off Kaushal Rath, an AI awareness initiative.
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (AISECT) के सहयोग से कौशल रथ नामक एआई जागरूकता पहल की शुरुआत की।
- Kaushal Rath is part of the National AI Literacy programme “Yuva AI for All.”
- कौशल रथ राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम “युवा एआई फॉर ऑल” के अंतर्गत शुरू किया गया है।
- The initiative aims to expand access to foundational AI education and bridge the digital divide, especially in semi-urban and underserved regions.
- इस पहल का उद्देश्य एआई की बुनियादी शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना और अर्ध-शहरी व वंचित क्षेत्रों में डिजिटल खाई को पाटना है।
- Kaushal Rath is a fully equipped mobile computer lab with internet-enabled systems, audio-visual tools, and structured training modules.
- कौशल रथ एक पूर्णतः सुसज्जित मोबाइल कंप्यूटर लैब है, जिसमें इंटरनेट-सक्षम सिस्टम, ऑडियो-विजुअल उपकरण और संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध हैं।
- It will travel to schools, colleges, ITIs, and community spaces to provide hands-on exposure to AI and Generative AI tools, supported by trained facilitators and contextualised Indian use-cases.
- यह स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और सामुदायिक स्थलों पर जाकर एआई और जनरेटिव एआई टूल्स का





Ques: What was the allocation made to the Department of Telecommunications (DoT) in the Union Budget 2026–27 to revive telecom infrastructure and strengthen BSNL?

केंद्रीय बजट 2026–27 में दूरसंचार अवसंरचना के पुनरुद्धार और BSNL को मजबूत करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) को कितनी राशि आवंटित की गई?

- A) ₹53,398.17 crore
- B) ₹73,990.94 crore
- C) ₹80,927.94 crore
- D) ₹81,005.24 cror
- E) ₹69,000 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Union Budget 2026–27 allocated ₹73,990.94 crore to the Department of Telecommunications (DoT), focusing on telecom infrastructure revival and strengthening Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL).
- केंद्रीय बजट 2026–27 में दूरसंचार अवसंरचना के पुनरुद्धार और BSNL को सशक्त बनाने के लिए दूरसंचार विभाग को ₹73,990.94 करोड़ आवंटित किए गए।
- The FY27 allocation is 8.65% lower than the FY26 Budget Estimate of ₹81,005.24 crore, but 38.56% higher than the FY26 Revised Estimate of ₹53,398.17 crore.
- वित्त वर्ष 2027 का यह आवंटन FY26 के बजट अनुमान से 8.65% कम, लेकिन संशोधित अनुमान से 38.56% अधिक है।
- The total net allocation for DoT in FY27 stands at ₹80,927.94 crore, including an additional ₹6,937 crore from the Universal Service Obligation Fund (USOF).
- FY27 में DoT का कुल शुद्ध आवंटन ₹80,927.94 करोड़ है, जिसमें USOF से ₹6,937 करोड़ शामिल हैं।
- Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia stated that the government is strengthening BSNL's financial and operational position, with ARPU rising from ₹90 to ₹99 and a target of ₹100.
- केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि सरकार BSNL की वित्तीय और परिचालन स्थिति को मजबूत कर रही है, जिसमें ARPU ₹90 से बढ़कर ₹99 हो गया है और लक्ष्य ₹100 है।





Ques: What was a key outcome of Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का एक प्रमुख परिणाम क्या था?

- A) Signing of 11 bilateral agreements across multiple sectors / कई क्षेत्रों में 11 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर
- B) Launch of a joint space mission / संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत
- C) Announcement of a free trade agreement / मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा
- D) Establishment of a common currency / साझा मुद्रा की स्थापना
- E) Suspension of palm oil imports / पाम ऑयल आयात का निलंबन

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- During Prime Minister Narendra Modi's visit to Kuala Lumpur, India and Malaysia signed 11 important agreements covering trade, technology, digital payments, and security.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान और सुरक्षा से जुड़े 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- Both sides agreed to expand bilateral trade beyond USD 18.6 billion and enhance investments, signalling a new phase in the India–Malaysia partnership.
- दोनों देशों ने 18.6 अरब डॉलर से अधिक व्यापार बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई, जो भारत–मलेशिया साझेदारी के नए चरण को दर्शाता है।
- Leaders appreciated cooperation between the Reserve Bank of India and Bank Negara Malaysia to promote invoicing and payments in Indian Rupee and Malaysian Ringgit.
- भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक नेगारा मलेशिया के बीच रुपये और रिंगgit में भुगतान व इनवॉइसिंग को बढ़ावा देने के सहयोग की सराहना की गई।
- Malaysia reaffirmed its commitment as a reliable supplier of sustainable palm oil to India.
- मलेशिया ने भारत को टिकाऊ पाम ऑयल का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।





Ques : Bodhan AI was launched to build which open-source digital public infrastructure?

बोधन AI किस ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया है?

- A) National AI Stack / राष्ट्रीय AI स्टैक
- B) India Digital Learning Grid / इंडिया डिजिटल लर्निंग ग्रिड
- C) Bharat EduAI Stack / भारत EduAI स्टैक
- D) EduTech India Network / एडुटेक इंडिया नेटवर्क
- E) National Education AI Portal / राष्ट्रीय शिक्षा AI पोर्टल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Dharmendra Pradhan, Union Education Minister, launched Bodhan AI at the Bharat Bodhan AI Conclave.
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बोधन AI कॉन्क्लेव में बोधन AI का शुभारंभ किया।
- Bodhan AI has been set up as a non-profit organisation under the Ministry of Education.
- बोधन AI को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- The primary objective of Bodhan AI is to develop an open-source Bharat EduAI Stack as digital public infrastructure (DPI).
- बोधन AI का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ओपन-सोर्स भारत EduAI स्टैक का निर्माण करना है।
- The Bharat EduAI Stack will integrate artificial intelligence across all levels of education, helping personalise learning, support teachers, and improve governance in education.
- भारत EduAI स्टैक शिक्षा के सभी स्तरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करेगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।
- The initiative aims to make education more equitable, affordable, and accessible, empowering students and assisting teachers with AI-driven tools.
- यह पहल शिक्षा को अधिक समान, किफायती और सुलभ बनाने के साथ-साथ छात्रों को सशक्त और शिक्षकों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।





Ques: Under the Companies Act, 2013, what does Corporate Social Responsibility (CSR) require eligible companies to do?

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत पात्र कंपनियों को क्या करना अनिवार्य है?

- A) Donate 5% of annual turnover to the government / वार्षिक टर्नओवर का 5% सरकार को दान करना
- B) Spend at least 2% of average net profits on social development projects / औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सामाजिक विकास परियोजनाओं पर खर्च करना
- C) Invest only in government-identified CSR projects / केवल सरकार द्वारा चिन्हित CSR परियोजनाओं में निवेश करना
- D) Contribute a fixed amount of ₹10 crore every year / हर वर्ष ₹10 करोड़ की निश्चित राशि देना
- E) Spend CSR funds only through government agencies / CSR राशि केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खर्च करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- In the last five financial years (2019–20 to 2023–24), Indian companies spent over ₹1,44,159 crore on Corporate Social Responsibility (CSR) activities.
- पिछले पांच वित्तीय वर्षों (2019–20 से 2023–24) में भारतीय कंपनियों ने ₹1,44,159 करोड़ से अधिक CSR गतिविधियों पर खर्च किए हैं।
- All CSR-related data (state-wise, project-wise, and company-wise) is publicly available on the MCA21 Portal.
- CSR से संबंधित सभी आंकड़े (राज्यवार, परियोजनावार और कंपनीवार) MCA21 पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

What is CSR? (2% Rule) | CSR क्या है? (2% नियम)

- As per Section 135(5) of the Companies Act, 2013, certain large companies are mandatorily required to contribute to social development.
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, बड़ी कंपनियों के लिए समाज कल्याण में योगदान देना अनिवार्य है।





- Eligible companies must spend at least 2% of their average net profits of the previous three financial years on CSR activities.
- पात्र कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना होता है।
- If a company's CSR obligation is ₹10 crore or more, it must appoint an independent agency for Impact Assessment.
- यदि किसी कंपनी की CSR देनदारी ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, तो उसे स्वतंत्र एजेंसी से इम्पैक्ट असेसमेंट कराना अनिवार्य है।
- Impact Assessment evaluates projects costing ₹1 crore or more and completed at least one year earlier to assess real outcomes.
- इम्पैक्ट असेसमेंट उन परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जिनकी लागत ₹1 करोड़ या उससे अधिक हो और जो कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों।
- The government does not allocate CSR funds; companies independently choose projects from Schedule VII areas like education, healthcare, poverty alleviation, and environmental sustainability.
- सरकार CSR फंड का आवंटन नहीं करती; कंपनियां अनुसूची VII में दिए गए क्षेत्रों—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण—में स्वयं परियोजनाएं चुनती हैं।
- The MCA21 portal is an e-governance initiative of the Ministry of Corporate Affairs providing a single window for company filings, registrations, and statutory compliance.
- MCA21 पोर्टल, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो कंपनी फाइलिंग, पंजीकरण और वैधानिक अनुपालन के लिए एकल मंच प्रदान करती है।

FY 2019-20 to FY 2023-24 are as follows:

- FY 2019-20 : 24,965.82
- FY 2020-21 : 26,210.95
- FY 2021-22 : 27,141.45
- FY 2022-23 : 30,932.08
- FY 2023-24 : 34,908.75





Ques: The Union Ministry of Home Affairs plans to compile a standard English medical dictionary under which policy?

गृह मंत्रालय किस नीति के तहत एक मानक अंग्रेज़ी मेडिकल शब्दकोश तैयार करने की योजना बना रहा है?

- A) National Health Policy 2017 / राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017
- B) National Education Policy 2020 / राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- C) National Digital Health Mission / राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- D) National Skill Development Policy / राष्ट्रीय कौशल विकास नीति
- E) Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan / राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Union Ministry of Home Affairs (MHA) plans to compile a standard English medical dictionary under the National Education Policy (NEP) 2020.
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत मानक अंग्रेज़ी मेडिकल शब्दकोश तैयार करेगा।
- The dictionary will be translated into 15 Indian languages to promote medical education in mother tongues.
- चिकित्सा शिक्षा को मातृभाषा में बढ़ावा देने के लिए इस शब्दकोश का 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।
- It will include at least 1,00,000 unique medical terms along with explanatory words.
- इसमें कम से कम 1,00,000 विशिष्ट चिकित्सा शब्द और उनके व्याख्यात्मक शब्द शामिल होंगे।
- The Department of Official Language (DoL) under MHA has invited bids from reputed international publishers to compile the dictionary titled "Medical Shabd Sindhu."
- MHA के अधीन आधिकारिक भाषा विभाग (DoL) ने "मेडिकल शब्द सिंधु" नामक शब्दकोश के संकलन हेतु प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से निविदाएँ आमंत्रित की हैं।
- In the first phase, translations will be done in Hindi, Telugu, Assamese, Gujarati, Kashmiri, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Bengali, Manipuri, Mizo and Konkani.
- पहले चरण में हिंदी, तेलुगु, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मिजो और कोंकणी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।





Ques: Which Indian space-tech startup signed a landmark agreement with Singapore's Defence Science and Technology Agency (DSTA) to protect satellites from space debris?

किस भारतीय स्पेस-टेक स्टार्टअप ने अंतरिक्ष मलबे से उपग्रहों की सुरक्षा के लिए सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी (DSTA) के साथ ऐतिहासिक समझौता किया?

- A) Skyroot Aerospace / स्काईरूट एयरोस्पेस
- B) Agnikul Cosmos / अग्निकुल कॉसमॉस
- C) Digantara Industries / दिगंतरा इंडस्ट्रीज़
- D) Pixxel / पिक्सेल
- E) Bellatrix Aerospace / बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Digantara Industries, a Bengaluru-based space-tech startup, signed a landmark agreement with Defence Science and Technology Agency (DSTA).
- बेंगलुरु स्थित स्पेस-टेक स्टार्टअप दिगंतरा इंडस्ट्रीज़ ने सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी (DSTA) के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- This partnership is historic as it marks the first formal collaboration between Singapore's defence establishment and an Indian space-tech company.
- यह साझेदारी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार है जब सिंगापुर के रक्षा तंत्र ने किसी भारतीय स्पेस-टेक कंपनी के साथ औपचारिक सहयोग किया है।
- The collaboration focuses on developing tools to protect national satellites from the growing threat of space debris and orbital congestion.
- इस सहयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे और कक्षीय भीड़ से राष्ट्रीय उपग्रहों की सुरक्षा के लिए उपकरण विकसित करना है।
- Digantara will provide services such as satellite tracking and conjunction screening to issue alerts when a satellite is at risk of collision with debris.
- दिगंतरा उपग्रह पथ ट्रैकिंग और कंजक्शन स्क्रीनिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करेगा, ताकि टकराव की आशंका होने पर चेतावनी जारी की जा सके।
- The partnership follows Digantara's successful \$50 million Series B funding round led by Reliance Business Ventures.





Ques: Why did the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) impose a ₹1 crore fine on Air India?

डीजीसीए ने एयर इंडिया पर ₹1 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया?

- A) For flight delay issues / उड़ान में देरी के कारण
- B) For safety violations by pilots / पायलटों द्वारा सुरक्षा उल्लंघन के कारण
- C) For operating an aircraft without valid airworthiness certification / वैध एयरवर्थिनेस प्रमाणन के बिना विमान संचालित करने के कारण
- D) For overcharging passengers / यात्रियों से अधिक शुल्क लेने के कारण
- E) For baggage mishandling / सामान प्रबंधन में त्रुटि के कारण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) imposed a ₹1 crore penalty on Air India.
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- The fine was imposed for operating an Airbus A320neo aircraft without valid airworthiness certification.
- यह जुर्माना वैध एयरवर्थिनेस प्रमाणन के बिना एयरबस A320 नियो विमान संचालित करने के कारण लगाया गया।
- The aircraft was reportedly operated on at least eight routes last year without proper certification.
- बताया गया है कि पिछले वर्ष इस विमान को कम से कम आठ मार्गों पर बिना उचित प्रमाणन के संचालित किया गया।
- Air India stated that the incident was voluntarily reported in 2025 and that all identified gaps have been addressed.
- एयर इंडिया के अनुसार, इस घटना की सूचना 2025 में स्वेच्छा से दी गई थी और सभी कमियों को दूर कर लिया गया है।
- DGCA is the regulatory authority responsible for civil aviation safety and compliance in India.
- DGCA भारत में नागरिक उड्डयन की सुरक्षा और अनुपालन के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरण है।





Ques: What is the key change introduced by the Ex-servicemen Amendment Rules, 2026?

पूर्व सैनिक संशोधन नियम, 2026 के तहत प्रमुख बदलाव क्या किया गया है?

- A) Introduction of new pension benefits for ex-servicemen / पूर्व सैनिकों के लिए नई पेंशन सुविधाएँ शुरू की गईं
- B) Inclusion of paramilitary forces under the ex-servicemen category / अर्धसैनिक बलों को पूर्व सैनिक श्रेणी में शामिल किया गया
- C) Official inclusion of the Military Nursing Service (MNS) under the definition of ex-servicemen / मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) को आधिकारिक रूप से पूर्व सैनिक की परिभाषा में शामिल किया गया
- D) Increase in reservation percentage for Group 'A' services / ग्रुप 'A' सेवाओं में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया गया
- E) Abolition of age relaxation for ex-servicemen / पूर्व सैनिकों के लिए आयु छूट समाप्त की गई

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government has notified the Ex-servicemen Amendment Rules, 2026 under Constitution of India – Article 309, effective from 9 February 2026.
- सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत पूर्व सैनिक संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 9 फरवरी 2026 से प्रभावी हैं।

Core Change | मुख्य बदलाव :

- Rule 2(c)(i) has been amended to explicitly include the Military Nursing Service (MNS) within the definition of “Ex-servicemen.”
- नियम 2(c)(i) में संशोधन कर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) को औपचारिक रूप से “पूर्व सैनिक” की परिभाषा में शामिल किया गया है।
- MNS is now listed alongside the Regular Army, Navy, and Air Force.
- अब MNS को नियमित थल सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ सूचीबद्ध किया गया है।
- The provision applies to all personnel, in any rank, whether combatants or non-combatants.





- यह प्रावधान सभी रैंकों में सेवा देने वाले कर्मियों पर लागू होगा, चाहे वे कॉम्बैटेंट हों या नॉन-कॉम्बैटेंट।

Why This Matters | यह क्यों महत्वपूर्ण है :

- Earlier, there was ambiguity regarding the eligibility of MNS officers (who are commissioned officers) for ex-servicemen benefits.
- पहले यह स्पष्ट नहीं था कि MNS अधिकारी (जो कमीशंड ऑफिसर होते हैं) पूर्व सैनिक लाभों के पात्र हैं या नहीं।
- The amendment removes this ambiguity and officially recognizes MNS personnel as veterans.
- यह संशोधन इस भ्रम को समाप्त करता है और MNS कर्मियों को आधिकारिक रूप से पूर्व सैनिक का दर्जा देता है।
- This strengthens their rehabilitation prospects and second-career opportunities in the civil sector.
- इससे नागरिक क्षेत्र में उनके पुनर्वास और द्वितीय करियर के अवसर मजबूत होते हैं।

Benefits Available to MNS Personnel | MNS कर्मियों को मिलने वाले लाभ :

- 10% reservation in Group 'C' Central Government posts.
- केंद्रीय सरकार की ग्रुप 'C' नौकरियों में 10% आरक्षण।
- 20% reservation in Group 'D' Central Government posts.
- केंद्रीय सरकार की ग्रुप 'D' नौकरियों में 20% आरक्षण।
- Age relaxation: Total years of military service plus 3 years can be deducted from actual age for civil job eligibility.
- आयु छूट: नागरिक नौकरियों की पात्रता के लिए कुल सैन्य सेवा अवधि + 3 वर्ष वास्तविक आयु से घटाए जा सकते हैं।
- Rule 2(c)(i) remains the defining clause for who qualifies as an ex-serviceman for re-employment benefits, now clearly including MNS.
- नियम 2(c)(i) पूर्व सैनिक की पात्रता तय करने वाला आधिकारिक प्रावधान है, जिसमें अब MNS को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।





Ques: As per the latest guidelines issued by the Union Home Ministry, which statement regarding Vande Mataram is correct?

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार वंदे मातरम् के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

- A) Only the first two stanzas of Vande Mataram will be sung / केवल वंदे मातरम् के पहले दो पद गाए जाएंगे
- B) Vande Mataram will be sung after the National Anthem / वंदे मातरम् राष्ट्रीय गान के बाद गाया जाएगा
- C) All six stanzas of Vande Mataram must be sung for 3 minutes 10 seconds and played before the National Anthem / वंदे मातरम् के सभी 6 पद 3 मिनट 10 सेकंड तक गाए जाएंगे और इसे राष्ट्रीय गान से पहले बजाया जाएगा
- D) Singing Vande Mataram is compulsory in cinema halls / सिनेमा हॉल में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य है
- E) The guidelines have no relation to the anniversary of the song / इन दिशानिर्देशों का गीत की वर्षगांठ से कोई संबंध नहीं है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Union Home Ministry (Ministry of Home Affairs) has issued fresh guidelines mandating that all six stanzas of Vande Mataram be sung at official functions and educational institutions.
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने आधिकारिक कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम् के सभी 6 पद गाने को अनिवार्य किया है।
- Vande Mataram was originally composed by Bankim Chandra Chatterjee, and the decision coincides with the 150th anniversary of the song's creation.
- वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, और यह निर्णय इसके 150वें वर्ष के अवसर पर लिया गया है।
- The total duration for singing or playing the national song has been fixed at 3 minutes and 10 seconds; earlier, only the first two stanzas were commonly used.
- राष्ट्रीय गीत को गाने/बजाने की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है; पहले सामान्यतः केवल दो पद ही उपयोग में थे।





- All persons present must stand in attention when the song is played; however, this rule is not compulsory in cinema halls if the song appears as part of a film or newsreel.
- गीत के दौरान सभी उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा, लेकिन यदि यह किसी फ़िल्म या न्यूज़रील का हिस्सा हो तो सिनेमा हॉल में यह अनिवार्य नहीं है।
- The order clearly states that when both the national song and the national anthem are played, Vande Mataram will be played first, including the four stanzas removed in 1937.
- आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों होने पर पहले वंदे मातरम् बजाया जाएगा, जिसमें 1937 में हटाए गए चार पद भी शामिल होंगे।

EXAM
Genius





Ques: Which organisation signed an agreement with the Technology Development Board to develop indigenous high-pressure hydrogen storage systems?

उन्नत उच्च-दाब हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने किस कंपनी के साथ समझौता किया?

- A) Tata Advanced Systems Limited / टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड
- B) Larsen & Toubro Limited / लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
- C) Reliance New Energy Limited / रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड
- D) Ashok Leyland Limited / अशोक लेलैंड लिमिटेड
- E) Gudlyf Mobility Private Limited / गुडलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Technology Development Board, under the Department of Science and Technology, signed an agreement with Gudlyf Mobility Private Limited, Tamil Nadu, to provide financial assistance for the development and commercialisation of indigenous high-pressure hydrogen storage systems based on advanced composite technologies.
- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत गुडलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (तमिलनाडु) के साथ उन्नत कम्पोज़िट तकनीक पर आधारित स्वदेशी उच्च-दाब हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के विकास एवं व्यावसायीकरण हेतु वित्तीय सहायता के लिए समझौता किया।
- The technology caters to both commercial and strategic sectors.
- यह तकनीक वाणिज्यिक और रणनीतिक—दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- Hydrogen Storage: Solutions for mobile applications (vehicles) and stationary energy systems.
- हाइड्रोजन भंडारण: मोबाइल अनुप्रयोगों (वाहनों) तथा स्थिर ऊर्जा प्रणालियों के लिए समाधान।
- UAVs (Drones): Lightweight fuel storage solutions for Unmanned Aerial Vehicles.
- यूएवी (ड्रोन): मानवरहित हवाई वाहनों के लिए हल्के ईंधन भंडारण समाधान।
- CNG & CBG: Advanced storage solutions for Compressed Natural Gas (CNG) and Compressed BioGas (CBG).
- सीएनजी व सीबीजी: संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) और संपीड़ित बायोगैस (CBG) के लिए उन्नत भंडारण समाधान।





Ques: The Defence Acquisition Council (DAC) recently approved procurement of 114 Rafale jets for which force?

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने हाल ही में 114 राफेल जेट किस बल के लिए स्वीकृत किए?

- A) Indian Navy / भारतीय नौसेना
- B) Indian Army / भारतीय सेना
- C) Indian Air Force / भारतीय वायु सेना
- D) Indian Coast Guard / भारतीय तटरक्षक बल
- E) Border Security Force / सीमा सुरक्षा बल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Rajnath Singh, granted Acceptance of Necessity (AoN) for capital acquisition proposals worth about ₹3.6 lakh crore.
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने लगभग ₹3.6 लाख करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी।
- The approval includes procurement of 114 Multi-Role Fighter Aircraft (MRFA) — Rafale jets — for the Indian Air Force (IAF).
- इस मंजूरी में भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 114 राफेल मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद शामिल है।
- Most of the Rafale jets are expected to be manufactured in India, boosting domestic defence production under Make in India.
- अधिकांश राफेल जेट भारत में निर्मित होने की संभावना है, जिससे मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- The Indian Navy has been granted AoN for six additional P-8I long-range maritime reconnaissance aircraft from the United States.
- भारतीय नौसेना को अमेरिका से 6 अतिरिक्त P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है।
- The P-8I aircraft will enhance anti-submarine warfare, maritime surveillance, and strike capabilities.
- P-8I विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी और स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करेंगे।





Ques: India and Vietnam recently deepened cooperation in which sector to promote sericulture, technical textiles, and R&D, aiming to create a new 'Silk Corridor' in Asia?

भारत और वियतनाम ने हाल ही में एशिया में एक नया 'सिल्क कॉरिडोर' विकसित करने के उद्देश्य से किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है?

- A) Information Technology / सूचना प्रौद्योगिकी
- B) Defence Manufacturing / रक्षा विनिर्माण
- C) Pharmaceuticals / फार्मास्यूटिकल्स
- D) Agriculture and Food Processing / कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
- E) Textile and Sericulture / वस्त्र और रेशम उत्पादन

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- India and Vietnam deepened their textile ties through a 5-day strategic collaboration, focusing on strengthening sericulture, technical textiles, and research & development (R&D).
- भारत और वियतनाम ने 5-दिवसीय रणनीतिक सहयोग के माध्यम से रेशम उत्पादन, तकनीकी वस्त्र और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग को मजबूत किया।
- The collaboration aligns Central Silk Board with major Vietnamese textile industry players to drive innovation and growth.
- इस सहयोग के तहत सेंट्रल सिल्क बोर्ड को वियतनाम के प्रमुख वस्त्र उद्योग समूहों के साथ जोड़ा गया है।
- Sericulture focus: Improving silk farming practices and mulberry cultivation.
- रेशम उत्पादन पर फोकस: रेशम की खेती और शहतूत (मलबरी) की खेती में सुधार।
- Technical textiles: Development of specialised, high-tech fabrics for industrial and advanced applications.
- तकनीकी वस्त्र: औद्योगिक उपयोग के लिए उन्नत और उच्च-तकनीकी कपड़ों का विकास।
- R&D collaboration: Joint research and technology transfer, particularly in automatic silk reeling technologies.
- R&D सहयोग: विशेष रूप से स्वचालित रीलिंग तकनीक में संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- This partnership aims to establish a modern 'Silk Corridor' in Asia, boosting textile trade, innovation, and regional value chains.





- यह साझेदारी एशिया में एक आधुनिक 'सिल्क कॉरिडोर' स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

About the Silk Corridor in Asia | एशिया में सिल्क कॉरिडोर के बारे में

- The Silk Corridor refers to the historic Silk Roads, a vast network of land and sea trade routes operating from the 2nd century BCE to the 15th century CE, linking East and West.
- सिल्क कॉरिडोर ऐतिहासिक सिल्क रोड को दर्शाता है, जो दूसरी शताब्दी ईसा-पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले स्थल एवं समुद्री व्यापार मार्ग थे।
- The land routes extended over 6,400 km, crossing difficult terrains like the Gobi Desert and Pamir Mountains.
- स्थलीय मार्ग 6,400 किमी से अधिक लंबे थे और गोबी रेगिस्तान तथा पामीर पर्वत जैसे दुर्गम क्षेत्रों से गुजरते थे।
- A key section is the Chang'an–Tianshan Corridor, a 5,000 km UNESCO-listed route, connecting Central China to the Zhetysu region of Central Asia via Kazakhstan and Kyrgyzstan.
- इसका प्रमुख भाग चांगआन–तियानशान कॉरिडोर है, जो UNESCO विश्व धरोहर में शामिल है।
- Major trading cities included Xi'an, Samarkand, Bukhara, Merv, and Kashgar, which served as hubs for trade and cultural exchange.
- ये शहर व्यापार, विश्राम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के प्रमुख केंद्र थे।

EXAM
Genius





Ques: Which aircraft platform is associated with Apogee Aerospace's ₹3,500 crore amphibian aircraft deal with Australia?

एपोजी एयरोस्पेस के ₹3,500 करोड़ के उभयचर विमान सौदे में कौन-सा विमान प्लेटफ़ॉर्म शामिल है?

- A) Albatross 2.0 / एल्बार्ट्रोस 2.0
- B) Twin Otter / ट्विन ऑटर
- C) Dornier 228 / डोर्नियर 228
- D) C-295 / सी-295
- E) Be-200 / बी-200

Answer: Option A

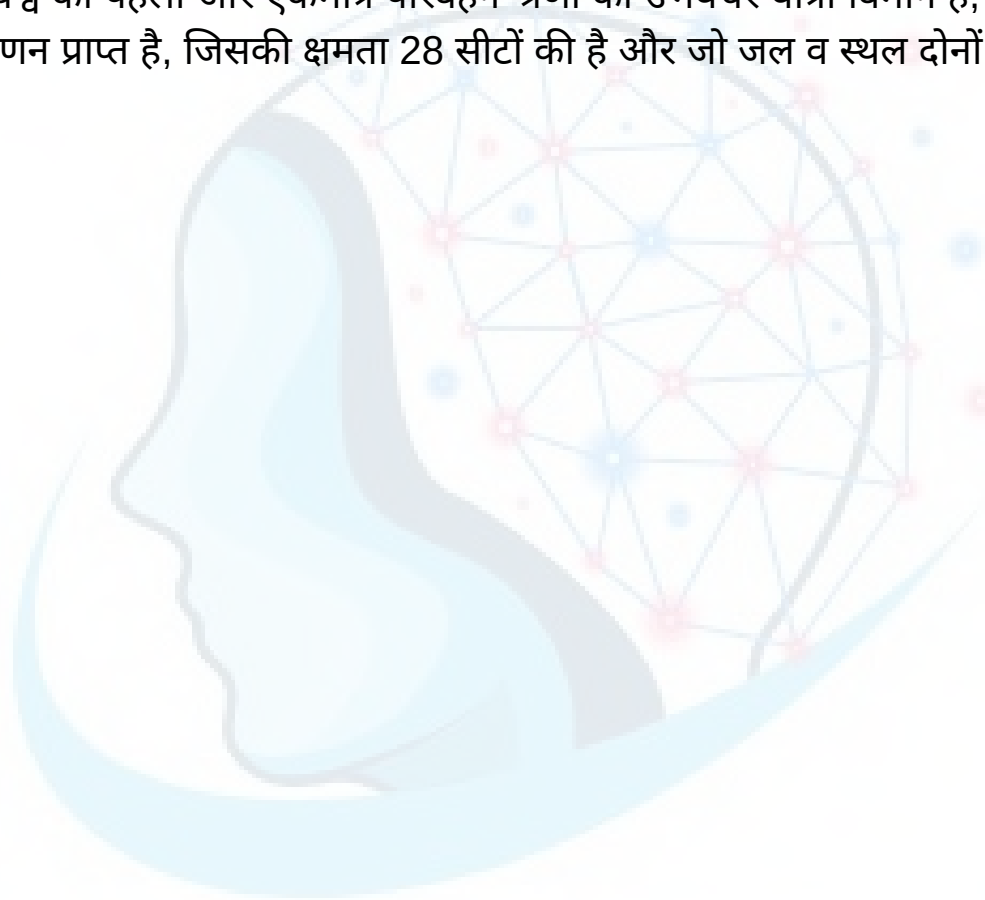
Explanation / व्याख्या:

- Apogee Aerospace Private Limited placed an order worth ₹3,500 crore for 15 amphibian aircraft (seaplanes) with Amphibian Aerospace Industries (AAI).
- एपोजी एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की एम्फीबियन एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ 15 उभयचर विमानों के लिए ₹3,500 करोड़ का ऑर्डर दिया।
- Apogee Aerospace has become the authorized partner of AAI across the Indian subcontinent, anchored by the Albatross 2.0 platform.
- इस समझौते के तहत एपोजी एयरोस्पेस भारतीय उपमहाद्वीप में AAI का अधिकृत भागीदार बन गया है, जो Albatross 2.0 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है।
- The partnership operates under the "Restricted Category", handling all Defence and Government aviation requirements.
- यह साझेदारी "रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी" के अंतर्गत रक्षा और सरकारी विमानन आवश्यकताओं को संभालेगी।
- Apogee Aerospace will invest ₹500 crore in India to support manufacturing and ecosystem development.
- एपोजी एयरोस्पेस भारत में निर्माण व इकोसिस्टम विकास के लिए ₹500 करोड़ का निवेश करेगा।
- About Albatross 2.0 Aircraft:
 - World's first and only transport-category amphibious aircraft in the Registered Passenger Transport segment
 - Certified by both the Federal Aviation Administration (FAA) and the European Union Aviation Safety Agency (EASA)





- Maximum capacity: 28 seats
- Capable of operating on both water and land
- Albatross 2.0 विश्व का पहला और एकमात्र परिवहन-श्रेणी का उभयचर यात्री विमान है, जिसे FAA और EASA दोनों से प्रमाणन प्राप्त है, जिसकी क्षमता 28 सीटों की है और जो जल व स्थल दोनों पर संचालन कर सकता है।



EXAM
Genius





Ques: Which state was the largest wool-producing state in India in FY24?

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन-सा था?

- A) Jammu & Kashmir / जम्मू-कश्मीर
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Rajasthan / राजस्थान
- D) Telangana / तेलंगाना
- E) Gujarat / गुजरात

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Rajasthan emerged as India's largest wool-producing state in FY24.
- FY24 में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य रहा।
- Rajasthan produced 16,013.50 thousand kg of wool, accounting for 47.53% of the country's total wool output.
- राजस्थान ने 16,013.50 हजार किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का 47.53% है।
- Jammu & Kashmir ranked second with 7,770 thousand kg, followed by Karnataka with 6,472 thousand kg of wool production.
- जम्मू-कश्मीर 7,770 हजार किलोग्राम के साथ दूसरे और कर्नाटक 6,472 हजार किलोग्राम के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- Telangana and Gujarat secured the fourth and fifth positions respectively.
- तेलंगाना और गुजरात क्रमशः चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे।
- India has the second-largest sheep population in the world, with around 77.4 million sheep.
- भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी है, जो लगभग 77.4 मिलियन है।
- Globally, India ranks 9th in wool production.
- वैश्विक स्तर पर ऊन उत्पादन में भारत का 9वाँ स्थान है।





Ques: Which country has been designated as the Country of the Year at BIOFACH 2026, the world's leading trade fair for organic products?

BIOFACH 2026, जो जैविक उत्पादों का विश्व का प्रमुख व्यापार मेला है, में कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को घोषित किया गया है?

- A) Germany / जर्मनी
- B) France / फ्रांस
- C) Australia / ऑस्ट्रेलिया
- D) Brazil / ब्राज़ील
- E) India / भारत

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- India has been designated as the Country of the Year at BIOFACH 2026, marking a major global recognition in sustainable and organic agriculture.
- भारत को BIOFACH 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जो टिकाऊ और जैविक कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि है।
- BIOFACH 2026 will be held from 10 to 13 February 2026 at Nuremberg, Germany.
- BIOFACH 2026 का आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में किया जाएगा।
- India's participation is being organised by the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) under the Ministry of Commerce and Industry.
- BIOFACH 2026 में भारत की भागीदारी का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत APEDA द्वारा किया जा रहा है।
- This recognition marks India's return to the global organic farming spotlight after 14 years.
- यह सम्मान 14 वर्षों बाद वैश्विक जैविक कृषि मंच पर भारत की सशक्त वापसी को दर्शाता है।
- The India Country Pavilion at BIOFACH 2026 will span 1,074 square metres, making it one of the largest national pavilions at the event.
- BIOFACH 2026 में भारत का कंट्री पवेलियन 1,074 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो इस आयोजन के सबसे बड़े राष्ट्रीय पवेलियनों में से एक होगा।
- Showcase of 5 GI-tagged rice varieties: Indrayani Rice (Maharashtra), Navara Rice





Ques: What is India's rank in the 2026 Henley Passport Index?

2026 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?

- A) 65th
- B) 70th
- C) 75th
- D) 80th
- E) 85th

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's passport jumped 10 places to rank 75th in the 2026 Henley Passport Index.
- भारत का पासपोर्ट 10 स्थान की छलांग लगाकर 2026 में 75वें स्थान पर पहुंच गया।
- Indian passport holders now enjoy easier or visa-free access to 56 countries worldwide.
- भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब दुनिया के 56 देशों में आसान या वीजा-मुक्त प्रवेश की सुविधा प्राप्त है।
- The improvement reflects enhanced global mobility and strengthening diplomatic relations.
- यह सुधार वैश्विक गतिशीलता में वृद्धि और मजबूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है।
- The Henley Passport Index ranks passports based on the number of destinations accessible without a prior visa.
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर करता है कि धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के जा सकते हैं

EXAM
Genius





Ques: Where will the National Large Optical–Near Infrared Telescope (NLOT) be built?

नेशनल लार्ज ऑप्टिकल–नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT) कहाँ बनाया जाएगा?

- A) Merak near Pangong Tso / पैंगोंग त्सो के पास मेराक
- B) Hanle, Ladakh / हनले, लद्दाख
- C) Kodaikanal, Tamil Nadu / कोडाइकनाल, तमिलनाडु
- D) Udaipur, Rajasthan / उदयपुर, राजस्थान
- E) Leh, Ladakh / लेह, लद्दाख

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- In the Union Budget, the Government of India approved the establishment of two new telescopes in Ladakh, along with the upgradation of an existing one.
- केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने लद्दाख में दो नए टेलीस्कोप स्थापित करने तथा एक मौजूदा टेलीस्कोप के उन्नयन को मंजूरी दी है।
- The National Large Solar Telescope (NLST) will be a 2-metre aperture solar telescope set up at Merak near Pangong Tso lake.
- नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप (NLST) 2-मीटर एपर्चर वाला सौर टेलीस्कोप होगा, जिसे पैंगोंग त्सो झील के पास मेराक में स्थापित किया जाएगा।
- Once operational in about 5–6 years, NLST will become India's third ground-based solar observatory.
- लगभग 5–6 वर्षों में संचालन शुरू होने के बाद, NLST भारत की तीसरी ग्राउंड-बेस्ड सौर वेधशाला बनेगा।
- At present, India has two operational solar observatories:
 - Kodaikanal Solar Observatory (Tamil Nadu, established in 1899)
 - Udaipur Solar Observatory (Rajasthan, established in 1975)
- वर्तमान में भारत में दो सौर वेधशालाएँ कार्यरत हैं: कोडाइकनाल (1899) और उदयपुर (1975)।
- The National Large Optical–Near Infrared Telescope (NLOT) will be a 13.7-metre segmented-mirror optical–near infrared telescope.
- नेशनल लार्ज ऑप्टिकल–नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप (NLOT) 13.7-मीटर सेगमेंटेड मिरर वाला ऑप्टिकल–नियर इन्फ्रारेड टेलीस्कोप होगा।





Ques: On which date is World Radio Day observed annually?

विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) 1 January
- B) 13 February
- C) 15 March
- D) 21 June
- E) 10 December

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- World Radio Day is observed every year on 13 February to commemorate the establishment of United Nations Radio in 1946.
- विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में है।
- The theme of World Radio Day 2026 is “Radio and Artificial Intelligence: AI is a tool, not a voice.”
- विश्व रेडियो दिवस 2026 का विषय है – “रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं।”
- India’s first Community Radio Station was inaugurated on 1 February 2004 by Lal Krishna Advani.
- भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 1 फरवरी 2004 को श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा उद्घाटित किया गया था।
- Ram Singh Bouddh from Amroha, Uttar Pradesh, popularly known as the “Radio Man of India,” was recognised by Guinness World Records in 2025.
- उत्तर प्रदेश के अमरोहा के राम सिंह बौद्ध, जिन्हें “रेडियो मैन ऑफ इंडिया” कहा जाता है, को 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई।
- He owns the world’s largest collection of 1,257 radios.
- उनके पास 1,257 रेडियो का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।





Ques: As per the February 2026 draft guidelines, what Credit-Deposit (CD) ratio target has been set for rural and semi-urban branches under the Lead Bank Scheme (LBS)?

फरवरी 2026 के मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार लीड बैंक स्कीम (LBS) के तहत ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए CD रेशियो लक्ष्य क्या है?

- A) 40%
- B) 50%
- C) 60%
- D) 70%
- E) 80%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

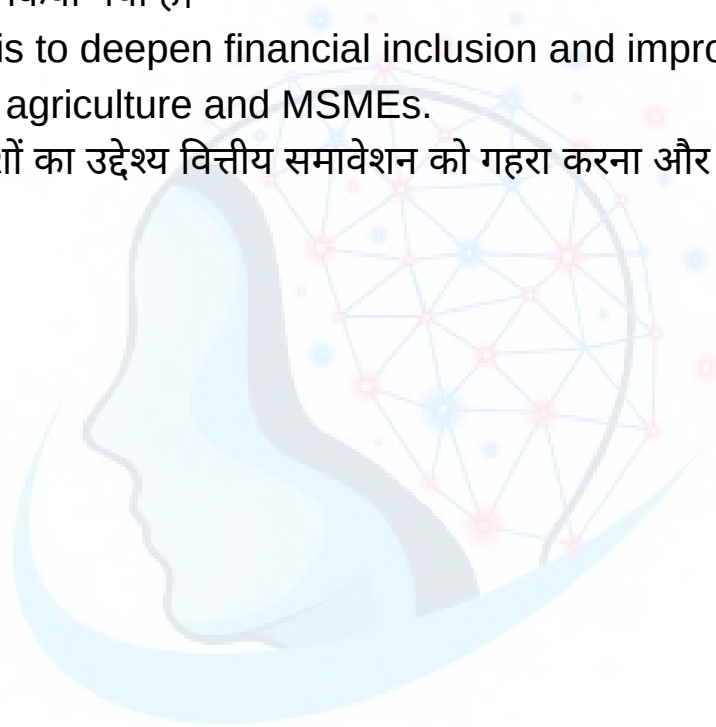
- Reserve Bank of India (RBI) issued draft guidelines in February 2026 to streamline the Lead Bank Scheme (LBS) with a focus on improving credit flow in rural and semi-urban areas.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2026 में लीड बैंक स्कीम (LBS) को सुव्यवस्थित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए।
- As per the draft, rural and semi-urban branches must achieve a minimum CD ratio of 60%.
- मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को न्यूनतम 60% CD रेशियो हासिल करना होगा।
- The Credit-Deposit (CD) ratio indicates how much of the deposits mobilised by banks are converted into loans; a higher ratio reflects better local credit deployment.
- क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो यह दर्शाता है कि बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशि का कितना हिस्सा ऋण के रूप में दिया गया है; अधिक CD रेशियो बेहतर स्थानीय ऋण प्रवाह को दर्शाता है।
- District Consultative Committees (DCCs) will closely monitor districts where the CD ratio lies between 40% and 60% to improve performance.
- जिन जिलों में CD रेशियो 40% से 60% के बीच है, उनकी निगरानी जिला परामर्श समिति (DCC) द्वारा की जाएगी।
- Districts with a CD ratio below 20% will be classified as 'Special Category' districts,





indicating very low credit absorption.

- 20% से कम CD रेशियो वाले जिलों को 'विशेष श्रेणी' में रखा जाएगा।
- The guidelines also mandate that at least 25% of total banking outlets be opened in Tier-V and Tier-VI Under-Served Rural Centres (URCs) to strengthen financial inclusion.
- इसके अलावा टियर-V और टियर-VI अंडर-सर्व्ड रूरल सेंटर्स (URCs) में कम-से-कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने का प्रावधान किया गया है।
- Overall, the objective is to deepen financial inclusion and improve credit flow to priority sectors such as agriculture and MSMEs.
- समग्र रूप से, इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को गहरा करना और प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाना है।



EXAM
Genius





Ques: Who has received a three-year extension as the Managing Director & CEO of AU Small Finance Bank?

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे तीन वर्ष का विस्तार मिला है?

- A) Uday Kotak / उदय कोटक
- B) Sanjay Agarwal / संजय अग्रवाल
- C) Hasmukh Adhia / हसमुख अधिया
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Chandra Shekhar Ghosh / चंद्रशेखर घोष

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- AU Small Finance Bank announced that Reserve Bank of India (RBI) has approved the reappointment of Sanjay Agarwal as its Managing Director & Chief Executive Officer.
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संजय अग्रवाल की एमडी एवं सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- The extension is for a further period of three years, effective from April 19.
- यह विस्तार 19 अप्रैल से प्रभावी तीन वर्षों के लिए है।
- The reappointment had earlier been approved by the Board (October 17, 2025) and shareholders (December 26, 2025), subject to RBI confirmation.
- पुनर्नियुक्ति को पहले बोर्ड (17 अक्टूबर 2025) और शेयरधारकों (26 दिसंबर 2025) से मंजूरी मिल चुकी थी, जो RBI की पुष्टि के अधीन थी।
- Recently, AU Small Finance Bank also received in-principle approval from RBI to transition into a universal bank.
- हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी भी प्राप्त हुई है।





Ques: As per the revised norms, what is the maximum aggregate exposure banks can extend towards acquisition (M&A) financing?

संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक अधिग्रहण (M&A) फाइनेंसिंग के लिए अधिकतम कितना कुल एक्सपोजर दे सकते हैं?

- A) 10% of capital base / पूंजी आधार का 10%
- B) 15% of capital base / पूंजी आधार का 15%
- C) 20% of capital base / पूंजी आधार का 20%
- D) 25% of capital base / पूंजी आधार का 25%
- E) 30% of capital base / पूंजी आधार का 30%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has allowed banks to extend aggregate exposure up to 20% of their eligible capital base for acquisition (M&A) financing, increased from the earlier proposed 10%.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अधिग्रहण फाइनेंसिंग के लिए बैंकों को अपनी पात्र पूंजी आधार का 20% तक कुल एक्सपोजर देने की अनुमति दी है, जो पहले प्रस्तावित 10% था।
- Banks are now permitted to finance acquisitions of unlisted companies, subject to prescribed conditions.
- अब बैंकों को कुछ शर्तों के तहत अनलिस्टेड कंपनियों के अधिग्रहण के लिए फाइनेंसिंग की अनुमति दी गई है।
- The target unlisted company must have a minimum net worth of ₹500 crore, be profit-making for the last three years, and possess an investment-grade credit rating (BBB– or above).
- लक्षित अनलिस्टेड कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ ₹500 करोड़, पिछले तीन वर्षों से लाभ में होना, और निवेश-ग्रेड रेटिंग (BBB– या उससे ऊपर) होना अनिवार्य है।
- The permissible portion of bank financing has been increased to 75% of the acquisition value from the earlier proposed 70%.
- बैंक फाइनेंसिंग की अनुमत सीमा को पहले प्रस्तावित 70% से बढ़ाकर अधिग्रहण मूल्य का 75% कर दिया गया है।
- The remaining 25% of the acquisition cost must be funded by the acquirer through internal accruals or fresh equity issuance.





Ques: Who has been appointed as the Chairman of GIFT City by the Government of Gujarat?

गुजरात सरकार द्वारा गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Hasmukh Adhia / हसमुख अधिया
- B) Uday Kotak / उदय कोटक
- C) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- D) Rajeev Jain / राजीव जैन
- E) Ajay Seth / अजय सेठ

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Government of Gujarat appointed Uday Kotak as the Chairman of Gujarat International Finance Tec-City Company Ltd (GIFT City).
- गुजरात सरकार ने उदय कोटक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड (GIFT City) का चेयरमैन नियुक्त किया।
- Uday Kotak is the Founder and Director of Kotak Mahindra Bank.
- वे कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक एवं निदेशक हैं।
- He replaced Hasmukh Adhia in this position.
- उन्होंने इस पद पर हसमुख अधिया का स्थान लिया।
- As per the resolution of the Urban Development Department of Gujarat, he will assume charge with immediate effect.
- गुजरात के शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, वे तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करेंगे।





Ques: Which bank was fined ₹63.60 lakh by the Reserve Bank of India (RBI) for non-compliance with regulatory norms?

नियामकीय मानदंडों का पालन न करने पर RBI द्वारा ₹63.60 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया?

- A) Bank of Maharashtra / बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- B) DCB Bank / डीसीबी बैंक
- C) CSB Bank / सीएसबी बैंक
- D) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक
- E) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India imposed monetary penalties on three banks for non-compliance with its regulatory guidelines.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर तीन बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- A fine of ₹32.50 lakh was imposed on Bank of Maharashtra.
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ₹32.50 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- A penalty of ₹29.60 lakh was imposed on DCB Bank.
- डीसीबी बैंक पर ₹29.60 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- The highest penalty of ₹63.60 lakh was imposed on CSB Bank.
- सबसे अधिक ₹63.60 लाख का जुर्माना सीएसबी बैंक पर लगाया गया।
- The penalties were related to non-compliance with RBI's regulatory norms.
- ये सभी जुर्माने RBI के नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित थे।





Ques: With reference to the Bird Atlas of Goa, consider the following statements:

गोवा के बर्ड एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. It was released during the 9th Bird Festival of Goa held at Valpoi.

इसे वालपोई में आयोजित गोवा के 9वें बर्ड फेस्टिवल के दौरान जारी किया गया।

2. Goa became the second state in India, after Kerala, to publish a comprehensive state-level bird atlas.

केरल के बाद गोवा भारत का दूसरा राज्य बना जिसने राज्य-स्तरीय व्यापक बर्ड एटलस प्रकाशित किया।

3. The atlas covers about 370 sq km area and nearly 1,400 km of transect distance.

यह एटलस लगभग 370 वर्ग किमी क्षेत्र और करीब 1,400 किमी ट्रांसेक्ट दूरी को कवर करता है।

4. The theme of the Bird Festival was “Majestic Mhadei”, highlighting the ecological importance of the Mhadei river basin.

बर्ड फेस्टिवल की थीम “मैजेस्टिक म्हादेई” थी, जो म्हादेई नदी बेसिन के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है।

Which of the statements given above are correct?

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2

B) 1, 2 and 3 only / केवल 1, 2 और 3

C) 2, 3 and 4 only / केवल 2, 3 और 4

D) 1, 2, 3 and 4 / 1, 2, 3 और 4

E) 1 and 4 only / केवल 1 और 4

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Bird Atlas of Goa was published by the Government of Goa during the 9th Bird Festival of Goa held at Valpoi.
- बर्ड एटलस ऑफ गोवा को गोवा सरकार द्वारा वालपोई में आयोजित 9वें बर्ड फेस्टिवल के दौरान जारी किया गया।
- Goa became the second Indian state after Kerala (2022) to publish a comprehensive state-level bird atlas.





- केरल (2022) के बाद गोवा ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य है।
- The atlas documents bird diversity across 370 sq km and nearly 1,400 km of transect distance.
- यह एटलस 370 वर्ग किमी क्षेत्र और लगभग 1,400 किमी ट्रांसेक्ट दूरी को कवर करता है।
- The theme of the festival was “Majestic Mhadei”, emphasising the ecological significance of the Mhadei River basin.
- उत्सव की थीम “मैजेस्टिक म्हादेई” थी, जो म्हादेई नदी बेसिन के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है।
- During the festival, an MoU was also signed between the Goa Forest Department and ResQ Charitable Trust to strengthen wildlife rescue and rehabilitation efforts across the state.
- इसी अवसर पर गोवा वन विभाग और ResQ चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच वन्यजीव बचाव व पुनर्वास हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

EXAM
Genius





Ques: Which state government signed a Letter of Intent (LoI) with Starlink to enhance satellite-based internet connectivity in remote and underserved areas?

किस राज्य सरकार ने दूरदराज़ और वंचित क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्टारलिनक के साथ आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Government of Rajasthan / राजस्थान सरकार
- B) Government of Maharashtra / महाराष्ट्र सरकार
- C) Government of Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश सरकार
- D) Government of Goa / गोवा सरकार
- E) Government of Gujarat / गुजरात सरकार

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Government of Gujarat signed a Letter of Intent (LoI) with Starlink Satellite Communications Private Limited in Gandhinagar to enhance high-speed satellite-based internet connectivity across remote, border, and underserved areas of the state.
- गुजरात सरकार ने दूरदराज़, सीमावर्ती और वंचित क्षेत्रों में उच्च गति सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गांधीनगर में स्टारलिनक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए।
- The pilot implementation will prioritise Aspirational Districts such as Narmada and Dahod to reduce regional digital disparities.
- पायलट कार्यान्वयन में क्षेत्रीय डिजिटल असमानताओं को कम करने के लिए नर्मदा और दाहोद जैसे आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- The initiative will connect Common Service Centres (CSCs) and e-Governance facilities to strengthen access to government digital services.
- इस पहल के तहत कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और ई-गवर्नेंस सुविधाओं को जोड़ा जाएगा ताकि सरकारी डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया जा सके।

About Gujarat :

- Capital : Gandhinagar
- Governor : Acharya Devvrat
- Chief Minister : Bhupendra Patel





About Starlink :

- Established : 2015
- CMO : Elon Musk
- HQ : California,U.S.
- Indian Subsidiary : NewDelhi



EXAM
Genius





Ques: Where was the first Emergency Landing Facility (ELF) of the Northeast inaugurated?

पूर्वोत्तर का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) कहाँ उद्घाटित किया गया?

- A) Guwahati, Assam / गुवाहाटी, असम
- B) Imphal, Manipur / इंफाल, मणिपुर
- C) Dibrugarh, Assam / डिब्रूगढ़, असम
- D) Agartala, Tripura / अगरतला, त्रिपुरा
- E) Shillong, Meghalaya / शिलांग, मेघालय

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first Emergency Landing Facility (ELF) of the Northeast in Dibrugarh, Assam.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) का उद्घाटन किया।
- The facility holds significant strategic importance for national security and disaster management.
- यह सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- It enables emergency landing of aircraft, including fighter jets, during natural disasters or strategic operations.
- यह प्राकृतिक आपदाओं या रणनीतिक अभियानों के दौरान फाइटर जेट सहित विमानों की आपातकालीन लैंडिंग को संभव बनाएगी।
- The ELF strengthens infrastructure development and improves overall connectivity in the Northeast region.
- यह ELF पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।





Ques: The 'India–Netherlands Hydrogen Fellowship Programme' was launched to support which key objective of India?

'भारत–नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम' भारत के किस प्रमुख उद्देश्य को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है?

- A) Expansion of nuclear energy capacity / परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार
- B) Development of fossil fuel infrastructure / जीवाश्म ईंधन अवसंरचना का विकास
- C) Capacity building in hydrogen technologies under National Green Hydrogen Mission / राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन तकनीकों में क्षमता निर्माण
- D) Promotion of electric vehicle manufacturing only / केवल इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा
- E) Space-based renewable energy research / अंतरिक्ष आधारित नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The India–Netherlands Hydrogen Fellowship Programme was launched in New Delhi by the Secretary, Department of Science and Technology, under the Ministry of Science and Technology.
- भारत–नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा किया गया।
- The initiative aims to build national capacity in hydrogen technologies by providing Indian fellows exposure to the advanced hydrogen ecosystem of the Netherlands.
- इस पहल का उद्देश्य भारतीय शोधकर्ताओं को नीदरलैंड्स के उन्नत हाइड्रोजन इकोसिस्टम से परिचित कराकर हाइड्रोजन तकनीकों में राष्ट्रीय क्षमता विकसित करना है।
- The fellowship is open to Indian PhD scholars, postdoctoral researchers, and faculty members from Indian institutions.
- यह फेलोशिप भारतीय पीएचडी शोधार्थियों, पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के लिए खुली है।
- The programme aligns with the Government of India's vision of the National Green Hydrogen Mission, Energy Independence by 2047, and Net-Zero emissions by 2070.
- यह पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।





About National Green Hydrogen Mission / राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में:

- The mission was launched in January 2023 by the Government of India under the Ministry of New and Renewable Energy.
- इस मिशन की शुरुआत जनवरी 2023 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
- It aims to scale up green hydrogen (H₂) production, utilisation, and exports, and establish India as a global leader in the clean hydrogen economy.
- इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ाना तथा भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में वैश्विक अग्रणी बनाना है।
- The mission has an initial outlay of ₹19,744 crore up to FY 2029–30 (FY30).
- इस मिशन के लिए वित्त वर्ष 2029–30 तक ₹19,744 करोड़ का प्रारंभिक परिव्यय निर्धारित किया गया है।

EXAM
Genius





Ques: Which Indian institution demonstrated a gentler method for recovering lab-grown T-cells, potentially making CAR T-cell cancer therapy more affordable in India?

भारत में CAR T-cell कैंसर थेरेपी को अधिक किफायती बनाने हेतु लैब-निर्मित T-cells को पुनः प्राप्त करने की एक सौम्य विधि किस संस्थान ने प्रदर्शित की?

- A) AIIMS Delhi / एम्स दिल्ली
- B) IISc Bengaluru / आईआईएससी बेंगलुरु
- C) NIMHANS / निमहांस
- D) PGIMER Chandigarh / पीजीआईएमईआर चंडीगढ़
- E) IIT Bombay / आईआईटी बॉम्बे

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- IIT Bombay, in a study published in Biomaterials Science, demonstrated a gentler method for recovering lab-grown T-cells.
- आईआईटी बॉम्बे ने Biomaterials Science में प्रकाशित शोध में लैब-निर्मित T-cells को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की नई विधि प्रदर्शित की।
- This advancement is significant for cancer immunotherapy, especially CAR T-cell therapy, as it improves efficiency and reduces wastage of costly cells.
- यह प्रगति कैंसर इम्यूनोथेरेपी, विशेषकर CAR T-cell थेरेपी, के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दक्षता बढ़ती है और महंगे कोशिकाओं की बर्बादी कम होती है।
- Globally, CAR T-cell therapies can cost ₹3–4 crore. By cutting waste and improving recovery, Indian initiatives like ImmunoACT aim to reduce costs to a fraction of global prices.
- वैश्विक स्तर पर CAR T-cell थेरेपी की लागत ₹3–4 करोड़ तक होती है। इस विधि से ImmunoACT जैसी भारतीय पहलें लागत को काफी कम कर सकती हैं।
- In 2023, NexCAR19 became India's first approved indigenous CAR-T cell therapy, developed through collaboration between IIT Bombay, Tata Memorial Centre, and ImmunoACT.
- 2023 में NexCAR19 भारत की पहली स्वदेशी CAR-T cell थेरेपी बनी, जिसे IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और ImmunoACT के सहयोग से विकसित किया गया।





- T-cells are a type of white blood cell that act as the body's frontline soldiers, constantly patrolling to detect infections or abnormal cells like cancer.
- T-cells श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार हैं, जो शरीर के फ्रंटलाइन सैनिक की तरह संक्रमण और कैंसर जैसी असामान्य कोशिकाओं की पहचान करते हैं।
- CAR T-cell therapy is currently approved for certain blood cancers such as leukemia and lymphoma.
- CAR T-cell थेरेपी को वर्तमान में ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसरों के लिए स्वीकृति प्राप्त है।

Indian Institute of Technology :

- Established : Powai, Mumbai, Maharashtra
- Founding Year : 1958 (Supported by UNESCO & Soviet Union)
- Current Director : Shireesh Kedare (since 2024)

EXAM
Genius





Ques: Kumar Bhaskar Varma Setu, inaugurated in 2026, has been constructed across which river?

2026 में उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मा सेतु किस नदी पर बनाया गया है?

- A) Ganga / गंगा
- B) Yamuna / यमुना
- C) Brahmaputra / ब्रह्मपुत्र
- D) Godavari / गोदावरी
- E) Narmada / नर्मदा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Kumar Bhaskar Varma Setu in Guwahati, Assam.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया।
- The bridge has been constructed across the Brahmaputra River.
- यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है।
- It is described as a vital infrastructure project for Guwahati and the surrounding regions, expected to significantly enhance connectivity, travel comfort, and commercial activities.
- यह गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है, जिससे कनेक्टिविटी, यात्रा सुविधा और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
- The bridge will also provide easier access for devotees travelling to the Kamakhya Temple, a major religious site in Assam.
- यह पुल कामाख्या मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आवागमन को अधिक सुगम बनाएगा।
- The Prime Minister shared the inauguration details on social media, highlighting the strategic and developmental importance of the project for the region.
- प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस परियोजना की रणनीतिक और विकासात्मक महत्ता को रेखांकित किया।





Ques: Which authority has urged telecom consumers to actively use the DND app to report spam calls and SMS?

स्पैम कॉल और एसएमएस की शिकायत के लिए DND ऐप का सक्रिय उपयोग करने की अपील किस प्राधिकरण ने की है?

- A) Department of Telecommunications / दूरसंचार विभाग
- B) Telecom Regulatory Authority of India / भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- C) Ministry of Electronics & IT / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- D) BSNL / बीएसएनएल
- E) NITI Aayog / नीति आयोग

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has urged telecom consumers to download and actively use the DND (Do Not Disturb) app to report spam calls and SMS instead of only blocking numbers.
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम उपभोक्ताओं से केवल नंबर ब्लॉक करने के बजाय DND ऐप के माध्यम से स्पैम कॉल और एसएमएस की शिकायत दर्ज करने की अपील की है।
- TRAI Chairman Anil Kumar Lahoti emphasized that consumer reporting is essential for effective action against spam and unsolicited communications.
- ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि स्पैम के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज करना बेहद जरूरी है।
- TRAI will roll out a revamped My Call app in March, enabling users to file complaints related to call quality.
- ट्राई मार्च में संशोधित My Call ऐप लॉन्च करेगा, जिससे उपभोक्ता कॉल गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे।
- The DND app will provide multilingual options and improved complaint management features.
- DND ऐप में बहुभाषी विकल्प और बेहतर शिकायत प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- Enhanced consumer participation will help TRAI in stricter monitoring and action against Unsolicited Commercial Communications (UCC).
- उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से अवांछित वाणिज्यिक संचार (UCC) के खिलाफ कड़ी निगरानी और प्रभावी कार्रवाई संभव होगी।





Ques: ISRO has identified which location as the prospective landing site for the Chandrayaan-4 mission near the Moon's south pole?

इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किस स्थान को संभावित लैंडिंग साइट के रूप में चिन्हित किया है?

- A) Shackleton Crater / शैकलटन क्रेटर
- B) Malapert Massif / मलापर्ट मैसिफ
- C) Aristarchus Plateau / एरिस्टार्कस पठार
- D) Tycho Crater / टाइको क्रेटर
- E) Mons Mouton-4 / मॉन्स मूटन-4

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Indian Space Research Organisation (ISRO) has identified Mons Mouton-4, located in the Mons Mouton region near the Moon's south pole, as the prospective touchdown zone for the Chandrayaan-4 mission.
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स मूटन क्षेत्र में स्थित मॉन्स मूटन-4 को चंद्रयान-4 मिशन के लिए संभावित लैंडिंग स्थल के रूप में चिन्हित किया है।
- The site offers minimal surface obstacles, continuous sunlight for nearly 11–12 days, stable Earth communication, and high scientific potential for studying water-ice deposits.
- यह स्थल कम बाधाओं वाला है, लगभग 11–12 दिनों तक निरंतर सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, पृथ्वी से विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करता है तथा जल-बर्फ (वॉटर-आइस) के अध्ययन की उच्च वैज्ञानिक क्षमता रखता है।
- Chandrayaan-4 is India's most complex lunar mission, comprising five modules: Propulsion, Descender, Ascender, Transfer, and Re-entry modules.
- चंद्रयान-4 भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र मिशन है, जिसमें पाँच मॉड्यूल शामिल हैं: प्रोपल्शन, डिसेंडर, एस्केंडर, ट्रांसफर और री-एंट्री मॉड्यूल।
- The mission is aimed at collecting lunar samples and safely returning them to Earth and is targeted for launch in 2028.
- इस मिशन का उद्देश्य चंद्र नमूनों को एकत्र कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है तथा इसका प्रक्षेपण 2028 के लिए निर्धारित है।





All Previous Chandrayaan Missions / सभी पूर्व चंद्रयान मिशन

- Chandrayaan-1 (2008): Discovery of water molecules on the Moon.
- Chandrayaan-2 (2019): Orbiter successful; lander crash-landed.
- Chandrayaan-3 (2023): Successful soft landing near the Moon's south pole.

Indian Space Research Organisation:

- Established : 1969
- HQ : Bengaluru
- Chairperson : Dr. V. Narayanan
- Motto : Space technology in the service of humankind

EXAM
Genius





Ques: Who won Thailand's general election for the 500-member House of Representatives?

500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए थाईलैंड का आम चुनाव किसने जीता?

- A) Prayut Chan-o-cha / प्रयुत चान-ओ-चा
- B) Srettha Thavisin / स्रेथा थाविसिन
- C) Anutin Charnvirakul / अनुतिन चार्नवीराकुल
- D) Paetongtarn Shinawatra / पैटोंगटार्न शिनावत्रा
- E) Abhisit Vejjajiva / अभिसित वेज्जाजीवा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Anutin Charnvirakul won Thailand's general election for the 500-member House of Representatives.
- अनुतिन चार्नवीराकुल ने 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए थाईलैंड का आम चुनाव जीता।
- He became Prime Minister of Thailand in September 2025 following political unrest and was serving as the caretaker Prime Minister during the election.
- राजनीतिक अशांति के बाद वह सितंबर 2025 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने और चुनाव के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे।
- Before entering top-level politics, he was a former top executive and head of Sino-Thai Engineering.
- शीर्ष राजनीति में आने से पहले, वह सिनो-थाई इंजीनियरिंग के शीर्ष कार्यकारी और प्रमुख रह चुके हैं।





Ques: Airports Authority of India (AAI) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with which organisation to improve last-mile connectivity at select airports?

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने चुनिंदा हवाई अड्डों पर अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुधारने के लिए किस संगठन के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) Bharat Taxi / भारत टैक्सी
- B) Uber India / उबर इंडिया
- C) Ola Mobility / ओला मोबिलिटीx
- D) IRCTC / आईआरसीटीसी
- E) Yulu Bikes / यूलू बाइक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Airports Authority of India (AAI) has signed an MoU with Bharat Taxi to improve last-mile connectivity at select airports.
- एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने चुनिंदा हवाई अड्डों पर अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत टैक्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- Bharat Taxi is India's first driver-owned cooperative taxi service, operated by Sahakar Taxi Cooperative Ltd.
- भारत टैक्सी भारत की पहली ड्राइवर-स्वामित्व वाली सहकारी टैक्सी सेवा है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड संचालित करता है।
- The platform is promoted by the National Cooperative Development Corporation (NCDC).
- इस प्लेटफॉर्म को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) द्वारा प्रोत्साहित किया गया है।
- Under the plan, services will be introduced at airports in Rajkot, Vadodara, Surat, Bhuj, Pune, Aurangabad, Varanasi, Kanpur, Prayagraj, and Agra.
- इस योजना के तहत राजकोट, वडोदरा, सूरत, भुज, पुणे, औरंगाबाद, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और आगरा के हवाई अड्डों पर सेवाएँ शुरू की जाएँगी।





Ques: The Indian Tsunami Early Warning System (ITEWS) has been established at which organisation and functions under which ministry?

भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ITEWS) किस संस्था में स्थापित है और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है?

- A) National Institute of Ocean Technology under Ministry of Science & Technology / राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
B) Survey of India under Ministry of Home Affairs / सर्वे ऑफ इंडिया – गृह मंत्रालय
C) Indian National Centre for Ocean Information Services under Ministry of Earth Sciences / INCOIS – पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
D) CSIR-NGRI under Ministry of Education / सीएसआईआर-एनजीआरआई – शिक्षा मंत्रालय
E) ISRO under Department of Space / इसरो – अंतरिक्ष विभाग

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Indian Tsunami Early Warning System (ITEWS) has been established at the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), Hyderabad, in 2007.
- भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली (ITEWS) की स्थापना 2007 में हैदराबाद स्थित INCOIS में की गई थी।
- INCOIS functions under the Ministry of Earth Sciences.
- INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- ITEWS is an integrated effort involving the Department of Space, Department of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Survey of India, and National Institute of Ocean Technology (NIOT).
- यह अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR, सर्वे ऑफ इंडिया और NIOT की संयुक्त पहल है।
- The programme aims to improve coastal community preparedness for tsunami emergencies and minimise loss of life and property.
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य तटीय समुदायों की तैयारी बढ़ाना और जन-धन की हानि कम करना है।
- ITEWS includes a real-time network of seismic stations, BPR buoys, tide gauges, and a 24×7 operational tsunami warning centre to detect tsunamigenic earthquakes and issue timely advisories.





- ITEWS में सीस्मिक स्टेशन, BPR बॉय, टाइड गेज और 24×7 सक्रिय चेतावनी केंद्र शामिल हैं।
- The system can detect tsunamigenic earthquakes in the Indian Ocean within 10 minutes.
- यह प्रणाली 10 मिनट के भीतर भारतीय महासागर में सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंप का पता लगा सकती है।
- It provides a lead time of 10–20 minutes for near-source regions like Andaman & Nicobar Islands and a few hours for the Indian mainland.
- यह अंडमान–निकोबार जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए 10–20 मिनट और मुख्य भूमि भारत के लिए कुछ घंटे का अग्रिम समय देती है।
- ITEWS is recognised by UNESCO as a Tsunami Service Provider (TSP), issuing advisories to 28 Indian Ocean Rim countries.
- UNESCO ने ITEWS को TSP के रूप में मान्यता दी है, जो 28 भारतीय महासागर तटीय देशों को परामर्श देता है।
- In 2004, India had no tsunami warning capability and minimal public awareness of tsunamis in the Indian Ocean.
- 2004 में भारत के पास सुनामी चेतावनी की कोई क्षमता नहीं थी और जन-जागरूकता भी सीमित थी।
- INCOIS is establishing a network of 35 stations to measure tectonic plate movements and vertical seabed displacement in real time.
- INCOIS 35 स्टेशनों का नेटवर्क विकसित कर रहा है ताकि टेक्टोनिक प्लेटों की गति और समुद्र तल के ऊर्ध्व विस्थापन को वास्तविक समय में मापा जा सके।
- INCOIS has partnered with Indian Space Research Organisation and Airports Authority of India to develop satellite-based message broadcasting through the indigenous navigation system NavIC.
- INCOIS ने ISRO और AAI के साथ मिलकर NavIC के माध्यम से सैटेलाइट आधारित संदेश प्रसारण सेवा विकसित की है।
- Two villages of Odisha — Venkatraipur (Ganjam) and Noliasahi (Jagatsinghpur) — have been certified as 'Tsunami Ready'.
- ओडिशा के दो गाँव — वेंकटरायपुर (गंजाम) और नोलियासाही (जगतसिंहपुर) — अब 'Tsunami रेडी' घोषित किए गए हैं।

ITEWS Infrastructure / ITEWS अवसंरचना:





- Seismic Network – Detects undersea earthquakes and estimates magnitude.
- सीस्मिक नेटवर्क – समुद्र के भीतर भूकंप का पता लगाता है और तीव्रता का अनुमान करता है।
- BPRs (Buoys) – Confirms tsunami wave triggering in the open ocean.
- BPR बॉय – खुले महासागर में सुनामी तरंग की पुष्टि करते हैं।
- Tide Gauges – Monitor wave progress and validate coastal arrival times.
- टाइड गेज – तरंगों की प्रगति और तट पर पहुँचने के समय की पुष्टि करते हैं।



EXAM
Genius





Ques: Which two public sector shipyards signed an MoU to form a strategic consortium for executing a large-scale National Shipbuilding Programme?

किस दो सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड्स ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जहाज निर्माण कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक रणनीतिक कंसोर्टियम बनाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. & Cochin Shipyard Ltd. / मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड एवं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
- B) Goa Shipyard Ltd. & Hindustan Shipyard Limited / गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
- C) Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. & Hindustan Shipyard Limited / गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
- D) Cochin Shipyard Ltd. & Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. / कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एवं गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
- E) Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. & Goa Shipyard Ltd. / मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड एवं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE) and Hindustan Shipyard Limited (HSL) signed a Memorandum of Understanding (MoU) in Kolkata to form a strategic consortium for executing a large-scale national shipbuilding programme.
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने कोलकाता में एक बड़े पैमाने के राष्ट्रीय जहाज निर्माण कार्यक्रम को लागू करने के लिए रणनीतिक कंसोर्टियम बनाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- Under the MoU, GRSE and HSL will jointly collaborate on the design, construction, and delivery of ships for national requirements.
- इस MoU के तहत, GRSE और HSL राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए जहाजों की डिजाइन, निर्माण और डिलीवरी में सहयोग करेंगे।
- The National Shipbuilding Programme is a strategic sovereign initiative aimed at transforming India into a top 5 global shipbuilding hub by 2047 through indigenous construction of commercial and defence vessels.
- राष्ट्रीय जहाज निर्माण कार्यक्रम एक रणनीतिक संप्रभु पहल है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रूप से वाणिज्यिक





Ques: The Offshore Areas Mineral Rules, 2026 were introduced by the Government of India primarily to achieve which objective?

ऑफशोर एरिया मिनरल रूल्स, 2026 भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लागू किए गए हैं?

- A) Promote offshore oil and gas exploration / ऑफशोर तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देना
- B) Regulate and prevent illegal offshore mining of minerals / ऑफशोर खनिजों के अवैध खनन को विनियमित और रोकना
- C) Privatise offshore mineral resources / ऑफशोर खनिज संसाधनों का निजीकरण करना
- D) Support only scientific oceanographic research / केवल वैज्ञानिक महासागरीय अनुसंधान को समर्थन देना
- E) Reduce export of coastal minerals / तटीय खनिजों के निर्यात को कम करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Offshore Areas Mineral Rules, 2026 have been notified by the Ministry of Mines and came into immediate effect.
- ऑफशोर एरिया मिनरल रूल्स, 2026 को खनन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गए।
- The rules aim to regulate offshore mining activities and prevent illegal mining, storage, transportation, and export of offshore minerals, excluding hydrocarbons.
- इन नियमों का उद्देश्य हाइड्रोकार्बन को छोड़कर ऑफशोर खनिजों के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन और निर्यात को रोकना है।
- The rules are issued under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.
- ये नियम ऑफशोर एरिया मिनरल (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 के तहत जारी किए गए हैं।

Scope & Key Provisions / दायरा और प्रमुख प्रावधान

- The rules apply to all operators and entities engaged in offshore mineral activities and exempt non-commercial scientific or research activities.
- ये नियम सभी ऑपरेटरों और संस्थाओं पर लागू होते हैं तथा गैर-व्यावसायिक वैज्ञानिक या अनुसंधान गतिविधियों को छूट देते हैं।





- Illegal mining is defined as operations carried out without valid rights or beyond approved limits.
- अवैध खनन का अर्थ बिना वैध अधिकार या स्वीकृत सीमा से अधिक खनन करना है।
- Operators and carrier owners must install real-time Electronic Monitoring Systems, and all machinery and carriers must be officially registered.
- ऑपरेटर्स और वाहक मालिकों को रियल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है तथा सभी मशीनरी और वाहनों का पंजीकरण आवश्यक है।
- The powers of the Indian Bureau of Mines have been extended to the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research for threshold-grade atomic minerals.
- इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की शक्तियाँ एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च तक विस्तारित की गई हैं।

Transit & Export / परिवहन और निर्यात

- Movement of minerals requires uploading dispatch details to obtain digital transit permits.
- खनिजों के परिवहन के लिए डिजिटल ट्रांजिट परमिट आवश्यक है।
- Mandatory weighing of minerals at discharge points has been prescribed.
- डिस्चार्ज प्वाइंट पर खनिजों का अनिवार्य तौल किया जाएगा।
- Prior clearance from the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) is required for export.
- निर्यात के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

Penalties & Appeals / दंड और अपील

- Appeals against orders can be made to the Central Government within 3 months.
- आदेश के विरुद्ध 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार में अपील की जा सकती है।
- Violations may attract imprisonment up to 5 years.
- उल्लंघन पर 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
- Penalties range from ₹50 lakh to ₹1 crore, with ₹5 lakh per day for continuing violations.
- दंड ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक हो सकता है, और निरंतर उल्लंघन पर ₹5 लाख प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।





Ques: What is iLive Connect, recently launched in India?

भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया iLive Connect क्या है?

- A) A government health insurance scheme / एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना
- B) A hospital management software / एक अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर
- C) The world's first doctor-led, AI-powered home healthcare ecosystem / दुनिया का पहला डॉक्टर-नेतृत्व वाला, एआई-संचालित होम हेल्थकेयर इकोसिस्टम
- D) A fitness tracking mobile application / एक फिटनेस ट्रैकिंग मोबाइल एप्लिकेशन
- E) A telemedicine chatbot service / एक टेलीमेडिसिन चैटबॉट सेवा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India launched iLive Connect, the world's first doctor-led, Artificial Intelligence (AI) powered healthcare ecosystem, aimed at providing 24×7 medical monitoring from patients' homes.
- भारत ने iLive Connect लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला डॉक्टर-नेतृत्व वाला एआई-संचालित हेल्थकेयर इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य मरीजों को उनके घर से ही 24×7 चिकित्सा निगरानी प्रदान करना है।
- It is especially designed for senior citizens and high-risk patients, functioning like a personalised Intensive Care Unit (ICU) at home.
- यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उच्च जोखिम वाले मरीजों के लिए तैयार किया गया है, जो घर पर ही एक व्यक्तिगत आईसीयू की तरह कार्य करता है।
- The platform was developed by cardiothoracic surgeon Dr Rahul Chandola and interventional cardiologist Dr Viveka Kumar.
- इस प्रणाली को कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. राहुल चंदोला और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. विवेका कुमार ने विकसित किया है।
- The system uses FDA and European Conformity (CE) certified wearable devices, including a chest-mounted biosensor patch and a wristband, for continuous real-time monitoring.
- यह प्रणाली FDA और यूरोपियन कन्फॉर्मिटी (CE) प्रमाणित पहनने योग्य उपकरणों का उपयोग करती है, जैसे चेस्ट-माउंटेड बायोसेंसर पैच और रिस्टबैंड।
- It continuously tracks vital health parameters such as two-lead ECG, heart rate, respiratory rate, oxygen saturation, body temperature, blood pressure trends, physical





Ques: World Unani Day is observed on which date?

विश्व यूनानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) February 5
- B) February 8
- C) February 10
- D) February 11
- E) February 13

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- World Unani Day is observed on February 11 to commemorate the birth anniversary of Mohammad Ajmal Khan, also known as Hakim Ajmal Khan.
- विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को Mohammad Ajmal Khan (हकीम अजमल खान) की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- Hakim Ajmal Khan was an eminent Indian Unani physician and a noted social reformer.
- हकीम अजमल खान एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक और सामाजिक सुधारक थे।
- The theme of World Unani Day 2026 is “Innovation and Evidence in Unani Practice”.
- विश्व यूनानी दिवस 2026 की थीम “यूनानी चिकित्सा में नवाचार और साक्ष्य” है।
- The day aims to highlight the significance of the Unani system of medicine and promote evidence-based practices.
- इस दिवस का उद्देश्य यूनानी चिकित्सा पद्धति के महत्व को उजागर करना और साक्ष्य-आधारित अभ्यासों को बढ़ावा देना है।





Ques: International Day of Women and Girls in Science is observed on which date?

विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) February 8
- B) February 10
- C) February 15
- D) February 18
- E) February 11

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- International Day of Women and Girls in Science is observed annually on February 11.
- विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है।
- The theme for International Day of Women and Girls in Science 2026 is “Synergizing AI, Social Science, STEM and Finance: Building Inclusive Futures for Women and Girls”.
- अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस 2026 की थीम है “एआई, सामाजिक विज्ञान, STEM और वित्त का समन्वय: महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण”.
- The day aims to promote full and equal access to participation in science for women and girls.
- इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान एवं पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- The observance was started in 2011.
- इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी।





Ques: Punjab National Bank (PNB) announced which themed half marathon to honour the Indian Armed Forces and promote fitness?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देने और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए किस थीम आधारित हाफ मैराथन की घोषणा की?

- A) PNB Fit India Run / पीएनबी फिट इंडिया रन
- B) PNB Veer Run / पीएनबी वीर रन
- C) PNB Soldierathon 2026 / पीएनबी सोल्जरार्थॉन 2026
- D) PNB National Pride Marathon / पीएनबी नेशनल प्राइड मैराथन
- E) PNB Unity Run / पीएनबी यूनिटी रन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) announced the 'PNB Soldierathon 2026', a themed half marathon, at its Corporate Office in Dwarka, New Delhi.
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने द्वारका, नई दिल्ली स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में थीम आधारित हाफ मैराथन 'PNB सोल्जरार्थॉन 2026' की घोषणा की।
- The initiative aims to honour the Indian Armed Forces.
- इस पहल का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देना है।
- It also seeks to promote fitness and a healthy lifestyle among citizens.
- यह नागरिकों में फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।
- The event encourages discipline, national pride, and stronger community engagement.
- यह आयोजन अनुशासन, राष्ट्रीय गौरव और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है।
- The Soldierathon is part of PNB's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives and supports nation-building efforts.
- सोल्जरार्थॉन PNB की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल का हिस्सा है और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का समर्थन करता है।





Ques: What did the Ministry of Finance state regarding Foreign Direct Investment (FDI) equity inflows into India's banking sector in FY 2024–25?

वित्त वर्ष 2024–25 में बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी प्रवाह को लेकर वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?

- A) It increased sharply compared to FY23 / FY23 की तुलना में इसमें तेज़ वृद्धि हुई
- B) It remained unchanged from FY23 / यह FY23 के समान ही रहा
- C) It declined significantly compared to FY23 / FY23 की तुलना में इसमें भारी गिरावट आई
- D) It crossed USD 1 billion / यह 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया
- E) Data was not disclosed / आंकड़े जारी नहीं किए गए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Ministry of Finance stated that FDI equity inflows into the banking sector declined to USD 115 million in FY 2024–25, compared to USD 898 million in FY 2022–23.
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह FY 2024–25 में घटकर 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि FY 2022–23 में यह 898 मिलियन डॉलर था।
- FDI inflows include equity inflow, equity capital of unincorporated bodies, re-invested earnings, and other capital.
- FDI प्रवाह में इक्विटी निवेश, अविनियमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय, और अन्य पूंजी शामिल होती है।
- Among public sector banks, State Bank of India recorded the highest foreign shareholding.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में सबसे अधिक विदेशी शेयरधारिता दर्ज की गई।
- **This foreign shareholding includes investments from:**
 - Foreign Direct Investment (FDI) / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
 - Foreign Portfolio Investors / Foreign Institutional Investors (FPI/FII) / विदेशी पोर्टफोलियो/ संस्थागत निवेशक
 - Non-Resident Indians (NRIs) / अनिवासी भारतीय





- As per the Reserve Bank of India Master Directions on 'Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies', prior RBI approval is mandatory for acquiring 5% or more of the paid-up capital of a banking company.
- RBI के 'बैंकिंग कंपनियों में शेयर या मतदान अधिकारों के अधिग्रहण एवं धारण' संबंधी मास्टर निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक की चुकता पूंजी का 5% या उससे अधिक अधिग्रहण करने के लिए RBI की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

Rankings with their foreign Shareholding :

- 1 State Bank of India - 11.07%
- 2 Canara Bank - 10.55%
- 3 Bank of Baroda - 9.43%
- 4 Union Bank of India - 7.48%
- 5 Punjab National Bank - 5.85%

EXAM
Genius





Ques: According to a report by State Bank of India (SBI), what percentage of India's agricultural exports to the United States will now face zero tariff?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अमेरिका को होने वाले कृषि निर्यात का कितना प्रतिशत अब शून्य शुल्क (Zero Tariff) का लाभ प्राप्त करेगा?

- A) 50%
- B) 60%
- C) 65%
- D) 70%
- E) 75%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- According to a report by State Bank of India (SBI), nearly 75% of India's agricultural exports to the United States will now face zero tariff.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को भारत के लगभग 75% कृषि निर्यात पर अब शून्य शुल्क लगेगा।
- Agricultural products worth \$1.36 billion will get access to the US market with zero additional duty.
- \$1.36 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों को अमेरिका में बिना अतिरिक्त शुल्क के प्रवेश मिलेगा।
- Products worth \$1.035 billion are assured zero reciprocal tariff treatment.
- \$1.035 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों को शून्य पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariff) की गारंटी दी गई है।
- This move strengthens India's agricultural trade surplus of around \$1.3 billion with the United States.
- यह कदम अमेरिका के साथ भारत के लगभग \$1.3 अरब के कृषि व्यापार अधिशेष को और मज़बूत करता है।
- The zero-tariff access is expected to improve price competitiveness and boost export volumes.
- शून्य शुल्क व्यवस्था से भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धा और निर्यात मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है।

Major Beneficiary Sectors / प्रमुख लाभार्थी क्षेत्र:





Rice:

- US global rice imports stand at \$1.378 billion, with imports from India at \$341 million.
- The US rice import market share of India is 24.7%.
- चावल: अमेरिका का कुल चावल आयात \$1.378 अरब है, जिसमें भारत से \$341 मिलियन का आयात होता है और भारत की हिस्सेदारी 24.7% है।

Fishery Sector:

- US global imports of fish and aquatic invertebrates are valued at \$18.84 billion.
- Imports from India amount to \$1.8 billion, giving India a 9.6% share.
- मत्स्य क्षेत्र: अमेरिका का कुल आयात \$18.84 अरब है, जिसमें भारत से \$1.8 अरब का आयात होता है और हिस्सेदारी 9.6% है।

Tea, Coffee and Spices:

- US global imports are \$14.02 billion, with India exporting \$396 million.
- India's share stands at 2.8%.
- चाय, कॉफी और मसाले: अमेरिका का कुल आयात \$14.02 अरब है, जिसमें भारत से \$396 मिलियन का आयात होता है और हिस्सेदारी 2.8% है।

Overall Agricultural Trade Position / समग्र कृषि व्यापार स्थिति:

- Across selected categories, total US agricultural imports are \$81.95 billion.
- Imports from India amount to \$2.89 billion, giving India an overall share of 3.5%.
- चयनित श्रेणियों में अमेरिका का कुल कृषि आयात \$81.95 अरब है, जिसमें भारत से \$2.89 अरब का आयात होता है और कुल हिस्सेदारी 3.5% है।





Ques: Which organization introduced a Braille-enabled Premier Credit Card to support visually impaired users in India?

दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रेल-सक्षम प्रीमियर क्रेडिट कार्ड किस संस्था ने पेश किया?

- A) State Bank of India (SBI) / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank (PNB) / पंजाब नेशनल बैंक
- C) BOBCARD Limited (Bank of Baroda) / बॉबकार्ड लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा)
- D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- BOBCARD Limited, the credit card arm of Bank of Baroda, introduced a Braille-enabled version of its Premier Credit Card at an event held in Manipal, Karnataka.
- बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड इकाई BOBCARD लिमिटेड ने कर्नाटक के मणिपाल में आयोजित कार्यक्रम में ब्रेल-सक्षम प्रीमियर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
- The card incorporates Braille elements to help visually impaired users identify and use the card with greater ease and confidence during everyday transactions.
- इस कार्ड में ब्रेल चिह्न शामिल किए गए हैं, जिससे दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता दैनिक लेन-देन में कार्ड को आसानी और आत्मविश्वास के साथ पहचान व उपयोग कर सकें।
- It also provides accelerated rewards on travel, lifestyle, dining, and international transactions.
- इसमें यात्रा, लाइफस्टाइल, डाइनिंग और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर तेज़ रिवॉईस मिलते हैं।
- The card offers travel benefits, including complimentary domestic airport lounge access and curated lifestyle privileges.
- कार्ड में घरेलू हवाई अड्डों के लाउंज की निःशुल्क सुविधा और विशेष लाइफस्टाइल लाभ भी शामिल हैं।

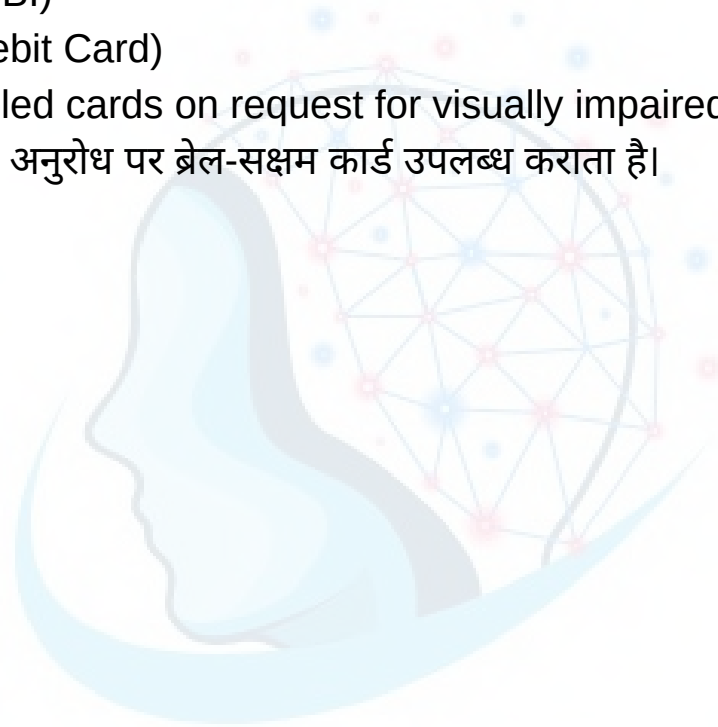
Braille-Enabled Card Providers in India | भारत में ब्रेल-सक्षम कार्ड प्रदाता

- Punjab National Bank (PNB)
 - PNB Braille Credit Card (Credit Card)
 - First major bank to launch a dedicated Braille Credit Card (December 2025).





- ब्रेल-सक्षम समर्पित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बड़ा बैंक।
- BOBCARD Limited / Bank of Baroda
- bob inSIGHT Debit Card (Debit Card)
- Features tactile dots and a rounded notch for orientation.
- पहचान हेतु स्पर्शनीय डॉट्स और राउंडेड नॉच की सुविधा।
- State Bank of India (SBI)
- Braille Debit Card (Debit Card)
- Provides Braille-enabled cards on request for visually impaired account holders.
- दृष्टिबाधित खाताधारकों को अनुरोध पर ब्रेल-सक्षम कार्ड उपलब्ध कराता है।



EXAM
Genius





Ques: Who became the first bowler to take 700 wickets in T20 cricket?

T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज़ कौन बने?

- A) Lasith Malinga / लसिथ मलिंगा
- B) Dwayne Bravo / ड्वेन ब्रावो
- C) Rashid Khan / राशिद खान
- D) Sunil Narine / सुनील नरेन
- E) Jasprit Bumrah / जसप्रीत बुमराह

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Rashid Khan, the captain of Afghanistan, became the first bowler in history to take 700 wickets in T20 cricket.
- अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज़ बने।
- He achieved this historic milestone during a T20 World Cup match against the UAE in New Delhi.
- उन्होंने यह उपलब्धि UAE के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में नई दिल्ली में हासिल की।
- Rashid Khan completed his 700th wicket by dismissing Muhammad Arfan.
- राशिद खान ने मुहम्मद अरफान को आउट कर अपना 700वां विकेट पूरा किया।
- He reached the landmark in just 518 T20 matches, highlighting his consistency and longevity.
- उन्होंने यह रिकॉर्ड मात्र 518 T20 मैचों में हासिल किया।
- Rashid's key bowling figures include an average of 18.51, strike rate of 16.8, and an economy rate of 6.59.
- राशिद का गेंदबाज़ी औसत 18.51, स्ट्राइक रेट 16.8 और इकॉनमी रेट 6.59 रहा है।
- He is widely regarded as one of the greatest T20 spinners in world cricket.
- उन्हें विश्व क्रिकेट के महानतम T20 स्पिनरों में गिना जाता है।





Ques: Which state government launched the 'Sthree Suraksha Scheme' to provide social security pension to unemployed women and transgender women?

किस राज्य सरकार ने बेरोज़गार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए 'स्त्री सुरक्षा योजना' शुरू की?

- A) Government of Kerala / केरल सरकार
- B) Government of Tamil Nadu / तमिलनाडु सरकार
- C) Government of Karnataka / कर्नाटक सरकार
- D) Government of Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश सरकार
- E) Government of Telangana / तेलंगाना सरकार

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Chief Minister of Kerala, Pinarayi Vijayan, launched the 'Sthree Suraksha Scheme'.
- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 'स्त्री सुरक्षा योजना' की शुरुआत की।
- The scheme is a social security pension initiative aimed at supporting unemployed women and transgender women not covered under existing welfare pensions.
- यह योजना उन बेरोज़गार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहल है जो मौजूदा कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- Under the scheme, eligible beneficiaries will receive a monthly pension of ₹1,000.
- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- The target group includes economically disadvantaged women and transgender women.
- लक्षित समूह में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं और ट्रांसजेंडर महिलाएं शामिल हैं।
- Eligibility criteria include age between 35 and 60 years and permanent residency in Kerala.
- पात्रता मानदंडों में 35 से 60 वर्ष की आयु और केरल का स्थायी निवासी होना शामिल है।
- Applicants must hold either an Antyodaya Anna Yojana (Yellow) ration card or a Priority Household (Pink) ration card.





Ques: Which schemes are being implemented by the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) to boost the food processing sector in India?

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा कौन-सी योजनाएँ लागू की जा रही हैं?

- A) PMKSY, PLISFPI and PMFME / पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई
- B) PMFBY, PMJDY and PMAY / पीएमएफबीवाई, पीएमजेडीवाई और पीएमएवाई
- C) PMGSY, PMUY and PMEGP / पीएमजीएसवाई, पीएमयूवाई और पीएमईजीपी
- D) PMAY, PMFBY and PLISFPI / पीएमएवाई, पीएमएफबीवाई और पीएलआईएसएफपीआई
- E) PMFME, PMUY and PMJDY / पीएमएफएमई, पीएमयूवाई और पीएमजेडीवाई

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) is implementing multiple schemes to promote the overall development of the food processing sector.
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई योजनाएँ लागू कर रहा है।
- Central Sector Schemes include Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY) and the Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI).
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) शामिल हैं।
- PMKSY aims to provide financial assistance for setting up and expanding food processing industries and to create modern infrastructure with efficient supply chains.
- पीएमकेएसवाई का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए वित्तीय सहायता और आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है।
- PLISFPI seeks to create global food manufacturing champions and promote Indian food brands in international markets during 2021–22 to 2026–27 with an outlay of ₹10,900 crore.
- पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनाना और भारतीय खाद्य ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना है।
- The Centrally Sponsored Scheme PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) supports micro food enterprises through financial, technical, and





Ques: Where will India's first national 'Cow Culture Museum' be established?

भारत का पहला राष्ट्रीय 'गौ संस्कृति संग्रहालय' कहाँ स्थापित किया जाएगा?

- A) Mathura / मथुरा
- B) Ayodhya / अयोध्या
- C) Varanasi / वाराणसी
- D) Lucknow / लखनऊ
- E) Haridwar / हरिद्वार

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या :

- India's first national Cow Culture Museum will be established in Mathura.
- भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया जाएगा।
- The initiative has been taken by the Uttar Pradesh Braj Teerth Vikas Parishad.
- यह पहल उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा की गई है।
- The museum will be set up at the campus of Pandit Deendayal Upadhyaya Veterinary Science University, Mathura.
- यह संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा के परिसर में बनाया जाएगा।
- It will showcase the religious, cultural, spiritual and scientific significance of cows.
- इसमें गायों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा।
- Around 100 digital and symbolic models of cattle will be displayed, including major and endangered breeds.
- इसमें लगभग 100 डिजिटल और प्रतीकात्मक पशु मॉडल, जिनमें प्रमुख एवं लुप्तप्राय नस्लें शामिल होंगी, प्रदर्शित किए जाएंगे।
- A special exhibition on milk and dairy products such as milk, curd, cheese and ghee will be a major attraction.
- दूध एवं दुग्ध उत्पादों (दूध, दही, पनीर, घी) पर विशेष प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होगी।
- A dairy parlour will also be developed on the premises to provide pure dairy products.
- परिसर में शुद्ध दुग्ध उत्पादों के लिए एक डेयरी पार्लर भी विकसित किया जाएगा।





Ques: Which institution released the ten-year roadmap titled “Technology Services – Reimagination Ahead” to scale India’s technology services sector by 2035?

किस संस्था ने 2035 तक भारत के प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र को विस्तार देने के लिए “Technology Services – Reimagination Ahead” शीर्षक से दस-वर्षीय रोडमैप जारी किया?

- A) Ministry of Electronics and IT / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- B) NITI Aayog – Frontier Tech Hub / नीति आयोग – फ्रंटियर टेक हब
- C) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- D) Department of Science and Technology / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- E) Invest India / इन्वेस्ट इंडिया

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- NITI Aayog’s Frontier Tech Hub released a ten-year roadmap titled “Technology Services – Reimagination Ahead”.
- नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने “Technology Services – Reimagination Ahead” शीर्षक से दस-वर्षीय रोडमैप जारी किया।
- The roadmap outlines how India’s technology services sector, currently around \$265 billion, can scale to \$750–850 billion by 2035.
- यह रोडमैप दर्शाता है कि लगभग 265 अरब डॉलर के भारत के टेक्नोलॉजी सेवा क्षेत्र को 2035 तक 750–850 अरब डॉलर तक कैसे बढ़ाया जा सकता है।
- The roadmap aligns with the vision of Viksit Bharat 2047 and aims to boost India’s global competitiveness in the AI era.
- यह रोडमैप विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप है और एआई युग में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- The roadmap was unveiled by Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry.
- इस रोडमैप का अनावरण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया।
- The NITI Frontier Tech Hub functions as an action tank to anticipate mega-technology shifts, strengthen preparedness, unlock economic growth, ensure inclusive outcomes, and build strategic resilience.





Ques: Who set a new world record while winning gold in the Men's 50m Rifle 3 Positions event at the Asian Shooting Championships 2026 held in New Delhi?

नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोज़िशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतते हुए नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया?

- A) Niraj Kumar / नीरज कुमार
- B) Akhil Sheoran / अखिल श्योराण
- C) Abhinav Bindra / अभिनव बिंद्रा
- D) Aishwary Pratap Singh Tomar / ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर
- E) Swapnil Kusale / स्वप्निल कुसाले

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Two-time Olympian Aishwary Pratap Singh Tomar created history by setting a new world record in the Men's 50m Rifle 3 Positions event at the Asian Shooting Championships 2026.
- दो बार के ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोज़िशन स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया।
- The championship was held in New Delhi.
- यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
- Aishwary Pratap Singh Tomar won the gold medal with a score of 362.0, which was a world record.
- ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 362.0 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक विश्व रिकॉर्ड है।
- Silver medal was won by Niraj Kumar with 361.8 points, while Akhil Sheoran secured bronze with 343.5 points.
- रजत पदक नीरज कुमार ने 361.8 अंकों के साथ जीता, जबकि कांस्य पदक अखिल श्योराण ने 343.5 अंकों के साथ हासिल किया।
- India achieved a clean sweep of the podium in this event.
- इस स्पर्धा में भारत ने पोज़ियम पर क्लीन स्वीप हासिल किया।





Ques: Which State became the first in India to adopt a comprehensive Urban Policy?

व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना?

- A) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) Kerala / केरल
- E) Gujarat / गुजरात

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Kerala has become India's first State to adopt a comprehensive Urban Policy to guide development over the next 25 years.
- केरल अगले 25 वर्षों के विकास को दिशा देने के लिए व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है।
- The policy was prepared by the Local Self-Government Department and approved by the State Cabinet.
- यह नीति स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा तैयार की गई और राज्य मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी।
- The Kerala Urban Policy Commission was constituted in December 2023 and submitted its report in March 2025.
- केरल अर्बन पॉलिसी आयोग का गठन दिसंबर 2023 में हुआ और उसने मार्च 2025 में रिपोर्ट सौंपी।
- The policy envisions 80% urbanisation by 2050, focusing on scientific planning, climate resilience, environmentally sensitive development, and creating a network of climate-smart cities and towns.
- नीति के अनुसार 2050 तक 80% शहरीकरण, वैज्ञानिक नियोजन, जलवायु अनुकूलता और पर्यावरण-संवेदनशील विकास पर जोर दिया गया है।
- It includes 10 key pillars to address urban challenges and strengthens Public-Private-People Partnership (PPPP) for future growth.
- शहरी चुनौतियों के समाधान हेतु 10 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं और PPPP मॉडल को बढ़ावा दिया गया है।





Ques: According to the World Intellectual Property Organization (WIPO), what was India's global rank in Research & Development (R&D) spending in 2024?

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के अनुसार, 2024 में अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी?

- A) 7th
- B) 6th
- C) 5th
- D) 8th
- E) 10th

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- According to the latest data released by World Intellectual Property Organization (WIPO) under the Global Innovation Index (GII) 2025, India ranked 7th globally in Research & Development (R&D) expenditure in 2024.
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 के तहत WIPO द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय में भारत का वैश्विक स्तर पर 7वाँ स्थान रहा।
- China topped the global R&D spending rankings in 2024.
- 2024 में वैश्विक R&D व्यय रैंकिंग में चीन शीर्ष स्थान पर रहा।
- Total global R&D spending in 2024 stood at USD 2.87 trillion, up from USD 2.78 trillion in 2023, registering around 3% year-on-year growth.
- 2024 में कुल वैश्विक R&D व्यय USD 2.87 ट्रिलियन रहा, जो 2023 के USD 2.78 ट्रिलियन से अधिक है, लगभग 3% वार्षिक वृद्धि के साथ।
- R&D expenditure as a share of global GDP increased from about 1.48% in 2000 to nearly 2% in 2024, highlighting a growing global focus on innovation-led growth.
- वैश्विक GDP में R&D का हिस्सा 2000 में लगभग 1.48% से बढ़कर 2024 में लगभग 2% हो गया, जो नवाचार-आधारित विकास पर बढ़ते वैश्विक जोर को दर्शाता है।

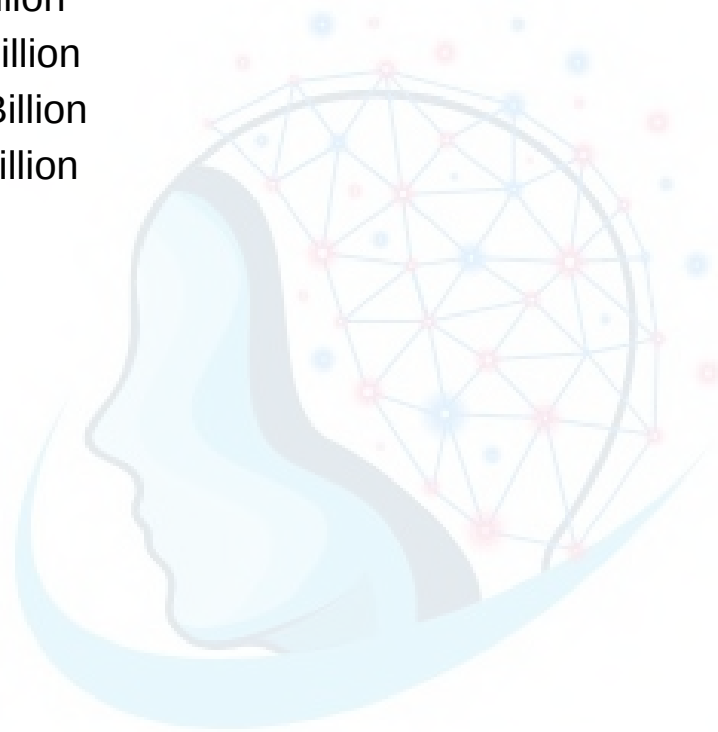
Ranking of Different countries with their spending :

1 China – 785.9 USD Billion





- 2 United states – 781.8 USD Billion
- 3 Japan - 186 USD Billion
- 4 Germany – 132.2 USD Billion
- 5 South Korea – 126.4 USD Billion
- 6 United Kingdom - 86.5 USD Billion
- 7 India – 75.73 USD Billion
- 8 France – 65.8 USD Billion
- 9 Turkiye – 43.2 USD Billion
- 10 Brazil – 38.4 USD Billion



EXAM
Genius





Ques: What is the new loan target under the Agriculture Infrastructure Fund (AIF)?

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत नया ऋण लक्ष्य क्या है?

- A) ₹1.5 lakh crore / ₹1.5 लाख करोड़
- B) ₹2 lakh crore / ₹2 लाख करोड़
- C) ₹3 lakh crore / ₹3 लाख करोड़
- D) ₹50,000 crore / ₹50,000 करोड़
- E) ₹75,000 crore / ₹75,000 करोड़

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

• On the first day after shifting to Seva Teerth, Narendra Modi approved several major welfare and growth-oriented proposals reflecting the spirit of Seva for farmers, women, youth, and vulnerable citizens.

• सेवा तीर्थ में स्थानांतरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के हित में कई बड़े जनकल्याण और विकास से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी।

Key Decisions Approved | प्रमुख निर्णय:

• PM RAHAT Scheme : Accident victims will receive cashless treatment up to ₹1.5 lakh, ensuring no life is lost due to lack of funds during emergencies.

• PM राहत योजना: दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा, ताकि पैसों की कमी के कारण किसी की जान न जाए।

• Lakhpati Didi Initiative : The government has already crossed 3 crore Lakhpati Didis, ahead of the March 2027 target, and has now set a new target of 6 crore by March 2029, focusing on women empowerment through SHGs and livelihood generation.

• लखपति दीदी पहल: सरकार ने मार्च 2027 से पहले ही 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ का नया लक्ष्य तय किया गया है।

• Agriculture Infrastructure Fund (AIF) : The loan target under AIF has been doubled from ₹1 lakh crore to ₹2 lakh crore to strengthen post-harvest infrastructure, storage, logistics, and the agricultural value chain.

• कृषि अवसंरचना कोष (AIF): AIF के तहत ऋण लक्ष्य को ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिससे भंडारण, लॉजिस्टिक्स और कृषि मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी।





Ques: Which state recorded its highest marine dolphin population in five years with 765 dolphins counted in the 2026 census?

किस राज्य ने 2026 की जनगणना में 765 डॉल्फिन के साथ पिछले पाँच वर्षों की सबसे अधिक समुद्री डॉल्फिन संख्या दर्ज की?

- A) West Bengal / पश्चिम बंगाल
- B) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
- C) Gujarat / गुजरात
- D) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- E) Odisha / ओडिशा

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Odisha recorded its highest marine dolphin population in the last five years, with 765 dolphins counted in the 2026 state-wide census.
- ओडिशा ने 2026 की राज्य-स्तरीय जनगणना में 765 डॉल्फिन के साथ पिछले पाँच वर्षों की सबसे अधिक समुद्री डॉल्फिन आबादी दर्ज की।
- The Irrawaddy Dolphin is classified as Endangered on the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.
- इरावदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
- Dolphins are protected under Schedule I of the Wildlife Protection Act, 1972, providing them the highest level of legal protection in India.
- डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षण प्राप्त है, जो भारत में सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- Marine species found along the Odisha coast include Humpback Dolphin, Irrawaddy Dolphin, Bottlenose Dolphin, Spinner Dolphin, and Finless Porpoise (a closely related cetacean).
- ओडिशा तट पर पाई जाने वाली प्रजातियों में हंपबैक डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, बॉटलनोज़ डॉल्फिन, स्पिनर डॉल्फिन और फ़िनलेस पॉरपॉइज़ शामिल हैं।





Ques: Sarita Yolmo has been assigned 'tour duty' on which UNESCO World Heritage Site narrow-gauge railway line in India?

सरिता योल्मो को भारत की किस यूनेस्को विश्व धरोहर संकीर्ण-गेज रेलवे लाइन पर 'टूर ड्यूटी' सौंपी गई है?

- A) Nilgiri Mountain Railway / नीलगिरि पर्वतीय रेलवे
- B) Kalka–Shimla Railway / कालका–शिमला रेलवे
- C) Matheran Hill Railway / माथेरान हिल रेलवे
- D) Darjeeling Himalayan Railway / दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे
- E) Kangra Valley Railway / कांगड़ा घाटी रेलवे

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Sarita Yolmo has been assigned tour duty on the Darjeeling Himalayan Railway (DHR), a narrow-gauge railway line linking New Jalpaiguri and Darjeeling in West Bengal.
- सरिता योल्मो को पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग को जोड़ने वाली दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) पर टूर ड्यूटी सौंपी गई है।
- The Darjeeling Himalayan Railway was built during the British era between 1879 and 1881 and is located in the foothills of the Himalayas in West Bengal.
- दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का निर्माण ब्रिटिश काल में 1879 से 1881 के बीच हुआ था और यह पश्चिम बंगाल में हिमालय की तलहटी में स्थित है।
- It was declared a World Heritage Site by UNESCO in 1999.
- इसे वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
- Other Indian mountain railways declared as UNESCO World Heritage Sites include the Nilgiri Mountain Railway in Tamil Nadu (2005) and the Kalka–Shimla Railway in Himachal Pradesh (2008).
- भारत की अन्य पर्वतीय रेलमार्ग जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं, उनमें तमिलनाडु की नीलगिरि पर्वतीय रेलवे (2005) और हिमाचल प्रदेश की कालका–शिमला रेलवे (2008) शामिल हैं।





Ques: The BAPS Hindu Mandir, the first traditional stone Hindu temple in West Asia, is located in which city?

पश्चिम एशिया का पहला पारंपरिक पत्थर से बना हिंदू मंदिर किस शहर में स्थित है?

- A) Abu Dhabi / अबू धाबी
- B) Doha / दोहा
- C) Dubai / दुबई
- D) Muscat / मस्कट
- E) Riyadh / रियाद

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi completed its second anniversary on February 14.
- अबू धाबी स्थित BAPS हिंदू मंदिर ने 14 फरवरी को अपनी दूसरी वर्षगांठ पूरी की।
- The temple was inaugurated in February 2024 by Prime Minister Narendra Modi.
- मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
- It is the first traditional stone Hindu temple in West Asia, built entirely of stone without using steel in the superstructure.
- यह पश्चिम एशिया का पहला पारंपरिक पत्थर से बना हिंदू मंदिर है, जिसकी ऊपरी संरचना में स्टील का उपयोग नहीं किया गया है।
- The temple is constructed using pink sandstone from Rajasthan and Italian marble, with intricate carvings done by thousands of artisans following traditional temple architecture.
- मंदिर के निर्माण में राजस्थान का गुलाबी बलुआ पत्थर और इटालियन मार्बल का उपयोग किया गया है, जिसे हजारों कारीगरों ने पारंपरिक वास्तुकला के अनुसार तराशा।
- The BAPS Hindu Mandir has emerged as a major centre for worship, cultural exchange, and interfaith harmony in the UAE, reinforcing Abu Dhabi's image as a global hub of cultural tolerance and interfaith dialogue.
- यह मंदिर UAE में पूजा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतरधार्मिक सद्भाव का प्रमुख केंद्र बन गया है और अबू धाबी की सांस्कृतिक सहिष्णुता की वैश्विक पहचान को मजबूत करता है।





Ques: Which task force has been assumed by the Indian Navy under the Combined Maritime Forces (CMF)?

भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री बल (CMF) के अंतर्गत किस टास्क फोर्स की कमान संभाली है?

- A) Combined Task Force 150 / संयुक्त टास्क फोर्स 150
- B) Combined Task Force 151 / संयुक्त टास्क फोर्स 151
- C) Combined Task Force 152 / संयुक्त टास्क फोर्स 152
- D) Combined Task Force 154 / संयुक्त टास्क फोर्स 154
- E) Combined Task Force 159 / संयुक्त टास्क फोर्स 159

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Indian Navy has assumed command of Combined Task Force 154 (CTF-154), a multinational training task force under the Combined Maritime Forces (CMF).
- भारतीय नौसेना ने संयुक्त समुद्री बल (CMF) के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण टास्क फोर्स संयुक्त टास्क फोर्स 154 (CTF-154) की कमान संभाली है।
- Commodore Milind M. Mokashi, Shaurya Chakra, formally took over as Commander of CTF-154.
- शौर्य चक्र से सम्मानित कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी ने औपचारिक रूप से CTF-154 के कमांडर का कार्यभार संभाला।
- He succeeded the outgoing Commander from the Italian Navy.
- उन्होंने इतालवी नौसेना के निवर्तमान कमांडर का स्थान लिया।
- The change of command ceremony was held at CMF Headquarters in Manama, Bahrain.
- कमान परिवर्तन समारोह सीएमएफ मुख्यालय, मनामा, बहरीन में आयोजित किया गया।
- The ceremony was presided over by Vice Admiral Tarun Sobti, Deputy Chief of Naval Staff (India), and Vice Admiral Curt A. Renshaw, Commander, US Naval Forces Central Command.
- इस समारोह की अध्यक्षता उप नौसेना प्रमुख (भारत) वाइस एडमिरल तरुण सोबती तथा यूएस नेवल फोर्स जेंट्रल कमांड के कमांडर वाइस एडमिरल कर्ट ए. रेंशॉ ने की।
- CTF-154 is a dedicated training and capacity-building task force focused on maritime security training, interoperability, and enhancing naval capabilities of member nations.





Ques: Under IN-SPACe's Satellite Bus as a Service (SBaaS) initiative, how many Indian private startups were selected in February 2026 to develop indigenous small satellite bus platforms?

IN-SPACe की सैटेलाइट बस ऐज़ अ सर्विस (SBaaS) पहल के तहत फरवरी 2026 में स्वदेशी स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कितने भारतीय निजी स्टार्टअप्स का चयन किया गया?

- A) Two / दो
- B) Three / तीन
- C) Four / चार
- D) Five / पाँच
- E) Six / छह

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- In February 2026, IN-SPACe, the commercial and regulatory arm of Indian Space Research Organisation (ISRO), selected three Indian private startups under the Satellite Bus as a Service (SBaaS) initiative.
- फरवरी 2026 में, ISRO की वाणिज्यिक और नियामक शाखा IN-SPACe ने SBaaS पहल के तहत तीन भारतीय निजी स्टार्टअप्स का चयन किया।
- The selected startups are Astrome Technologies Private Limited, Azista Industries Private Limited, and Dhruva Space Private Limited.
- चयनित स्टार्टअप्स हैं: Astrome Technologies Private Limited, Azista Industries Private Limited और Dhruva Space Private Limited।
- Each selected company will receive a grant of ₹5 crore.
- प्रत्येक चयनित कंपनी को ₹5 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- The objective of the SBaaS initiative is the development, testing, and demonstration of robust indigenous small satellite bus platforms.
- SBaaS पहल का उद्देश्य मजबूत स्वदेशी स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करना है।





Ques: Which body cleared the ₹92,000-crore Great Nicobar Island mega infrastructure project?

₹92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को किस संस्था ने मंजूरी दी?

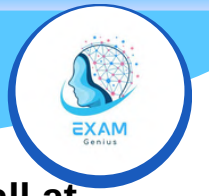
- A) Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय
- B) Ministry of Environment / पर्यावरण मंत्रालय
- C) National Green Tribunal (NGT) / नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Cabinet Committee on Economic Affairs / आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Green Tribunal cleared the ₹92,000-crore Great Nicobar Island mega infrastructure project.
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने ₹92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
- NGT stated that it found “no good ground to interfere” with the 2022 Environmental Clearance (EC).
- NGT ने कहा कि 2022 की पर्यावरण मंजूरी (EC) में हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं है।
- The tribunal noted that adequate environmental safeguards were included and upheld the review of a High-Powered Committee (HPC).
- ट्रिब्यूनल ने कहा कि पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं और हाई-पावर्ड कमेटी (HPC) की समीक्षा को बरकरार रखा।
- The project includes a transshipment port, airport, power plant and township, with directions to protect coral reefs, turtle nesting sites, and prevent shoreline erosion.
- परियोजना में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा, पावर प्लांट और टाउनशिप शामिल हैं, साथ ही कोरल रीफ, कछुओं के nesting sites की सुरक्षा और तटीय क्षरण रोकने के निर्देश दिए गए हैं।





Ques: Which country was affected by Cyclone Gezani, making landfall at Toamasina on its eastern coast?

चक्रवात गेज़ानी किस देश को प्रभावित करते हुए उसके पूर्वी तट पर टोमासिना में टकराया?

- A) Mozambique / मोज़ाम्बिक
- B) Madagascar / मेडागास्कर
- C) Tanzania / तंज़ानिया
- D) Seychelles / सेशेल्स
- E) Comoros / कोमोरोस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Cyclone Gezani struck Madagascar, impacting the eastern coastal regions.
- चक्रवात गेज़ानी ने मेडागास्कर को प्रभावित किया, विशेष रूप से पूर्वी तटीय क्षेत्रों को।
- The cyclone made landfall at Toamasina on Madagascar's eastern coast.
- इस चक्रवात ने मेडागास्कर के पूर्वी तट पर स्थित टोमासिना में लैंडफॉल किया।
- Wind speeds exceeded 195 km/h, causing significant damage.
- हवा की गति 195 किमी/घंटा से अधिक रही, जिससे भारी नुकसान हुआ।
- More than 2,700 people were displaced due to the cyclone.
- चक्रवात के कारण 2,700 से अधिक लोग विस्थापित हुए।





Ques: India's first government-supported national biobank has been established to focus on which category of rare diseases?

भारत का पहला सरकारी समर्थित राष्ट्रीय बायोबैंक किस प्रकार की दुर्लभ बीमारियों पर केंद्रित है?

- A) Autoimmune disorders / ऑटोइम्यून रोग
- B) Mitochondrial diseases / माइटोकॉन्ड्रियल रोग
- C) Neuromuscular disorders / न्यूरोमस्क्युलर रोग
- D) Blood coagulation disorders / रक्त के थक्के बनने से संबंधित रोग
- E) Lysosomal Storage Disorders (LSDs) / लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Researchers from 28 medical and research institutions across six states and two Union Territories have established India's first national biobank dedicated to Lysosomal Storage Disorders (LSDs).
- छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 28 चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ताओं ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSDs) के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया है।
- The initiative is funded by the Department of Biotechnology (DBT).
- इस पहल को जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- The biobank integrates biological samples and detailed clinical, biochemical, and genetic data of 530 patients from 15 states.
- यह बायोबैंक 15 राज्यों के 530 रोगियों के जैविक नमूनों तथा विस्तृत नैदानिक, जैव-रासायनिक और आनुवंशिक आंकड़ों को एकीकृत करता है।
- The lead institution is the Foundation for Research in Genetics and Endocrinology (FRIGE) and the Institute of Human Genetics, Ahmedabad.
- इस बायोबैंक का प्रमुख संस्थान फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी (FRIGE) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, अहमदाबाद है।
- The biobank covers 8 LSD subgroups and 27 disorders, with samples such as genomic DNA, plasma, and urine precipitate processed for enzyme and genetic analysis.
- यह बायोबैंक 8 LSD उपसमूहों और 27 विकारों को कवर करता है, जिसमें जीनोमिक डीएनए, प्लाज़्मा और मूत्र अवक्षेप जैसे नमूनों का एंज़ाइम एवं आनुवंशिक विश्लेषण किया जाता है।





Ques: The Ministry of Earth Sciences (MoES) signed a landmark MoU with which State/UT government to promote marine research and Blue Economy initiatives?

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने समुद्री अनुसंधान और ब्लू इकोनॉमी पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Government of Tamil Nadu / तमिलनाडु सरकार
- B) Government of Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश सरकार
- C) Government of Gujarat / गुजरात सरकार
- D) Government of Puducherry / पुडुचेरी सरकार
- E) Government of Kerala / केरल सरकार

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Earth Sciences (MoES), Government of India, signed a landmark MoU with the Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry.
- भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने पुडुचेरी सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- The MoU aims to promote marine research, infrastructure development, and Blue Economy initiatives.
- इस MoU का उद्देश्य समुद्री अनुसंधान, अवसंरचना विकास और ब्लू इकोनॉमी पहलों को बढ़ावा देना है।
- The agreement covers six strategic domains for sustainable coastal development.
- यह समझौता सतत तटीय विकास के लिए छह रणनीतिक क्षेत्रों को कवर करता है।
- These include sustainable marine fisheries, offshore wind energy, desalination technologies, ocean climate advisory and real-time monitoring, permanent coastal management, and marine spatial planning (MSP).
- इनमें सतत समुद्री मत्स्य पालन, अपतटीय पवन ऊर्जा, विलवणीकरण तकनीक, महासागर जलवायु परामर्श एवं रियल-टाइम निगरानी, स्थायी तटीय प्रबंधन तथा समुद्री स्थानिक योजना (MSP) शामिल हैं।
- The implementation framework includes designation of nodal officers by both sides and formation of Joint Working Groups (JWGs).
- कार्यान्वयन ढांचे में दोनों पक्षों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और संयुक्त कार्य समूहों (JWGs) का गठन शामिल है।





Ques: What is the total Central Assistance allocated under the Urban Challenge Fund (UCF)?

अर्बन चैलेंज फंड (UCF) के तहत कुल केंद्रीय सहायता कितनी है?

- A) ₹50,000 crore / ₹50,000 करोड़
- B) ₹75,000 crore / ₹75,000 करोड़
- C) ₹1 lakh crore / ₹1 लाख करोड़
- D) ₹2 lakh crore / ₹2 लाख करोड़
- E) ₹4 lakh crore / ₹4 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Union Cabinet, chaired by Narendra Modi, approved the launch of the Urban Challenge Fund (UCF) to accelerate market-linked and reform-driven urban infrastructure development.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी अवसंरचना विकास को गति देने के लिए अर्बन चैलेंज फंड (UCF) को मंजूरी दी।
- The total Central Assistance (CA) under UCF is ₹1 lakh crore, which will act as a catalytic fund to leverage private and market-based financing.
- UCF के तहत कुल केंद्रीय सहायता ₹1 लाख करोड़ निर्धारित की गई है, जो बाजार और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- The Central Assistance will cover 25% of the project cost, provided that at least 50% of the funding is raised from market sources such as bonds, PPPs, or private investments.
- केंद्रीय सहायता परियोजना लागत का 25% होगी, बशर्ते कम-से-कम 50% धन बाजार स्रोतों से जुटाया जाए।
- The fund is expected to mobilize a total investment of ₹4 lakh crore in the urban sector over the next five years.
- अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में ₹4 लाख करोड़ के कुल निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है।
- The operational period of the Urban Challenge Fund is from FY 2025–26 to FY 2030–31, with the implementation period extendable up to FY 2033–34.
- UCF की संचालन अवधि FY 2025–26 से 2030–31 तक होगी, जबकि कार्यान्वयन अवधि FY 2033–





Ques: What was the year-on-year (YoY) growth in Currency in Circulation (CiC) in January 2026?

जनवरी 2026 में प्रचलन में मुद्रा (CiC) की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि कितनी रही?

- A) 5.3%
- B) 8.5%
- C) 9.7%
- D) 11.1%
- E) 14.4%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या :

- Currency in Circulation (CiC) touched a record high of ₹40 lakh crore for the month ending January 2026.
- जनवरी 2026 को समाप्त माह में प्रचलन में मुद्रा (CiC) ₹40 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई।
- CiC registered a year-on-year growth of 11.1%, significantly higher than 5.3% recorded in January last year.
- CiC में 11.1% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह यह 5.3% थी।
- On a year-to-date (YTD) basis, CiC increased by ₹2.76 lakh crore, which is about 3.11 times higher than the increase during the same period last year.
- वर्ष-से-तारीख (YTD) आधार पर CiC में ₹2.76 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 3.11 गुना अधिक है।
- Despite the rise in cash usage, the cash-to-GDP ratio declined to 11% in FY26 (so far), compared to 14.4% in FY21, indicating deeper financialisation and digital payments penetration.
- नकदी प्रचलन बढ़ने के बावजूद, FY26 (अब तक) में नकद-से-GDP अनुपात घटकर 11% रह गया, जो FY21 में 14.4% था।
- These findings were reported by SBI Research.
- यह आँकड़े SBI Research द्वारा जारी किए गए हैं।





Ques: Who released the latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 (July–September 2025)? Q2 FY 2025–26 (जुलाई–सितंबर 2025) के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया?

- A) Amitabh Kant / अमिताभ कांत
- B) Rajiv Kumar / राजीव कुमार
- C) Suman Bery / सुमन बेरी
- D) Sanjeev Sanyal / संजीव सान्याल
- E) Arvind Panagariya / अरविंद पनगढ़िया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The latest edition of “Trade Watch Quarterly” for Q2 FY 2025–26 was released by Suman Bery, Vice-Chairman of NITI Aayog.
- Q2 FY 2025–26 के लिए “ट्रेड वॉच क्वार्टरली” का नवीनतम संस्करण नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी किया गया।
- The report notes that global trade growth has moderated but remains positive, with services trade outperforming goods trade.
- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन सकारात्मक बनी हुई है, जहाँ सेवा व्यापार वस्तु व्यापार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- India's trade expansion in Q2 FY26 was driven by export-led momentum, with services and merchandise exports growing by around 8.5%, faster than imports.
- Q2 FY26 में भारत का व्यापार विस्तार निर्यात-आधारित गति से संचालित रहा, जहाँ सेवा और वस्तु निर्यात लगभग 8.5% बढ़े, जो आयात वृद्धि से अधिक था।
- The report highlights India's increasing alignment with regional value chains and new trade corridors.
- रिपोर्ट में क्षेत्रीय वैल्यू चेन और नए व्यापार गलियारों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है।
- E-commerce exports, though currently modest, are projected to contribute 20–30% of India's merchandise exports by 2030.
- ई-कॉमर्स निर्यात वर्तमान में सीमित हैं, लेकिन 2030 तक भारत के वस्तु निर्यात में 20–30% योगदान देने का अनुमान है।





Ques: NPCI extended the 'UPI One World' wallet service for international visitors attending which event?

NPCI ने 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए किया?

- A) G20 Summit 2026 / G20 शिखर सम्मेलन 2026
- B) India AI Impact Summit 2026 / इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026
- C) Digital India Conference 2026 / डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2026
- D) Vibrant Gujarat Summit 2026 / वाइब्रेंट गुजरात समिट 2026
- E) World Economic Forum 2026 / वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- National Payments Corporation of India (NPCI) has extended the 'UPI One World' wallet service for international visitors from 40+ countries.
- National Payments Corporation of India (NPCI) ने 40 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए 'UPI One World' वॉलेट सेवा का विस्तार किया है।
- This facility is specifically available for attendees of the India AI Impact Summit 2026, held from 16–20 February 2026 in New Delhi.
- यह सुविधा 16–20 फरवरी 2026 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में भाग लेने वाले आगंतुकों के लिए उपलब्ध है।
- Under this pilot initiative, foreign travellers can make seamless, secure, real-time Person-to-Merchant (P2M) payments using UPI while staying in India.
- इस पायलट पहल के तहत विदेशी यात्री भारत में रहते हुए सहज, सुरक्षित और रियल-टाइम Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान कर सकते हैं।
- The initiative aims to promote digital payments, showcase India's fintech leadership, and enhance convenience for inbound tourists and global delegates.
- इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, भारत की फिनटेक क्षमता को प्रदर्शित करना और विदेशी पर्यटकों व वैश्विक प्रतिनिधियों की सुविधा बढ़ाना है।





Ques: Which company received full WHO approval for the polio vaccine nOPV2?
किस कंपनी को पोलियो वैक्सीन nOPV2 के लिए WHO की पूर्ण मंजूरी मिली?

- A) Serum Institute of India / सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
- B) Bharat Biotech / भारत बायोटेक
- C) Biological E Ltd / बायोलॉजिकल ई लिमिटेड
- D) Zydus Lifesciences / ज़ायडस लाइफसाइंसेज़
- E) Panacea Biotech / पैनासिया बायोटेक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Biological E Ltd, a Hyderabad-based company, received full approval from the World Health Organization for its novel oral polio vaccine type-2 (nOPV2).
- हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को अपने नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप-2 (nOPV2) के लिए WHO की पूर्ण मंजूरी प्राप्त हुई।
- This approval upgrades the Phase-I clearance granted in June 2024, enabling complete regulatory authorization.
- यह मंजूरी जून 2024 में मिली चरण-I स्वीकृति का उन्नत चरण है।
- With this approval, the company can now manufacture both the drug substance and the final drug product in-house, completing the entire manufacturing chain at a single site.
- अब कंपनी एक ही स्थान पर दवा पदार्थ और अंतिम उत्पाद दोनों का निर्माण कर सकती है, जिससे पूरी निर्माण श्रृंखला पूरी होती है।
- Biological E has already supplied over 700 million doses of nOPV2 globally, supporting polio outbreak response worldwide.
- बायोलॉजिकल ई अब तक वैश्विक स्तर पर 700 मिलियन से अधिक nOPV2 डोज़ की आपूर्ति कर चुकी है।
- nOPV2 is specifically designed for outbreak control of circulating vaccine-derived poliovirus, offering improved genetic stability compared to earlier vaccines.
- nOPV2 को वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस के प्रकोप नियंत्रण के लिए बेहतर आनुवंशिक स्थिरता के साथ विकसित किया गया है।





Ques: Why is the Ministry of Defence drafting a standardized framework for book-writing by serving and retired Armed Forces personnel?

रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुस्तक-लेखन हेतु एक मानकीकृत ढांचा क्यों तैयार कर रहा है?

- A) To promote military literature / सैन्य साहित्य को बढ़ावा देने के लिए
- B) To provide financial incentives for veterans / पूर्व सैनिकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए
- C) To address regulatory gaps and national security concerns / नियामकीय खामियों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए
- D) To ban all memoirs by retired officers / सेवानिवृत्त अधिकारियों की सभी आत्मकथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए
- E) To align with international military publishing norms / अंतरराष्ट्रीय सैन्य प्रकाशन मानकों के अनुरूप होने के लिए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Ministry of Defence is drafting a standardized framework for both serving and retired Armed Forces personnel to bridge existing regulatory gaps related to writing and publishing books.
- रक्षा मंत्रालय सेवारत एवं सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों के लिए पुस्तक-लेखन से जुड़े नियामकीय अंतर को पाटने हेतु एक मानकीकृत ढांचा तैयार कर रहा है।
- The move gained attention due to controversy surrounding the unpublished memoir Four Stars of Destiny by former Army Chief Gen. M.M. Naravane (Retd.).
- यह मुद्दा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे (सेवानिवृत्त) की अप्रकाशित आत्मकथा Four Stars of Destiny से जुड़े विवाद के बाद चर्चा में आया।

Legal Grey Area for Retirees | सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कानूनी अस्पष्टता

- Unlike serving officers, retired Army personnel are not governed by a single consolidated law for literary works.
- सेवारत अधिकारियों के विपरीत, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए पुस्तक-लेखन पर कोई एकीकृत कानून नहीं है।





- After retirement, they are not strictly bound by the Army Act, 1950 and Army Rules, 1954 for publications.
- सेवानिवृत्ति के बाद वे आर्मी एक्ट, 1950 और आर्मी रूल्स, 1954 के प्रकाशन संबंधी प्रावधानों से सीधे बंधे नहीं रहते।
- However, the Official Secrets Act (OSA), 1923 applies for life, making disclosure of classified or security-sensitive information a criminal offence.
- हालांकि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (OSA) आजीवन लागू रहता है, जिसके तहत गोपनीय या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का खुलासा अपराध है।

Existing Rules for Serving Personnel | सेवारत कर्मियों के लिए नियम

- Serving officers require mandatory prior written permission for any literary or remunerative work.
- सेवारत अधिकारियों को किसी भी साहित्यिक या पारिश्रमिक कार्य के लिए पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होती है।
- Manuscripts undergo a vetting process through the chain of command, up to Army Headquarters or the MoD.
- पांडुलिपियों की कमांड चैन के माध्यम से जांच होती है, जो सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय तक जाती है।

Precedent from Civil Services | सिविल सेवा से उदाहरण

- The proposal is inspired by the Central Civil Services (Pension) Rules Amendment, 2021.
- यह प्रस्ताव केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम संशोधन, 2021 से प्रेरित है।
- Under this amendment, retired officials from intelligence or security agencies like RAW or IB must obtain prior government clearance before publishing sensitive material.
- इस संशोधन के तहत RAW या IB जैसी खुफिया एजेंसियों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होती है।
- Unauthorized disclosure can lead to withholding or withdrawal of pension as a penalty.
- अनधिकृत खुलासे पर पेंशन रोके जाने या वापस लेने का प्रावधान है।





Ques: Which two institutions signed an MoU to promote science communication and evidence-based science policy research in India?

भारत में विज्ञान संचार और साक्ष्य-आधारित विज्ञान नीति अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) CSIR & NITI Aayog / सीएसआईआर और नीति आयोग
- B) DST & ICMR / डीएसटी और आईसीएमआर
- C) Indian National Science Academy & National Institute of Science Communication and Policy Research / भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान
- D) DBT & AIIMS / डीबीटी और एम्स
- E) UGC & NCERT / यूजीसी और एनसीईआरटी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Indian National Science Academy and National Institute of Science Communication and Policy Research signed a Memorandum of Understanding (MoU) to promote collaborative activities in science communication and evidence-based science policy research.
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने विज्ञान संचार और साक्ष्य-आधारित विज्ञान नीति अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए।
- The partnership aims to strengthen evidence-based policymaking in India by connecting scientific research with policy formulation.
- यह साझेदारी भारत में साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है।
- The Union Budget (February 2026) allocated approximately ₹6,710.61 crore to CSIR, supporting operational costs for institutes like NIScPR to undertake such collaborations.
- फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में CSIR को लगभग ₹6,710.61 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे NIScPR जैसे संस्थानों को इस प्रकार की साझेदारियाँ करने में सहायता मिलेगी।

About Indian National Science Academy (INSA) :



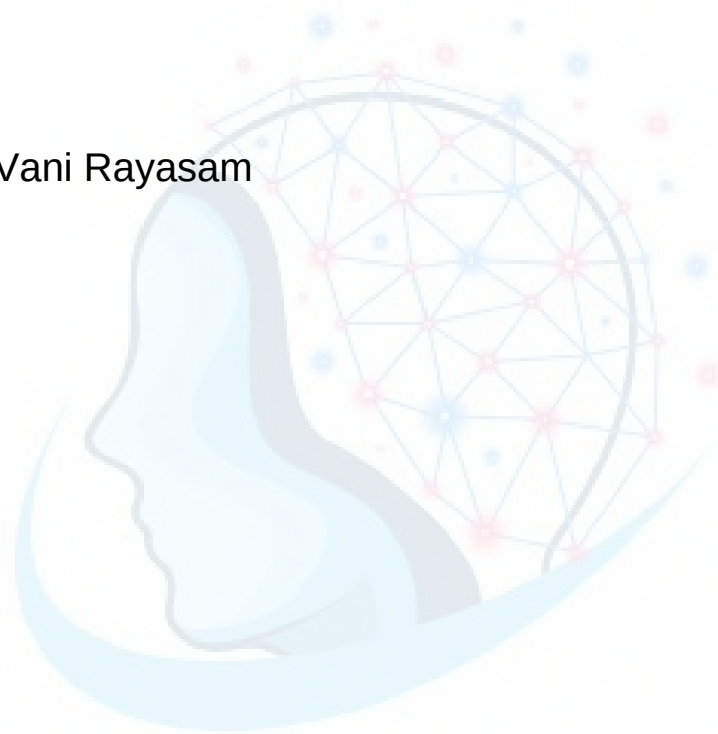


hed : 1935

- HQ : New Delhi
- President : Prof. Shekhar C. Mande

About CSIR-National Institute of Science Communication and Policy Research (NIScPR) :

- Established : 2021
- HQ : New Delhi
- Director : Dr. Geetha Vani Rayasam



EXAM
Genius





Ques: What was a key outcome of the recent India–France bilateral meeting?

हालिया भारत–फ्रांस द्विपक्षीय बैठक का एक प्रमुख परिणाम क्या था?

- A) Signing of a new climate treaty / नए जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर
B) Amendment of the Double Taxation Avoidance Agreement and launch of 'Year of Innovation' /
दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन और 'Year of Innovation' की शुरुआत
C) Launch of a joint space mission / संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत
D) Establishment of a common currency / साझा मुद्रा की स्थापना
E) Withdrawal from defence cooperation / रक्षा सहयोग से हटना

Answer: Option B

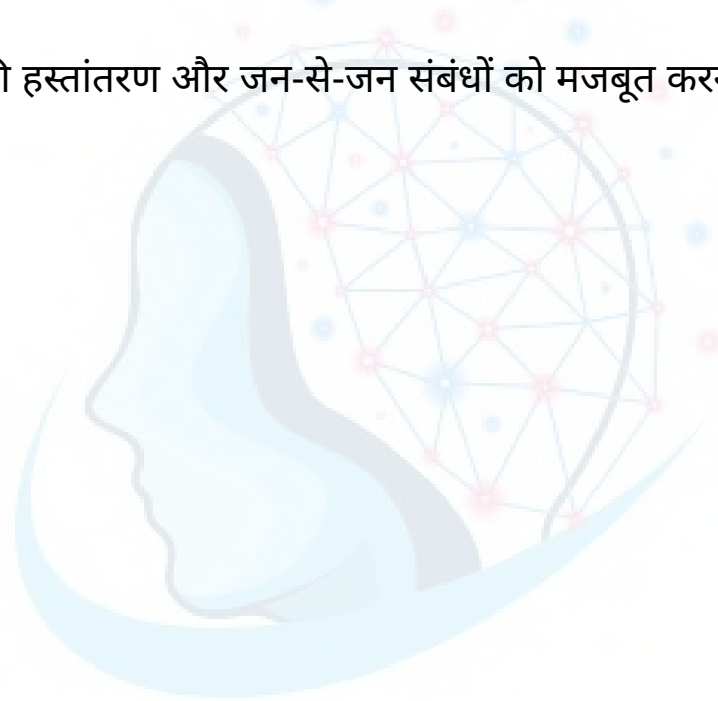
Explanation / व्याख्या :

- India and France amended the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) to boost bilateral trade and investments.
- भारत और फ्रांस ने व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए DTAA में संशोधन किया।
- Narendra Modi and Emmanuel Macron launched the 'India–France Year of Innovation'.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 'भारत–फ्रांस नवाचार वर्ष' की शुरुआत की।
- The initiative will focus on Artificial Intelligence (AI), digital technologies, and start-ups.
- यह पहल AI, डिजिटल तकनीकों और स्टार्ट-अप्स पर केंद्रित होगी।
- Both leaders virtually inaugurated the Tata–Airbus H125 helicopter final assembly line in Karnataka.
- दोनों नेताओं ने कर्नाटक में टाटा–एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- Multiple agreements were signed covering defence, civil nuclear cooperation, critical minerals, health, and counter-terrorism.
- रक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य और आतंकवाद-रोधी सहयोग सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
- A joint venture between Bharat Electronics Ltd and Safran for HAMMER missile production was announced.





- BEL और Safran के बीच HAMMER मिसाइल उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई।
- New initiatives include an Indo-French Centre for AI (Health), a Centre of Digital Science & Technology, and a National Centre of Excellence for Skilling in Aeronautics.
- नई पहलों में AI (स्वास्थ्य) के लिए इंडो-फ्रेंच केंद्र, डिजिटल साइंस एवं टेक्नोलॉजी केंद्र, और एरोनॉटिक्स में स्किलिंग हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं।
- France reiterated support for technology transfer to India and for strengthening people-to-people ties.
- फ्रांस ने भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जन-से-जन संबंधों को मजबूत करने के समर्थन को दोहराया।



EXAM
Genius





Ques: According to the report analysing India's electricity transition under the Current Policy Scenario (CPS) and Net Zero Scenario (NZS), what share of final energy consumption is projected to come from electricity under the NZS by 2070?

CPS और NZS (2070 नेट ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप) के तहत भारत के बिजली संक्रमण का विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट के अनुसार, 2070 तक NZS में अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी कितनी होने का अनुमान है?

- A) 30%
- B) 40%
- C) 50%
- D) 60%
- E) 75%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The report analyses India's electricity transition under two scenarios: the Current Policy Scenario (CPS) and the Net Zero Scenario (NZS), aligned with India's 2070 Net Zero commitment.
- रिपोर्ट भारत के बिजली संक्रमण का विश्लेषण दो परिदृश्यों के तहत करती है: करंट पॉलिसी सीनारियो (CPS) और नेट ज़ीरो सीनारियो (NZS), जो भारत के 2070 नेट ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप है।
- The power sector accounted for 39.4% of India's total greenhouse gas (GHG) emissions in 2020, making it the single largest source of emissions.
- वर्ष 2020 में भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बिजली क्षेत्र की हिस्सेदारी 39.4% थी, जिससे यह सबसे बड़ा उत्सर्जन स्रोत बन गया।
- Under electrification-led demand growth, electricity is expected to become the dominant energy carrier.
- विद्युतीकरण-आधारित मांग वृद्धि के तहत, बिजली के प्रमुख ऊर्जा वाहक बनने की उम्मीद है।
- The share of electricity in final energy consumption is projected at 40% under CPS and 60% under NZS by 2070.
- अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी CPS के तहत 40% और NZS के तहत 2070 तक 60% होने का अनुमान है।





- Total installed power capacity is expected to multiply 9–14 times by 2070, with renewables contributing 90–93% of total capacity, led mainly by solar PV and wind energy.
- 2070 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता के 9–14 गुना बढ़ने की संभावना है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 90–93% होगी, और इसमें सोलर पीवी व पवन ऊर्जा प्रमुख होंगी।
- To support a renewables-heavy grid, strong storage and flexibility measures will be required, including up to 3,000 GW of battery storage and around 160 GW of pumped hydro storage by 2070.
- नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रिड को संतुलित रखने के लिए 2070 तक लगभग 3,000 GW बैटरी स्टोरेज और लगभग 160 GW पम्पड हाइड्रो स्टोरेज की आवश्यकता होगी।
- Nuclear energy is expected to play a key role as firm power, with nuclear capacity projected to rise from 8.8 GW to over 300 GW by 2070.
- परमाणु ऊर्जा को स्थिर (फर्म) बिजली स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसकी क्षमता 8.8 GW से बढ़कर 2070 तक 300 GW से अधिक हो सकती है।

EXAM
Genius





Ques: Who was named BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025?
BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025 के रूप में किसे चुना गया?

- A) Harmanpreet Kaur / हरमनप्रीत कौर
- B) PV Sindhu / पीवी सिंधु
- C) Smriti Mandhana / स्मृति मंधाना
- D) Mirabai Chanu / मीराबाई चानू
- E) Nikhat Zareen / निकहत जरीन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Smriti Mandhana, Vice-Captain of the Indian Women's Cricket Team, was named BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025.
- भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना को BBC Indian Sportswoman of the Year (ISWOTY) 2025 चुना गया।
- The award recognizes outstanding achievements of Indian women athletes across various sports.
- यह पुरस्कार विभिन्न खेलों में भारतीय महिला खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करता है।
- The award ceremony was organized by the BBC to celebrate excellence in Indian women's sports.
- यह पुरस्कार समारोह BBC द्वारा भारतीय महिला खेलों में उत्कृष्टता के सम्मान हेतु आयोजित किया गया।
- Smriti Mandhana is widely known for her consistent performances and significant contributions to Indian women's cricket at the international level.
- स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट में अपने निरंतर प्रदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती हैं।





Ques: The first national call for the BIRAC–RDI Fund was announced under which broader Government of India initiative? BIRAC–RDI फंड के लिए पहली राष्ट्रीय कॉल भारत सरकार की किस व्यापक पहल के अंतर्गत घोषित की गई?

- A) National Biotechnology Development Programme / राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम
- B) Startup India Mission / स्टार्टअप इंडिया मिशन
- C) Research, Development and Innovation (RDI) Initiative / अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) पहल
- D) Digital India Programme / डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- E) Make in India Initiative / मेक इन इंडिया पहल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Union Minister Dr. Jitendra Singh announced the first national call for the BIRAC–RDI Fund under the Government of India's ₹1 lakh crore Research, Development and Innovation (RDI) initiative.
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत सरकार की ₹1 लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) पहल के अंतर्गत BIRAC–RDI फंड के लिए पहली राष्ट्रीय कॉल की घोषणा की।
- The BIRAC–RDI Fund operates under the institutional framework of the Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) and the Anusandhan National Research Foundation (ANRF).
- BIRAC–RDI फंड, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के संस्थागत ढांचे के अंतर्गत संचालित होता है।
- The fund is anchored by the Department of Science and Technology (DST).
- यह फंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा एंकर किया गया है।
- Out of the total ₹1 lakh crore RDI corpus, BIRAC has been allocated ₹2,000 crore initially for up to five years.
- कुल ₹1 लाख करोड़ के RDI कोष में से BIRAC को प्रारंभिक रूप से पाँच वर्षों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- The fund provides support through equity, convertible instruments, and long-term debt.
- यह फंड इक्विटी, परिवर्तनीय उपकरणों और दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।





- It supports innovations from Technology Readiness Level (TRL)-4 (validation stage) to TRL-9 (commercial deployment stage).
- यह फंड प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL)-4 (सत्यापन चरण) से लेकर TRL-9 (व्यावसायिक तैनाती चरण) तक के नवाचारों को समर्थन देता है।
- India's bioeconomy has grown from \$28 billion in 2012 to \$165.7 billion in 2024, with a target of \$300 billion by 2030 and \$1 trillion by 2047.
- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2012 में \$28 बिलियन से बढ़कर 2024 में \$165.7 बिलियन हो गई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक \$300 बिलियन और 2047 तक \$1 ट्रिलियन है।
- The number of biotech startups has increased from around 50 in 2014 to over 11,000 today, indicating rapid ecosystem expansion.
- जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में लगभग 50 से बढ़कर आज 11,000 से अधिक हो गई है, जो तेज़ी से विकसित होते इकोसिस्टम को दर्शाता है।

EXAM
Genius





Ques: What is the primary purpose of Bharat-VISTAAR launched by the Government of India?

भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारत-विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Direct financial subsidies / प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी
- B) AI-based multilingual agricultural information / AI आधारित बहुभाषी कृषि जानकारी
- C) Free farm equipment / मुफ्त कृषि उपकरण
- D) Crop insurance compensation / फसल बीमा मुआवजा
- E) Online market trading platform / ऑनलाइन बाजार व्यापार मंच

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- The Government of India has launched Bharat-VISTAAR (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources), an AI-powered multilingual digital tool designed especially for farmers.
- भारत सरकार ने भारत-विस्तार (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए एक AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल टूल है।
- The platform provides farmers with agricultural and scheme-related information in their own language through mobile phones or even a simple voice call, ensuring inclusivity.
- यह प्लेटफॉर्म किसानों को मोबाइल या साधारण फोन कॉल के माध्यम से उनकी मातृभाषा में कृषि एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- Farmers can access details of 10 major Central Government schemes, including PM-KISAN, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, and Kisan Credit Card (KCC).
- किसान 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं जैसे पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- The interface and audio content of Bharat-VISTAAR will be available in 22 से अधिक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं to bridge the digital and language divide.
- भारत-विस्तार का इंटरफेस और ऑडियो सामग्री 22+ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिससे डिजिटल और भाषाई अंतर कम होगा।
- The initiative was announced in the Union Budget 2026–27 with a dedicated allocation of ₹150 crore, highlighting the government's focus on technology-driven





Ques: Which Indian company received a general licence from the United States government to import Venezuelan crude oil without violating US sanctions?

किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना वेनेजुएला का कच्चा तेल आयात करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से सामान्य लाइसेंस प्राप्त हुआ?

- A) Indian Oil Corporation / इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
- B) ONGC Videsh Limited / ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
- C) Bharat Petroleum Corporation Limited / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- D) Reliance Industries Limited / रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- E) Hindustan Petroleum Corporation Limited / हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Reliance Industries Limited (RIL) received a general licence from the United States government to purchase crude oil from Venezuela.
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने के लिए सामान्य लाइसेंस प्राप्त हुआ।
- This licence allows RIL to directly import Venezuelan crude oil without violating US sanctions.
- यह लाइसेंस रिलायंस को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना सीधे वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने की अनुमति देता है।
- RIL operates the Jamnagar Refinery Complex in Gujarat, which is the world's largest and most complex single-site refinery.
- रिलायंस गुजरात में जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल सिंगल-साइट रिफाइनरी है।
- The Jamnagar refinery has a significant advantage as it is capable of processing heavy crude and high-sulphur (sour) crude oil.
- जामनगर रिफाइनरी की बड़ी विशेषता यह है कि यह भारी कच्चे तेल और उच्च सल्फर (सॉर) कच्चे तेल को भी प्रोसेस करने में सक्षम है।





Ques: Where did six-year-old environmental advocate Roohi Mohazzab deliver her keynote address during GCE 2026?

GCE 2026 के दौरान 6 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता रूही मोहज्ज़ब ने अपना मुख्य भाषण कहाँ दिया?

- A) New York, USA / न्यूयॉर्क, अमेरिका
- B) Geneva, Switzerland / जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- C) Bangkok, Thailand / बैंकॉक, थाईलैंड
- D) Paris, France / पेरिस, फ्रांस
- E) Nairobi, Kenya / नैरोबी, केन्या

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Roohi Mohazzab, a six-year-old environmental advocate from Kerala, delivered a keynote address at the UN Asia-Pacific Headquarters in Bangkok, Thailand.
- केरल की 6 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता रूही मोहज्ज़ब ने बैंकॉक, थाईलैंड स्थित UN एशिया-प्रशांत मुख्यालय में मुख्य भाषण दिया।
- She spoke during the Global Conference on Education for a Sustainable Future (GCE 2026).
- उन्होंने Global Conference on Education for a Sustainable Future (GCE 2026) के दौरान संबोधन दिया।
- Roohi was honoured with the prestigious SDG Impact Award at the UN Asia-Pacific Headquarters.
- रूही को UN एशिया-प्रशांत मुख्यालय में प्रतिष्ठित SDG Impact Award से सम्मानित किया गया।
- Her recognition highlights the importance of young voices in sustainability, climate action, and global awareness.
- उनका यह सम्मान सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक जागरूकता में युवा आवाज़ों की भूमिका को रेखांकित करता है।





Ques: Which Indian Major Port became the first to receive the IGBC Platinum Rating for its Administration Building?

भारत का कौन-सा प्रमुख बंदरगाह अपने प्रशासनिक भवन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बना?

- A) Jawaharlal Nehru Port / जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
- B) Chennai Port / चेन्नई पोर्ट
- C) Paradip Port / पारादीप पोर्ट
- D) V.O. Chidambaranar Port / वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट
- E) Cochin Port / कोचीन पोर्ट

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- V.O. Chidambaranar Port Authority has become India's first Major Port to receive the prestigious IGBC Platinum Rating, the highest certification awarded by the Indian Green Building Council (IGBC).
- वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण IGBC द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है।
- The Administration Building follows the Port Authority's Green Policy and waste management plan, reinforcing its commitment to sustainability.
- प्रशासनिक भवन पोर्ट प्राधिकरण की ग्रीन नीति और अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अनुरूप बनाया गया है, जो सतत विकास को बढ़ावा देता है।
- The building is equipped with rooftop solar panels and a high Solar Reflectance Index (SRI) reflective roof coating, helping reduce the Urban Heat Island effect and improve overall energy efficiency.
- भवन में रूफटॉप सोलर पैनल और उच्च SRI रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग लगाई गई है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कम होता है और ऊर्जा दक्षता बढ़ती है।
- The port has also received Shunya and Shunya Plus certifications from the Bureau of Energy Efficiency (BEE) under the Ministry of Power, Government of India.
- यह बंदरगाह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) से शून्य और शून्य प्लस प्रमाणन भी प्राप्त कर चुका है।





Top 3 Green Award Recipients (2025–2026) | शीर्ष ग्रीन अवॉर्ड प्राप्तकर्ता

- V.O. Chidambaranar Port – IGBC Platinum | Shunya Plus
 - First Major Port in India to run its administration building on 100% renewable energy.
 - प्रशासनिक भवन को 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह।
- Bank of Baroda (Apex Academy) – IGBC Platinum | Shunya
 - Awarded for its state-of-the-art sustainable campus in Ahmedabad (Dec 2025).
 - अहमदाबाद में अत्याधुनिक सतत कैंपस के लिए सम्मानित।
- The Oterra Hotel, Bengaluru – IGBC Platinum | Shunya
 - Recognized as the highest-rated green existing building in India (Jan 2026).
 - भारत की सबसे उच्च रेटिंग वाली ग्रीन मौजूदा इमारत के रूप में मान्यता।

EXAM
Genius





Ques: Who has been sworn in as the new Prime Minister of Bangladesh?

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?

- A) Sheikh Hasina / शेख हसीना
- B) Khaleda Zia / खालिदा जिया
- C) Tarique Rahman / तारीक रहमान
- D) Muhammad Yunus / मोहम्मद यूनुस
- E) Mirza Fakhrul Islam Alamgir / मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- Tarique Rahman, chairman of the Bangladesh Nationalist Party (BNP), was sworn in as the Prime Minister of Bangladesh.
- BNP के अध्यक्ष तारीक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।
- He will head a council of 25 Cabinet Ministers and 24 Ministers of State.
- वे 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों की परिषद का नेतृत्व करेंगे।
- The oath of office was administered by Mohammed Shahabuddin, the President of Bangladesh, in Dhaka.
- शपथ ढाका में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन द्वारा दिलाई गई।
- The ceremony followed the parliamentary elections and the transfer of power from the interim government.
- यह शपथ ग्रहण संसदीय चुनावों और अंतरिम सरकार से सत्ता हस्तांतरण के बाद हुआ।
- Around 1,200 domestic and foreign guests attended, including dignitaries from Maldives, Pakistan, and India.
- समारोह में मालदीव, पाकिस्तान और भारत सहित लगभग 1,200 अतिथि शामिल हुए।





Ques: What is 'EKAM' showcased by the Indian Army?

भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत 'EKAM' क्या है?

- A) A cyber weapon system / साइबर हथियार प्रणाली
- B) A secure indigenous AI cloud platform (AI-as-a-Service) / एक सुरक्षित स्वदेशी AI क्लाउड प्लेटफॉर्म (AI-as-a-Service)
- C) A drone surveillance system / ड्रोन निगरानी प्रणाली
- D) A satellite communication network / उपग्रह संचार नेटवर्क
- E) A blockchain-based defence payment system / ब्लॉकचेन-आधारित रक्षा भुगतान प्रणाली

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Indian Army showcased 'EKAM', an indigenous AI-as-a-Service (AlaaS) cloud platform.
- भारतीय सेना ने 'EKAM' नामक स्वदेशी AI-as-a-Service क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया।
- EKAM is a secure and air-gapped platform, specifically designed to protect sensitive military data.
- EKAM एक सुरक्षित और air-gapped प्लेटफॉर्म है, जिसे संवेदनशील सैन्य डेटा की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है।
- The platform focuses on data sovereignty and secure processing of critical information.
- यह प्लेटफॉर्म डेटा संप्रभुता और महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षित प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- The initiative reflects the Army's push towards technological self-reliance and AI-enabled defence capabilities.
- यह पहल सेना की तकनीकी आत्मनिर्भरता और AI-सक्षम रक्षा क्षमताओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





Ques: The high-level CSR Conclave on “Leveraging PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (DDKY) for Farmer Prosperity” was organised by which department under the Government of India? “किसान समृद्धि के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) का लाभ उठाना” विषय पर उच्च स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव भारत सरकार के किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया?

- A) Department of Rural Development / ग्रामीण विकास विभाग
- B) Department of Agriculture & Farmers Welfare / कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- C) Ministry of Panchayati Raj / पंचायती राज मंत्रालय
- D) Department of Food & Public Distribution / खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
- E) Ministry of Cooperation / सहकारिता मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The high-level CSR Conclave was organised by the Department of Agriculture & Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
- यह उच्च स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया।
- The conclave was held in New Delhi in collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP) and the Bill & Melinda Gates Foundation.
- यह कॉन्क्लेव नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।
- The theme of the conclave was “Leveraging PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (DDKY) for Farmer Prosperity.”
- कॉन्क्लेव का विषय “किसान समृद्धि के लिए पीएम धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) का लाभ उठाना” था।
- PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (DDKY) was launched on 11 October 2025 for a duration of 6 years.
- पीएम धन-धान्य कृषि योजना (DDKY) को 11 अक्टूबर 2025 को 6 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया।
- The scheme covers 100 districts and is India's first agriculture-exclusive programme.
- यह योजना 100 जिलों को कवर करती है और भारत की पहली केवल कृषि-केन्द्रित योजना है।
- The programme is inspired by NITI Aayog's Aspirational District Programme.





Ques: Which flagship scheme primarily funds marine conservation initiatives in India, including artificial reefs and financial support to fishers?

भारत में समुद्री संरक्षण पहलों (कृत्रिम रीफ, मछुआरों को वित्तीय सहायता आदि) को मुख्य रूप से कौन-सी प्रमुख योजना वित्तपोषित करती है?

- A) National Mission for Clean Ganga / राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
- B) Blue Economy Policy / ब्लू इकोनॉमी नीति
- C) Sagarmala Programme / सागरमाला कार्यक्रम
- D) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana / प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
- E) Coastal Regulation Zone Scheme / तटीय विनियमन क्षेत्र योजना

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या :

- To ensure oceans remain rich in biodiversity for future generations, the Government of India along with research bodies like Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) is implementing targeted marine conservation strategies, especially for species such as Silver Pomfret.
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए महासागरों की जैव-विविधता बनाए रखने हेतु भारत सरकार और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) जैसे अनुसंधान संस्थान सिल्वर पॉम्फ्रेट जैसी प्रजातियों पर विशेष ध्यान देते हुए संरक्षण रणनीतियाँ लागू कर रहे हैं।
- To prevent “over-cleaning” and overfishing of oceans, mesh-size regulations are enforced so that nets have sufficiently large holes to allow juvenile fish to escape.
- महासागरों में अत्यधिक मछली पकड़ने से रोकने के लिए जाल के जाल-आकार (Mesh-Size) नियम लागू किए गए हैं, जिससे छोटी मछलियाँ बाहर निकल सकें।
- Certain fishing methods are banned, including:
 - Bull/Pair trawling, to protect the ocean floor.
 - LED lights, as they unnaturally attract fish.
- समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा हेतु कुछ विधियाँ प्रतिबंधित हैं, जैसे:
 - बुल/पेयर ट्रॉलिंग, जिससे समुद्र तल को नुकसान होता है।
 - LED लाइट्स, क्योंकि ये मछलियों को अस्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं।
- As per the Marine Fish Stock Status Report 2022, 91.1% of India’s marine fish stocks are in healthy condition.





- मरीन फिश स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के 91.1% समुद्री मत्स्य भंडार स्वस्थ स्थिति में हैं।
- Funding for conservation initiatives such as artificial reefs and financial aid to fishers is mainly driven by the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, a flagship scheme aimed at transforming India's fisheries sector.
- कृत्रिम रीफ और मछुआरों को वित्तीय सहायता जैसी पहलों का वित्तपोषण मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किया जाता है, जो भारत के मत्स्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की प्रमुख योजना है।
- The Silver Pomfret (*Pampus argenteus*), often called the "King of Fish" in South and Southeast Asia, is nutritionally rich and a key focus of conservation efforts.
- सिल्वर पॉम्फ्रेट (*Pampus argenteus*) को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में "मछलियों का राजा" कहा जाता है और यह पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Marine Conservation Measures | समुद्री संरक्षण उपाय

- Minimum Legal Size (MLS): Prevents juvenile fishing; fish below a specified size (e.g., 140 mm for Pomfret) cannot be caught.
- न्यूनतम वैधानिक आकार (MLS): छोटी मछलियों के शिकार पर रोक; निर्धारित आकार (जैसे पॉम्फ्रेट के लिए 140 मिमी) से कम मछली नहीं पकड़ी जा सकती।
- State Fish Status: Silver Pomfret is the State Fish of Maharashtra to promote conservation and breeding.
- राज्य मछली दर्जा: प्रजनन संरक्षण के लिए सिल्वर पॉम्फ्रेट महाराष्ट्र की राज्य मछली है।
- Zonal Restrictions: Near-shore areas reserved for traditional fishers; large vessels are restricted.
- क्षेत्रीय प्रतिबंध: तटवर्ती क्षेत्रों को पारंपरिक मछुआरों के लिए आरक्षित किया गया है; बड़े जहाजों पर रोक है।
- Fishing Ban: A 61-day annual ban on both East and West coasts to allow breeding.
- मछली पकड़ने पर प्रतिबंध: प्रजनन के लिए पूर्वी व पश्चिमी तटों पर 61 दिनों का वार्षिक प्रतिबंध।
- Financial Aid: Fishers receive ₹4,500 (₹1,500 contribution + ₹3,000 government subsidy) during ban periods.
- वित्तीय सहायता: प्रतिबंध अवधि में मछुआरों को ₹4,500 (₹1,500 अंशदान + ₹3,000 सरकारी सब्सिडी) मिलती है।
- Artificial Reefs: Man-made structures placed on the sea floor to restore habitats and boost fish populations.
- कृत्रिम रीफ: समुद्र तल पर बनाए गए ढांचे, जो आवास पुनर्स्थापन और मछली आबादी बढ़ाने में सहायक हैं।





Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana :

- Launched : September 10, 2020
- Nodal Ministry : Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
- Chairperson (Union Minister) : Shri Rajiv Ranjan Singh
- Global Rank : India is the 2nd largest fish producer in the world.
- Agri-GVA Contribution : Fisheries contribute 7.43% to Agriculture GVA.
- Budget FY 2026-27 : ₹2,500 Crore (highest ever allocation for PMMSY).
- Key Sub-Scheme : PM-MKSSY (Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana) - ₹6,000 Crore outlay.
- Goal : Integrated development of 500 reservoirs & Amrit Sarovars



EXAM
Genius





Ques: According to India's tech services roadmap aligned with Viksit Bharat@2047, what is the targeted annual revenue size of India's technology services industry by 2035?

विकसित भारत@2047 के अनुरूप भारत की टेक सर्विसेज रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत की प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग का लक्षित वार्षिक राजस्व कितना है?

- A) \$400–500 billion / 400–500 अरब डॉलर
- B) \$550–650 billion / 550–650 अरब डॉलर
- C) \$650–700 billion / 650–700 अरब डॉलर
- D) \$750–850 billion / 750–850 अरब डॉलर
- E) Above \$1 trillion / 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक

Answer: Option D

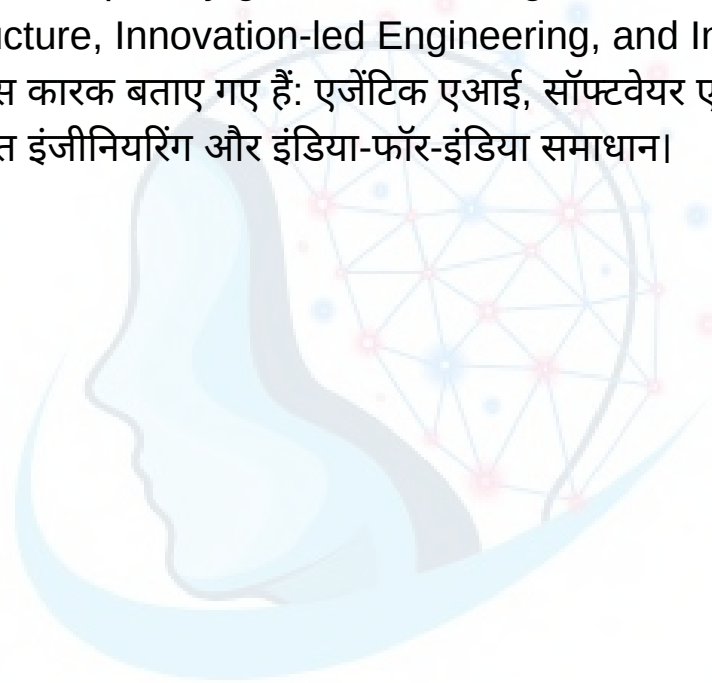
Explanation | व्याख्या:

- India's tech services industry comprises companies that design, build, implement, manage, and support technology solutions for global and domestic clients.
- भारत का टेक सर्विसेज उद्योग उन कंपनियों से मिलकर बना है जो वैश्विक और घरेलू ग्राहकों के लिए तकनीकी समाधान डिज़ाइन, निर्माण, कार्यान्वयन और प्रबंधन करती हैं।
- Core segments of the industry include IT services, software development, digital transformation, business process & operations management, and engineering & R&D services.
- इस उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं: आईटी सेवाएँ, सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल परिवर्तन, बिज़नेस प्रोसेस एवं ऑपरेशंस मैनेजमेंट तथा इंजीनियरिंग एवं R&D सेवाएँ।
- The sector contributes nearly 7% to India's GDP and generates around \$265 billion in annual revenue.
- यह क्षेत्र भारत की GDP में लगभग 7% का योगदान देता है और लगभग 265 अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है।
- India accounts for nearly 20% share in the global tech services market.
- वैश्विक टेक सर्विसेज बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है।
- Under the Viksit Bharat@2047 vision, India aims to scale the tech services industry to \$750–850 billion in annual revenue by 2035 and increase its global market share beyond 25%.





- विकसित भारत@2047 के तहत, भारत का लक्ष्य 2035 तक टेक सर्विसेज उद्योग का वार्षिक राजस्व 750–850 अरब डॉलर तक पहुँचाना और वैश्विक हिस्सेदारी को 25% से अधिक करना है।
- However, current projections indicate a potential revenue shortfall of \$250–300 billion if growth momentum is not accelerated.
- हालांकि, यदि विकास की गति तेज नहीं हुई तो 250–300 अरब डॉलर के राजस्व घाटे की संभावना जताई गई है।
- The roadmap identifies five priority growth levers: Agentic AI, Software & Products (SaaS), Digital Infrastructure, Innovation-led Engineering, and India-for-India solutions.
- रोडमैप में पाँच प्रमुख विकास कारक बताए गए हैं: एजेंटिक एआई, सॉफ्टवेयर एवं उत्पाद (SaaS), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार-आधारित इंजीनियरिंग और इंडिया-फॉर-इंडिया समाधान।



EXAM
Genius





Ques: APEDA was established under which Act?

APEDA की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?

- A) Foreign Trade Act, 1992 / विदेशी व्यापार अधिनियम, 1992
- B) APEDA Act, 1985 / APEDA अधिनियम, 1985
- C) Food Safety Act, 2006 / खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006
- D) Export Promotion Act, 1980 / निर्यात प्रोत्साहन अधिनियम, 1980
- E) Agricultural Trade Act, 1991 / कृषि व्यापार अधिनियम, 1991

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या :

- APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) was established under the APEDA Act, 1985.
- APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) की स्थापना APEDA अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी।
- The Act was passed in December 1985 and came into force on 13 February 1986, marking the beginning of APEDA's statutory role.
- यह अधिनियम दिसंबर 1985 में पारित हुआ और 13 फरवरी 1986 से लागू हुआ।
- APEDA replaced the earlier Processed Food Export Promotion Council (PFEP) to provide a stronger institutional framework for exports.
- APEDA ने Processed Food Export Promotion Council (PFEP) का स्थान लिया।
- It functions under the Ministry of Commerce & Industry, Government of India.
- यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- In FY 2024–25, APEDA contributed USD 28.59 billion out of India's total USD 51.91 billion agricultural exports.
- वित्त वर्ष 2024–25 में भारत के कुल USD 51.91 बिलियन कृषि निर्यात में से USD 28.59 बिलियन का योगदान APEDA का रहा।
- Over the past decade, India's agricultural exports rose from USD 38.66 billion to USD 51.90 billion, reflecting sustained growth.
- पिछले एक दशक में भारत का कृषि निर्यात USD 38.66 बिलियन से बढ़कर USD 51.90 बिलियन हो गया।





Ques: Why is the rapid thinning and retreat of the Thwaites Glacier considered a major global concern?

थ्वाइट्स ग्लेशियर के तेजी से पतले होने और पीछे हटने को वैश्विक चिंता क्यों माना जाता है?

- A) Because it is the coldest glacier in the world / क्योंकि यह दुनिया का सबसे ठंडा ग्लेशियर है
- B) Because it supports marine biodiversity only / क्योंकि यह केवल समुद्री जैव विविधता को सहारा देता है
- C) Because its collapse could trigger massive global sea-level rise / क्योंकि इसके ढहने से वैश्विक समुद्र-स्तर में भारी वृद्धि हो सकती है
- D) Because it lies entirely on land and has no ocean connection / क्योंकि यह पूरी तरह भूमि पर स्थित है और समुद्र से कोई संबंध नहीं है
- E) Because it is shrinking slower than other Antarctic glaciers / क्योंकि यह अन्य अंटार्कटिक ग्लेशियरों की तुलना में धीमी गति से सिकुड़ रहा है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Recent studies show rapid thinning and retreat of the Thwaites Glacier located in West Antarctica.
- हालिया अध्ययनों में थ्वाइट्स ग्लेशियर (पश्चिम अंटार्कटिका) के तेजी से पतले होने और पीछे हटने की पुष्टि हुई है।
- It is one of the world's widest glaciers, with a width of about 120 km.
- यह लगभग 120 किमी चौड़ा है, जो इसे दुनिया के सबसे चौड़े ग्लेशियरों में शामिल करता है।
- The glacier covers an area of nearly 1.9 lakh वर्ग किमी, roughly comparable to Great Britain or the Indian state of Gujarat.
- इसका क्षेत्रफल लगभग 1.9 लाख वर्ग किमी है, जो ग्रेट ब्रिटेन या गुजरात राज्य के बराबर है।
- Thwaites is a fast-moving glacier, meaning its ice reaches the ocean quickly, accelerating ice loss.
- थ्वाइट्स एक तेज़ी से बहने वाला ग्लेशियर है, जिससे बर्फ तेजी से समुद्र में पहुँचती है।
- If Thwaites Glacier collapses, it alone contains enough ice to raise global sea levels by about 0.5 मीटर.
- यदि यह ग्लेशियर ढह गया, तो अकेले इससे ही वैश्विक समुद्र-स्तर लगभग 0.5 मीटर बढ़ सकता है।





Ques: The Raksha Mantri approved the expansion of the definition of 'family' for which purpose?

रक्षा मंत्री ने 'परिवार' की परिभाषा के विस्तार को किस उद्देश्य के लिए मंजूरी दी है?

- A) Pension eligibility of Armed Forces personnel / सशस्त्र बल कर्मियों की पेंशन पात्रता
- B) Allotment of Government Accommodation to Service Officers / सेवा अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन
- C) Promotion policy reforms / पदोन्नति नीति में सुधार
- D) Medical benefits under ECHS / ईसीएचएस के तहत चिकित्सा लाभ
- E) Leave and travel concessions / अवकाश और यात्रा रियायतें

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या :

- The Raksha Mantri has approved a proposal to expand the definition of 'family' for the allotment of Government Accommodation to Service Officers of the Armed Forces.
- रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के सेवा अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटन के लिए 'परिवार' की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी दी है।
- Core Theme: Social Welfare Reform and Administrative Modernization.
- मुख्य विषय: सामाजिक कल्याण सुधार और प्रशासनिक आधुनिकीकरण।
- The decision aligns with the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, reinforcing the legal obligation of children to care for their parents.
- यह निर्णय Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के अनुरूप है, जो माता-पिता की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी को मजबूत करता है।
- The move specifically benefits Single Women Officers who live with and take care of their elderly parents.
- यह कदम विशेष रूप से उन एकल महिला अधिकारियों के लिए लाभकारी है जो अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहती हैं और उनकी देखभाल करती हैं।
- Key Changes in Definition | परिभाषा में प्रमुख बदलाव
 - Existing members: Spouse, dependent children, and step-children.
 - मौजूदा सदस्य: जीवनसाथी, आश्रित बच्चे और सौतेले बच्चे।
 - Added members: Parents, dependent siblings, and legally adopted children.
 - जोड़े गए सदस्य: माता-पिता, आश्रित भाई-बहन और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे।





Ques: Which institute has successfully achieved induced breeding of the Mangrove Clam (*Geloina erosa*)? किस संस्थान ने मैंग्रोव क्लैम (*Geloina erosa*) का कृत्रिम प्रजनन सफलतापूर्वक किया है?

- A) ICAR–CIFT, Kochi / आईसीएआर–सीआईएफटी, कोच्चि
- B) ICAR–CMFRI, Kochi / आईसीएआर–सीएमएफआरआई, कोच्चि
- C) CIFRI, Barrackpore / सीआईएफआरआई, बैरकपुर
- D) National Institute of Oceanography, Goa / राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा
- E) Zoological Survey of India, Kolkata / प्राणी सर्वेक्षण भारत, कोलकाता

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The induced breeding of Mangrove Clam (*Geloina erosa*) has been achieved by ICAR–Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI).
- मैंग्रोव क्लैम (*Geloina erosa*) का कृत्रिम प्रजनन आईसीएआर–केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) द्वारा किया गया है।
- Mangrove clam is commonly known as mud clam.
- मैंग्रोव क्लैम को सामान्यतः मड क्लैम कहा जाता है।
- The scientific name of the mangrove clam is *Geloina erosa* and it belongs to the bivalve group under the phylum Mollusca.
- मैंग्रोव क्लैम का वैज्ञानिक नाम *Geloina erosa* है और यह मोलस्का संघ के द्विपटली (बाइवेल्व) वर्ग से संबंधित है।
- The species is found in mangrove and estuarine ecosystems.
- यह प्रजाति मैंग्रोव और मुहाना (एस्टुअरीन) पारितंत्रों में पाई जाती है।
- It is distributed across South and Southeast Asia. In India, it is commonly found along the western coast.
- इसका वितरण दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत में यह मुख्य रूप से पश्चिमी तट पर पाई जाती है।
- In parts of Kerala, it is locally known as “Kandal Kakka”.
- केरल के कुछ हिस्सों में इसे स्थानीय रूप से “कंडल कक्का” कहा जाता है।





Ques: Whose birth anniversary is observed as Antyodaya Diwas in India?

भारत में अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है?

- A) Mahatma Gandhi / महात्मा गांधी
- B) Ram Manohar Lohia / राम मनोहर लोहिया
- C) Pandit Deendayal Upadhyaya / पंडित दीनदयाल उपाध्याय
- D) Jayaprakash Narayan / जयप्रकाश नारायण
- E) B. R. Ambedkar / डॉ. बी. आर. अंबेडकर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Vice-President of India paid tribute to Pandit Deendayal Upadhyaya on his death anniversary, observed on 11 February 1968.
- भारत के उपराष्ट्रपति ने 11 फरवरी 1968 को उनकी पुण्यतिथि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की।
- He was an Indian politician, philosopher, and ideologue associated with the RSS and Bharatiya Jana Sangh (BJS), the predecessor of the Bharatiya Janata Party (BJP).
- वे एक भारतीय राजनेता, दार्शनिक और RSS तथा भारतीय जनसंघ (BJS) के प्रमुख विचारक थे, जो भाजपा का पूर्ववर्ती संगठन था।
- His core philosophy was Antyodaya, which focuses on uplifting the last person in society and addressing the needs of the most disadvantaged.
- उनका मूल विचार अंत्योदय था, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है।
- Since 25 September 2014, his birth anniversary has been observed nationwide as Antyodaya Diwas to honor his contributions.
- 25 सितंबर 2014 से उनकी जयंती को देशभर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
- In 2015, the National Rural Livelihood Mission (NRLM) was renamed Deendayal Antyodaya Yojana–NRLM in his honor.
- 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना–NRLM किया गया।
- In 2018, Mughalsarai Junction in Uttar Pradesh was renamed Pandit Deendayal Upadhyaya Junction.
- 2018 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया।





Ques: The Reserve Bank of India (RBI) granted final approval to Bain Capital affiliates to acquire joint control and up to what percentage stake in Manappuram Finance?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी?

- A) 26%
- B) 33%
- C) 41.66%
- D) 49%
- E) 51%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has granted final approval to affiliates of Bain Capital to acquire joint control and up to 41.66% stake in Kerala-based Manappuram Finance.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेन कैपिटल की सहयोगी कंपनियों को केरल स्थित मणप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त नियंत्रण और अधिकतम 41.66% हिस्सेदारी हासिल करने की अंतिम मंजूरी दी है।
- This approval clears the way for the completion of Bain Capital's ₹4,385 crore investment in the gold loan-focused NBFC.
- इस मंजूरी से गोल्ड लोन पर केंद्रित NBFC में बेन कैपिटल के ₹4,385 करोड़ के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- Bain Capital was founded in 1984 and is headquartered in Boston, Massachusetts, USA.
- बेन कैपिटल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में स्थित है।
- Manappuram Finance was originally founded in 1949 and is headquartered at Valapad in the Thrissur district of Kerala.
- मणप्पुरम फाइनेंस की मूल स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर ज़िले के वलापाड में स्थित है।
- It is a Non-Deposit Accepting Loan Company and is classified as a Systemically Important Non-Banking Financial Company (NBFC-ND-SI).
- यह एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली ऋण कंपनी है और इसे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय





कंपनी (NBFC-ND-SI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- Deepak Reddy assumed charge as the Chief Executive Officer (CEO) of Manappuram Finance on August 1, 2025.
- दीपक रेड्डी ने 1 अगस्त 2025 को मणप्पुरम फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला।



EXAM
Genius





Ques: NPCI has partnered with which company to advance its sovereign AI model for digital payments?

NPCI ने डिजिटल भुगतान के लिए सॉवरेन AI मॉडल को आगे बढ़ाने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Nvidia / एनवीडिया
- B) Google / गूगल
- C) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- D) IBM / आईबीएम
- E) Amazon / अमेज़न

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या :

- National Payments Corporation of India (NPCI) has partnered with Nvidia to scale and advance a sovereign AI model for India's digital payments ecosystem.
- NPCI ने भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए सॉवरेन AI मॉडल को विकसित और विस्तारित करने हेतु Nvidia के साथ साझेदारी की है।
- The initiative focuses on building AI capabilities aligned with India's regulatory framework and data sovereignty requirements.
- यह पहल भारत की नियामकीय व्यवस्था और डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के अनुरूप AI क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।
- NPCI will leverage Nvidia's advanced AI and accelerated computing platforms, including Nvidia Nemotron models.
- NPCI, Nvidia के उन्नत AI और accelerated computing प्लेटफॉर्म, जैसे Nvidia Nemotron मॉडल्स, का उपयोग करेगा।
- The collaboration aims to enhance trust, resilience, security, and efficiency in large-scale real-time payment systems.
- इस सहयोग का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रियल-टाइम भुगतान प्रणालियों में भरोसा, लचीलापन, सुरक्षा और दक्षता को मजबूत करना है।





Ques: What key change has the Reserve Bank of India (RBI) introduced regarding Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) को लेकर कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Banned the use of DLGs permanently / DLG के उपयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाया
- B) Allowed DLGs only for banks, not NBFCs / DLG केवल बैंकों के लिए अनुमति दी, NBFCs के लिए नहीं
- C) Restored the use of DLGs for NBFCs in loan loss provisioning / NBFCs को ऋण हानि प्रावधान में DLG शामिल करने की अनुमति दी
- D) Increased the cap on DLGs to 10% of loan portfolio / DLG की सीमा 10% तक बढ़ाई
- E) Allowed DLGs only for government-backed fintechs / DLG केवल सरकारी समर्थित फिनटेक्स के लिए अनुमति दी

Answer: Option C

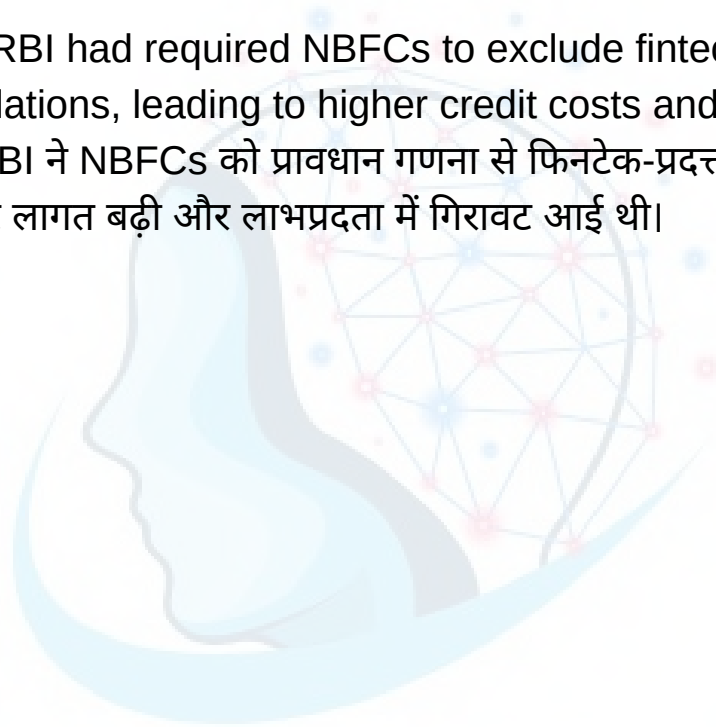
Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has restored the use of Default Loss Guarantees (DLGs) for non-bank lenders, reversing its curbs imposed in May 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई 2025 में लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेते हुए गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) के उपयोग को बहाल कर दिया है।
- Under the revised framework, NBFCs can again factor in DLGs while calculating loan loss provisions, and the changes take effect immediately.
- संशोधित ढांचे के तहत NBFCs अब ऋण हानि प्रावधान की गणना में DLG को शामिल कर सकती हैं और यह व्यवस्था तुरंत प्रभावी होगी।
- The guarantee must be an integral part of the loan arrangement and cannot be treated as a separate standalone protection.
- यह गारंटी ऋण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और इसे अलग सुरक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा।
- Loss estimates must be updated every time the DLG is invoked, as the level of protection reduces with each utilisation.
- प्रत्येक बार DLG के उपयोग पर हानि अनुमान को अपडेट करना होगा, क्योंकि हर उपयोग के साथ सुरक्षा घटती जाती है।





- DLGs are risk-sharing mechanisms widely used in digital lending and co-lending models, usually capped at 5% of the loan portfolio and often backed by fixed deposits from fintech partners.
- DLG जोखिम-साझाकरण तंत्र हैं, जो डिजिटल लेंडिंग और सह-ऋण मॉडल में सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं, आमतौर पर ऋण पोर्टफोलियो के 5% तक सीमित होते हैं और अक्सर फिनटेक भागीदारों की फिक्स्ड डिपॉजिट से समर्थित होते हैं।
- Earlier, in May 2025, RBI had required NBFCs to exclude fintech-provided DLGs from provisioning calculations, leading to higher credit costs and reduced profitability.
- इससे पहले मई 2025 में RBI ने NBFCs को प्रावधान गणना से फिनटेक-प्रदत्त DLG को बाहर रखने का निर्देश दिया था, जिससे क्रेडिट लागत बढ़ी और लाभप्रदता में गिरावट आई थी।



EXAM
Genius





Ques: Why has SEBI constituted a working group recently?

SEBI ने हाल ही में कार्यसमूह क्यों गठित किया है?

- A) To regulate cryptocurrency exchanges / क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंज को विनियमित करने के लिए
- B) To review the framework for ESG Rating Providers / ESG रेटिंग प्रदाताओं के ढांचे की समीक्षा के लिए
- C) To revise mutual fund taxation rules / म्यूचुअल फंड कर नियमों में संशोधन के लिए
- D) To promote IPO listings / IPO लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए
- E) To regulate commodity markets / क्मोडिटी बाजार को विनियमित करने के लिए

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has constituted a dedicated working group to review the regulatory framework for ESG Rating Providers (ERPs).
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने ESG रेटिंग प्रदाताओं (ERPs) के नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेष कार्यसमूह का गठन किया है।
- The move follows feedback from market participants regarding ESG rating practices.
- यह कदम बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के बाद उठाया गया है।
- The panel includes representatives from issuers, investors, domestic & global ERPs, ESG analysts, legal experts, and academia.
- इस पैनल में इश्यूअर्स, निवेशकों, घरेलू व वैश्विक ERPs, ESG विश्लेषकों, कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- The group will review existing regulations, assess global developments, and recommend measures to enhance transparency and reliability in ESG ratings.
- यह कार्यसमूह मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगा, वैश्विक विकास का आकलन करेगा और ESG रेटिंग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उपाय सुझाएगा।





Ques: Indian Overseas Bank (IOB) expanded its start-up focused banking network by launching exclusive branches in which cities?

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्टार्ट-अप केंद्रित बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किन शहरों में विशेष शाखाएँ शुरू करके किया?

- A) Chennai, Hyderabad, Pune / चेन्नई, हैदराबाद, पुणे
- B) Delhi, Mumbai, Bengaluru / दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु
- C) Kolkata, Ahmedabad, Jaipur / कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर
- D) Kochi, Trivandrum, Coimbatore / कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोयंबटूर
- E) Noida, Gurugram, Faridabad / नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Indian Overseas Bank has expanded its dedicated Start-up Banking Network by launching exclusive start-up focused branches in Delhi, Mumbai, and Bengaluru.
- इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में विशेष स्टार्ट-अप केंद्रित शाखाएँ शुरू करके अपने स्टार्ट-अप बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया है।
- This expansion builds on the success of its first start-up focused branch in Chennai, which was launched in June 2024.
- यह विस्तार जून 2024 में चेन्नई में शुरू की गई पहली स्टार्ट-अप शाखा की सफलता पर आधारित है।
- The initiative was announced on the occasion of the 90th Foundation Day of Indian Overseas Bank.
- यह पहल इंडियन ओवरसीज बैंक के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित की गई।
- These specialised branches offer a tailored Startup Current Account with benefits such as waiver of Quarterly Average Balance (QAB) for the first 18 months.
- इन विशेष शाखाओं में स्टार्ट-अप के लिए विशेष करंट अकाउंट उपलब्ध है, जिसमें पहले 18 महीनों तक तिमाही औसत शेष राशि (QAB) से छूट दी गई है।
- Additional features include 200 free cheque leaves per month and free NEFT, RTGS, and IMPS transactions.
- अतिरिक्त सुविधाओं में प्रति माह 200 निःशुल्क चेक पत्ते और निःशुल्क NEFT, RTGS तथा IMPS लेन-देन शामिल हैं।
- The bank also launched 'IOB Gram Sweekar', a rural outreach programme aimed at





Ques: What is the key impact of the Reserve Bank of India's (RBI) new lending norms for capital market intermediaries effective from April 1?

1 अप्रैल से प्रभावी RBI के नए ऋण नियमों का पूंजी बाजार मध्यस्थों पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ेगा?

- A) Banks can freely lend for brokers' proprietary trading / बैंक ब्रोकरों के स्वयं के ट्रेडिंग के लिए स्वतंत्र रूप से ऋण दे सकेंगे
- B) Unsecured loans to stock brokers are permitted / स्टॉक ब्रोकरों को बिना गारंटी ऋण देने की अनुमति होगी
- C) All credit to securities firms must be fully collateral-backed / प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया हर ऋण पूरी तरह जमानत-आधारित होगा
- D) Bank guarantees for proprietary trades need no cash collateral / प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए बैंक गारंटी में नकद जमानत की आवश्यकता नहीं होगी
- E) Commodity brokers are exempted from the new norms / कमोडिटी ब्रोकरों को नए नियमों से छूट दी गई है

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has tightened lending norms for capital market intermediaries, including stock and commodity brokers involved in proprietary trading.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में लगे स्टॉक और कमोडिटी ब्रोकरों सहित पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए ऋण नियम सख्त कर दिए हैं।
- Under the new prudential framework, all loans to securities firms must be fully backed by collateral, eliminating unsecured exposure to speculative activities.
- नए सावधानीपूर्ण ढांचे के तहत प्रतिभूति कंपनियों को दिया गया प्रत्येक ऋण पूरी तरह जमानत से सुरक्षित होना अनिवार्य होगा, जिससे सट्टात्मक गतिविधियों में बिना गारंटी जोखिम समाप्त होगा।
- Banks are prohibited from lending for brokers' own-account (proprietary) trading or for investments made by brokers.
- बैंकों को ब्रोकरों की स्वयं की ट्रेडिंग या उनके निवेश के लिए ऋण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- Bank guarantees issued for proprietary trades must be fully secured, with at least 50% collateral in cash and the remaining portion in cash equivalents or government securities.





Ques: Vast Space signed an order with NASA for its sixth Private Astronaut Mission (PAM) to which destination?

वास्त स्पेस ने नासा के साथ अपना छठा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन (PAM) किस गंतव्य के लिए हस्ताक्षरित किया?

- A) Lunar Gateway / लूनर गेटवे
- B) International Space Station (ISS) / अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)
- C) Tiangong Space Station / तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन
- D) Haven-1 Commercial Station / हेवन-1 वाणिज्यिक स्टेशन
- E) Low Earth Orbit Free Flyer / लो अर्थ ऑर्बिट फ्री फ्लायर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Vast Space signed an order with NASA for its sixth Private Astronaut Mission (PAM) to the International Space Station.
- वास्त स्पेस ने अपने छठे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन (PAM) के लिए नासा के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए समझौता किया।
- The mission is targeted for launch no earlier than Summer 2027 from Florida, USA.
- इस मिशन का प्रक्षेपण ग्रीष्म 2027 से पहले नहीं, फ्लोरिडा (अमेरिका) से प्रस्तावित है।
- This will be Vast's first private astronaut mission in partnership with NASA.
- यह नासा के साथ साझेदारी में वास्त का पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा।
- Astronauts will spend up to 14 days aboard the ISS.
- अंतरिक्ष यात्री ISS पर अधिकतम 14 दिनों तक रहेंगे।
- The mission will use SpaceX's Falcon 9 launch vehicle and Dragon spacecraft for crew transport.
- मिशन में प्रक्षेपण के लिए स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और चालक दल के परिवहन के लिए ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा।
- The final launch date will depend on ISS traffic and operational planning.
- अंतिम प्रक्षेपण तिथि ISS की ट्रैफिक स्थिति और परिचालन योजना पर निर्भर करेगी।
- Vast is also developing Haven-1, planned for launch in 2027, aiming to become the world's first commercial space station.





Ques: The Global Finance & Technology Network (GFTN) was created by which authority?

ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) की स्थापना किस प्राधिकरण द्वारा की गई थी?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Monetary Authority of Singapore / सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण
- C) World Bank / विश्व बैंक
- D) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
- E) International Monetary Fund / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या :

- The Global Finance & Technology Network (GFTN) and the Startup Policy Forum (SPF) announced a strategic collaboration to accelerate fintech and digital innovation.
- GFTN और Startup Policy Forum (SPF) ने फिनटेक और डिजिटल नवाचार को तेज़ करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की।
- The partnership was announced at the Black Swan Summit India 2026 held in Bhubaneswar, Odisha.
- इस साझेदारी की घोषणा भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित Black Swan Summit India 2026 के दौरान की गई।
- GFTN is based in Singapore and was created by the Monetary Authority of Singapore (MAS).
- GFTN सिंगापुर स्थित है और इसकी स्थापना Monetary Authority of Singapore (MAS) द्वारा की गई थी।
- **The collaboration focuses on three goals:**
 - Build Bridges: Create innovation corridors between India and the world.
 - Better Rules: Strengthen dialogue between regulators and tech firms.
 - Go Global: Support Indian startups in expanding internationally.
- इस सहयोग के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
 - ब्रिज बनाना: भारत और विश्व के बीच नवाचार कॉरिडोर बनाना।
 - बेहतर नियम: नियामकों और टेक कंपनियों के बीच संवाद को मजबूत करना।
 - वैश्विक विस्तार: भारतीय स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार में सहायता देना।





- SPF represents over 65 fast-growing Indian startups with a combined valuation of more than USD 100 billion.
- SPF 65 से अधिक तेज़ी से बढ़ते भारतीय स्टार्टअप्स का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका संयुक्त मूल्यांकन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।



EXAM
Genius





Ques: Google's new undersea cable project will directly connect which two countries?

Google का नया अंडरसी केबल प्रोजेक्ट किन दो देशों को सीधे जोड़ेगा?

- A) India and UK / भारत और यूके
- B) India and Australia / भारत और ऑस्ट्रेलिया
- C) India and United States / भारत और अमेरिका
- D) India and Japan / भारत और जापान
- E) India and Singapore / भारत और सिंगापुर

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- Google CEO Sundar Pichai announced an undersea cable project directly linking India and the United States.
- Google के CEO सुंदर पिचाई ने भारत और अमेरिका को सीधे जोड़ने वाले अंडरसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा की।
- This will be the second planned subsea cable system directly connecting the two nations.
- यह दोनों देशों को सीधे जोड़ने वाला दूसरा नियोजित अंडरसी केबल सिस्टम होगा।
- The first such initiative was Meta's Project Waterworth.
- इससे पहले ऐसा प्रोजेक्ट Meta का 'Project Waterworth' था।
- Currently, most internet traffic between the two countries passes through relay hubs like Singapore.
- वर्तमान में दोनों देशों के बीच अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक सिंगापुर जैसे रिले प्वाइंट्स के माध्यम से जाता है।
- The new project is expected to improve digital connectivity, data security, and internet speed between India and the U.S.
- यह परियोजना दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और इंटरनेट गति को बेहतर बनाएगी।





Recent News Headlines Related to MoU and agreement:

- Indian Institute of Technology ,Madras Research Park, in partnership with Unicorn India Ventures, launched a 'IITM-Unicorn Frontier Fund I' , a venture capital fund, worth Rs.600 crores to support deeptechology startups in India. It plans to invest in over 25 startups and will allocate about 60% for initial investments and 40% for follow-on funding.
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास रिसर्च पार्क ने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के साथ साझेदारी में भारत में डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 600 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड 'आईआईटीएम-यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड I' लॉन्च किया है। यह फंड 25 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश करने की योजना बना रहा है और लगभग 60% प्रारंभिक निवेश और 40% अनुवर्ती फंडिंग के लिए आवंटित करेगा।
- Indian National Science Academy and National Institute of Science Communication and Policy Research signed a Memorandum of Understanding (MoU) to promote collaborative activities in science communication and evidence-based science policy research.
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने विज्ञान संचार और साक्ष्य-आधारित विज्ञान नीति अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए।
- India and France amended the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) to boost bilateral trade and investments.
- भारत और फ्रांस ने व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए DTAA में संशोधन किया।
- Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE) and Hindustan Shipyard Limited (HSL) signed a Memorandum of Understanding (MoU) in Kolkata to form a strategic consortium for executing a large-scale national shipbuilding programme.
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) ने कोलकाता में एक बड़े पैमाने के राष्ट्रीय जहाज निर्माण कार्यक्रम को लागू करने के लिए रणनीतिक कंसोर्टियम बनाने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- Airports Authority of India (AAI) has signed an MoU with Bharat Taxi to improve last-mile connectivity at select airports.
- एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने चुनिंदा हवाई अड्डों पर अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत टैक्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।





Ques: Which ministry is organising the National Conference on Safety of Women at Workplace (SHe-Box) on 14 February 2026 at Vigyan Bhawan, New Delhi?

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (SHe-Box) पर 14 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है?

- A) Ministry of Labour and Employment / श्रम और रोजगार मंत्रालय
- B) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- C) Ministry of Women and Child Development / महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- D) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- E) Ministry of Education / शिक्षा मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Conference on Safety of Women at Workplace (SHe-Box) is being organised by the Ministry of Women and Child Development on 14 February 2026 at Vigyan Bhawan.
- कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (SHe-Box) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 14 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- The objective of the conference is to reaffirm the Government's commitment to ensuring safe, dignified and harassment-free workplaces for women.
- इस सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराना है।
- It also aims to strengthen the implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
- यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने पर भी केंद्रित है।
- The SHe-Box (Sexual Harassment electronic Box) portal was launched by MWCD on 29 August 2024.
- SHe-Box (सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) पोर्टल को 29 अगस्त 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- The portal is a secure, user-friendly and multilingual digital platform that enables





online complaint filing and ensures automatic forwarding of complaints to the Internal Committee (IC) or Local Committee (LC).

- यह पोर्टल एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल और बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उन्हें आंतरिक समिति (IC) या स्थानीय समिति (LC) तक स्वतः भेजने की सुविधा देता है।
- It provides real-time complaint tracking along with strict confidentiality safeguards for complainants.
- यह शिकायतों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग और शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।



EXAM
Genius





Ques: The AI models 'Vikram' launched by Sarvam AI are primarily designed for what feature?

Sarvam AI द्वारा लॉन्च 'विक्रम' एआई मॉडल मुख्य रूप से किस विशेषता के लिए डिजाइन किए गए हैं?

- A) Only English text processing / केवल अंग्रेजी टेक्स्ट प्रोसेसिंग
- B) Voice-command usage and support for 22 Indian languages / वॉइस कमांड आधारित उपयोग और 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन
- C) Military surveillance applications / सैन्य निगरानी उपयोग
- D) Cryptocurrency trading / क्रिप्टोकॉरेन्सी ट्रेडिंग
- E) Space research simulations / अंतरिक्ष अनुसंधान सिमुलेशन

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- Sarvam AI unveiled two AI language models named 'Vikram' at an AI Summit in New Delhi.
- Sarvam AI ने नई दिल्ली में आयोजित AI समिट में 'विक्रम' नामक दो एआई भाषा मॉडल लॉन्च किए।
- The models are specifically designed to function through voice commands.
- ये मॉडल विशेष रूप से वॉइस कमांड के माध्यम से कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- They support and are accessible in 22 Indian languages, strengthening multilingual AI capability.
- ये 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे बहुभाषी एआई क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
- The initiative aims to significantly improve AI performance in Indian languages, marking a milestone in India's AI ecosystem.
- यह पहल भारतीय भाषाओं में एआई प्रदर्शन सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





Ques: The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved India's first underwater road-rail tunnel beneath which river?

कैबिनेट समिति on Economic Affairs (CCEA) ने भारत की पहली अंडरवॉटर रोड-रेल सुरंग किस नदी के नीचे स्वीकृत की है?

- A) Ganga / गंगा
- B) Yamuna / यमुना
- C) Brahmaputra / ब्रह्मपुत्र
- D) Godavari / गोदावरी
- E) Narmada / नर्मदा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the construction of India's first underwater twin-tube road-cum-rail tunnel beneath the Brahmaputra River in Assam.
- कैबिनेट समिति on Economic Affairs (CCEA) ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडरवॉटर ट्विन-ट्यूब रोड-कम-रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है।
- The total length of the project is 33.7 km, which includes a 15.79 km long underwater twin-tube tunnel.
- इस परियोजना की कुल लंबाई 33.7 किमी है, जिसमें 15.79 किमी लंबी अंडरवॉटर ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है।
- The project will be developed under the Engineering, Procurement and Construction (EPC) mode at an estimated cost of ₹18,662 crore.
- यह परियोजना इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड के तहत लगभग ₹18,662 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी।
- The tunnel will improve connectivity between Gohpur (NH-15) and Numaligarh (NH-715).
- यह सुरंग गोहपुर (NH-15) और नुमालीगढ़ (NH-715) के बीच संपर्क को बेहतर बनाएगी।
- The distance between the two points will reduce from about 240 km to just 34 km, while travel time will drop from nearly 6 hours to around 20 minutes.
- इससे दूरी लगभग 240 किमी से घटकर 34 किमी रह जाएगी और यात्रा समय लगभग 6 घंटे से घटकर 20





मिनट हो जाएगा।

- Additionally, the Cabinet approved three multitracking railway projects: Kasara–Manmad, Delhi–Ambala, and Ballari–Hosapete third and fourth lines across multiple states.
- इसके अलावा, कैबिनेट ने कासारा–मनमाड, दिल्ली–अंबाला और बल्लारी–होसपेटे रेलखंडों पर तीसरी और चौथी लाइन के मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है।



EXAM
Genius





Ques: The Chief Minister Skill Development Scheme approved by the Delhi Government is aimed at supporting artisans engaged in which sectors?

दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किन क्षेत्रों से जुड़े कारीगरों को समर्थन देने के लिए है?

- A) IT and Software Services / आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएँ
- B) Automobile and Engineering Industries / ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग
- C) Khadi, Handloom and Cottage Industries / खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योग
- D) Construction and Real Estate / निर्माण और रियल एस्टेट
- E) Tourism and Hospitality / पर्यटन और आतिथ्य

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Delhi Government has approved the Chief Minister Skill Development Scheme to support artisans engaged in khadi, handloom and cottage industries.
- दिल्ली सरकार ने खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योगों से जुड़े कारीगरों के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है।
- The initiative was announced by Chief Minister Rekha Gupta, who highlighted that artisans are custodians of Delhi's cultural heritage and should be connected to modern markets.
- इस पहल की घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की, जिन्होंने कहा कि कारीगर दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं और उन्हें आधुनिक बाजारों से जोड़ना आवश्यक है।
- The scheme aims to provide structured skill training to artisans.
- इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को संरचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- It also focuses on enabling digital access and marketing support.
- योजना डिजिटल पहुंच और विपणन सहायता उपलब्ध कराने पर भी केंद्रित है।
- Financial assistance will be offered to improve income levels and livelihood opportunities.
- आय और आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।





Ques: What is the purpose of NHAI's bee corridor initiative?

NHAI के बी कॉरिडोर पहल का उद्देश्य क्या है?

- A) To increase highway toll revenue / राजमार्ग टोल राजस्व बढ़ाना
- B) To reduce ecological stress and promote biodiversity / पारिस्थितिक दबाव कम करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना
- C) To build expressways in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सप्रेसवे बनाना
- D) To promote electric vehicles / इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना
- E) To develop industrial zones / औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- National Highways Authority of India (NHAI) will develop bee corridors along national highways.
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बी कॉरिडोर विकसित करेगा।
- The initiative aims to reduce ecological stress, improve pollination, and promote biodiversity conservation.
- इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिक दबाव को कम करना, परागण को बढ़ावा देना और जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- At least three bee corridors are expected to be developed in the next financial year starting April 1.
- 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन बी कॉरिडोर विकसित किए जाने की संभावना है।
- The announcement was made by the Ministry of Road Transport and Highways.
- इसकी घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई।





Ques: Which two Central Public Sector Enterprises (CPSEs) signed an MoU to collaborate on thermal captive power and renewable energy projects?

थर्मल कैप्टिव पावर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग के लिए किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) National Aluminium Company Limited (NALCO) and Coal India Limited / नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और कोल इंडिया लिमिटेड
- B) National Aluminium Company Limited (NALCO) and NLC India Limited / नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड
- C) Hindustan Copper Limited and NLC India Limited / हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड
- D) Steel Authority of India Limited (SAIL) and NTPC / स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और एनटीपीसी
- E) National Aluminium Company Limited (NALCO) and NTPC / नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और एनटीपीसी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- National Aluminium Company Limited (NALCO), a Navratna Central Public Sector Enterprise, signed an MoU with NLC India Limited (NLCIL).
- नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- The MoU aims to strengthen collaboration on a 1080-MW Thermal Captive Power Project and renewable energy development.
- इस समझौते का उद्देश्य 1080 मेगावाट की थर्मल कैप्टिव पावर परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग को मजबूत करना है।
- NALCO is a Navratna CPSE under the Ministry of Mines and is a major player in bauxite, alumina, aluminium, and power generation.
- NALCO खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न CPSE है और बॉक्साइट, एल्यूमिना, एल्युमिनियम तथा विद्युत उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।
- NLC India Limited is a CPSE under the Ministry of Coal, engaged in lignite mining, thermal power generation, and renewable energy projects.





Ques: Why was Galgotias University removed from the India AI Impact Summit 2026?

गलगोटियास यूनिवर्सिटी को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से क्यों हटाया गया?

- A) Technical malfunction at the stall / स्टॉल पर तकनीकी खराबी
- B) Security violation / सुरक्षा उल्लंघन
- C) Presenting a Chinese-made robot as its own in-house innovation / चीनी निर्मित रोबोट को अपनी इन-हाउस नवाचार के रूप में प्रस्तुत करना
- D) Non-payment of participation fees / भागीदारी शुल्क का भुगतान न करना
- E) Political protest at the venue / स्थल पर राजनीतिक विरोध

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- Galgotias University was asked to vacate its stall at the India AI Impact Summit 2026 on February 18, 2026.
- गलगोटियास यूनिवर्सिटी को 18 फरवरी 2026 को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया।
- The action followed allegations that the university showcased the Chinese-manufactured robotic dog Unitree Go2 as its own in-house innovation under the name "Orion."
- यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि विश्वविद्यालय ने चीनी निर्मित रोबोटिक डॉग Unitree Go2 को "Orion" नाम से अपनी स्वयं की विकसित तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया।
- The controversy led to claims of misrepresentation, after which the university issued a clarification and apology stating there was no institutional intent to mislead.
- इस विवाद के बाद गलत प्रस्तुतीकरण के आरोप लगे और विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण व माफी जारी करते हुए कहा कि गलत जानकारी देने का कोई संस्थागत इरादा नहीं था।





Ques: The Shahpurkandi Dam is built on which river?

शाहपुरकंडी बांध किस नदी पर बनाया गया है?

- A) Chenab / चिनाब
- B) Ravi / रावी
- C) Jhelum / झेलम
- D) Beas / ब्यास
- E) Sutlej / सतलुज

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या :

- The Shahpurkandi Dam has been constructed on the Ravi River.
- शाहपुरकंडी बांध रावी नदी पर बनाया गया है।
- After its completion, additional water that earlier flowed into Pakistan will now be diverted for irrigation use in India.
- इसके पूरा होने के बाद, जो अतिरिक्त पानी पहले पाकिस्तान चला जाता था, अब उसे भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा।
- The dam is located on the Punjab–Jammu border and is expected to become operational soon.
- यह बांध पंजाब–जम्मू सीमा पर स्थित है और जल्द ही चालू होने की संभावना है।
- The project will significantly boost irrigation in Jammu and Kashmir (especially the Kathua region) and Punjab.
- यह परियोजना जम्मू-कश्मीर (विशेषकर कठुआ क्षेत्र) और पंजाब में सिंचाई को बढ़ावा देगी।
- Work on such projects has accelerated following developments related to the Indus Waters Treaty.
- इस प्रकार की परियोजनाओं पर कार्य सिंधु जल संधि से संबंधित घटनाओं के बाद तेज हुआ है





Ques: The Centre for Development of Telematics (C-DOT) signed a landmark MoU with which institution to promote telecom innovation and cybersecurity research?

दूरसंचार विकास केंद्र (C-DOT) ने दूरसंचार नवाचार और साइबर सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Indian Institute of Technology Delhi / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
- B) Rashtriya Raksha University / राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
- C) National Defence College / राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज
- D) Indian Institute of Science / भारतीय विज्ञान संस्थान
- E) National Institute of Electronics & IT / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Centre for Development of Telematics (C-DOT), under the Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications, signed a landmark MoU with Rashtriya Raksha University (RRU).
- दूरसंचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत C-DOT ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के साथ एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए।
- The collaboration focuses on promoting telecom innovation and advanced cybersecurity research.
- यह सहयोग दूरसंचार नवाचार और उन्नत साइबर सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- A key initiative under the MoU is the establishment of an Innovation-cum-Experience Centre at RRU.
- MoU के तहत RRU में एक इनोवेशन-कम-एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- The centre will deploy TRINETRA, a unified AI-powered cyber security solution developed indigenously by C-DOT.
- इस केंद्र में C-DOT द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित TRINETRA नामक एकीकृत AI-संचालित साइबर सुरक्षा समाधान तैनात किया जाएगा।
- Rashtriya Raksha University is an Institution of National Importance under the Ministry of Home Affairs, focusing on internal security, cyber defence, national security studies, and technology-driven security solutions.





Ques: What was the theme of the 18th Foundation Day of the National Statistical Systems Training Academy (NSSTA)?

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA) के 18वें स्थापना दिवस का विषय क्या था?

- A) Strengthening Digital Governance for India / भारत के लिए डिजिटल शासन को सशक्त बनाना
- B) Reimagining Capacity Building for Official Statistics to achieve Vision of Viksit Bharat@2047 / विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना
- C) Data-Driven Growth for Atmanirbhar Bharat / आत्मनिर्भर भारत के लिए डेटा-आधारित विकास
- D) Modernising Statistical Systems for Global Competitiveness / वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सांख्यिकी प्रणालियों का आधुनिकीकरण
- E) Inclusive Development through Evidence-Based Policy / साक्ष्य-आधारित नीति के माध्यम से समावेशी विकास

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The National Statistical Systems Training Academy (NSSTA), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation, celebrated its 18th Foundation Day.
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA) ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया।
- The theme of the Foundation Day was “Reimagining Capacity Building for Official Statistics to achieve Vision of Viksit Bharat@2047.”
- स्थापना दिवस का विषय था “विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना।”
- NSSTA was established to strengthen India’s National Statistical System (NSS) by enhancing skills and capacities in official statistics.
- NSSTA की स्थापना भारत की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (NSS) को सुदृढ़ करने हेतु आधिकारिक सांख्यिकी में कौशल और क्षमता विकास के लिए की गई थी।





Ques: Why did the Government of India lift the wheat export ban after four years?

भारत सरकार ने चार वर्षों बाद गेहूं निर्यात प्रतिबंध क्यों हटाया?

- A) To control domestic inflation only / केवल घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए
- B) Due to surplus production and to ensure remunerative prices for farmers / अधिशेष उत्पादन और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए
- C) To meet WTO obligations / डब्ल्यूटीओ दायित्वों को पूरा करने के लिए
- D) Due to decline in wheat acreage / गेहूं के रकबे में गिरावट के कारण
- E) To reduce buffer stock costs / बफर स्टॉक लागत कम करने के लिए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India lifted the wheat export ban after four years due to comfortable domestic availability and to ensure remunerative prices for farmers.
- भारत सरकार ने घरेलू उपलब्धता संतोषजनक होने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चार वर्षों बाद गेहूं निर्यात प्रतिबंध हटाया।
- Wheat is a Rabi crop grown mainly in tropical, sub-tropical and temperate regions.
- गेहूं एक रबी फसल है, जिसे उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- It requires cool and moist weather during the vegetative growth period, followed by dry and warm weather for grain maturity and ripening.
- इसके लिए वृद्धि अवधि में ठंडा और नम मौसम तथा दाने के पकने के लिए शुष्क और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।
- The optimum temperature for wheat cultivation is 20–25°C with ideal rainfall of 50–75 cm.
- गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 20–25 डिग्री सेल्सियस और उपयुक्त वर्षा 50–75 सेमी होती है।
- India is the world's second-largest producer of wheat, contributing around 14% of global output, and has the largest area under wheat cultivation.
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 14% योगदान देता है और इसके पास गेहूं का सबसे बड़ा रकबा है।
- The top wheat-producing states in India are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Punjab.





Ques: When is GalaxEye's 'Mission Drishti' scheduled to be launched?

GalaxEye का 'Mission Drishti' कब लॉन्च किया जाएगा?

- A) 2024
- B) 2025
- C) 2026
- D) 2027
- E) 2028

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या :

- GalaxEye has announced that its upcoming satellite mission 'Mission Drishti' is scheduled for launch in 2026.
- GalaxEye ने घोषणा की है कि उसका सैटेलाइट मिशन 'Mission Drishti' वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा।
- The satellite will integrate Nvidia's Jetson Orin GPU architecture to enable advanced AI processing directly in orbit.
- इस सैटेलाइट में Nvidia का Jetson Orin GPU आर्किटेक्चर शामिल होगा, जिससे कक्षा में ही उन्नत AI प्रोसेसिंग संभव होगी।
- It aims to enhance real-time processing and delivery of Earth observation data and will feature GalaxEye's SyncFused OptoSAR architecture.
- इसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन डेटा की रियल-टाइम प्रोसेसिंग और विश्लेषण को बेहतर बनाना है, साथ ही इसमें SyncFused OptoSAR आर्किटेक्चर शामिल होगा।
- The announcement was made at the IndiaAI Impact Summit 2026 in New Delhi.
- इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित IndiaAI Impact Summit 2026 में की गई।





Ques: Which of the following are the Umbrella Missions of the Ministry of Women & Child Development (MWCD)?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की अम्ब्रेला मिशनों निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?

- A) Mission Saksham Anganwadi & Poshan 2.0, Mission Shakti, Mission Vatsalya / मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य
- B) Mission Poshan Abhiyaan, Mission Swachh Bharat, Mission Vatsalya / मिशन पोषण अभियान, मिशन स्वच्छ भारत, मिशन वात्सल्य
- C) Mission Shakti, Mission Jal Jeevan, Mission Poshan 2.0 / मिशन शक्ति, मिशन जल जीवन, मिशन पोषण 2.0
- D) Mission Saksham Anganwadi, Mission Ayushman Bharat, Mission Vatsalya / मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन आयुष्मान भारत, मिशन वात्सल्य
- E) Mission Poshan Abhiyaan, Mission Beti Bachao Beti Padhao, Mission Vatsalya / मिशन पोषण अभियान, मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन वात्सल्य

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Women & Child Development (MWCD) implements three Umbrella Missions to streamline and strengthen women- and child-centric schemes.
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं को सुदृढ़ करने हेतु तीन अम्ब्रेला मिशनों का क्रियान्वयन करता है।

1. Mission Saksham Anganwadi & Poshan 2.0

(Also known as Mission Poshan 2.0)

- Objective: Improve nutrition and health indicators of women, children, and adolescent girls.
- उद्देश्य: महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार।
- Key Components (Reorganisation of):
 - Anganwadi Services
 - POSHAN Abhiyaan
 - Scheme for Adolescent Girls





2. Mission Shakti

- Objective: Ensure safety, security, and empowerment of women.
- उद्देश्य: महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
- It has two verticals:

A. Sambal (Safety & Protection)

- One Stop Centres (OSC)
- Women Helpline (181)
- Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)
- Nari Adalat

B. Samarthya (Empowerment)

- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)
- Shakti Sadan
- Sakhi Niwas
- National Hub for Empowerment of Women (NHEW)
- Palna (Crèche Facility)

3. Mission Vatsalya

- Focus: Protection, care, and welfare of children in difficult circumstances.
- फोकस: कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और कल्याण।
- Includes:
 - Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
- Objectives:
 - Support children in difficult circumstances
 - Provide holistic development
 - Encourage innovation
 - Ensure convergence across departments

Evaluation & Monitoring

- A third-party evaluation of these missions (FY 2019–2024) was conducted by NITI Aayog.
- The study found the schemes to be relevant, impactful, and well-aligned with national development goals.





Ques: Which event will be hosted by the Indian Army as the first-ever international military adventure competition in February 2026?

फरवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा पहली बार आयोजित किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक प्रतियोगिता कार्यक्रम कौन-सा है?

- A) International Mountain Warfare Cup / अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय युद्ध कप
- B) International Military Adventure Challenge Cup (IMACC) / अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप
- C) Global Armed Forces Endurance Meet / वैश्विक सशस्त्र बल सहनशक्ति प्रतियोगिता
- D) Himalayan Joint Military Games / हिमालय संयुक्त सैन्य खेल
- E) International Defence Sports Championship / अंतरराष्ट्रीय रक्षा खेल चैम्पियनशिप

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Indian Army will host the first-ever International Military Adventure Challenge Cup (IMACC) 2026 from 18–23 February 2026.
- भारतीय सेना 18 से 23 फरवरी 2026 तक पहली बार अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप (IMACC) 2026 की मेजबानी करेगी।
- The event will be held in the foothills of the Eastern Himalayas.
- यह आयोजन पूर्वी हिमालय की तलहटी में आयोजित किया जाएगा।
- The objective of IMACC is to enhance military cooperation, build camaraderie, and test soldiers' endurance in challenging mountainous terrain.
- IMACC का उद्देश्य सैन्य सहयोग बढ़ाना, आपसी सौहार्द विकसित करना और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में सैनिकों की सहनशक्ति का परीक्षण करना है।
- Military teams from seven friendly foreign nations will participate: Bhutan, Brazil, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Sri Lanka, and Saudi Arabia.
- सात मित्र देशों की सैन्य टीमों में भाग लेंगी: भूटान, ब्राज़ील, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब।
- Indian participants will include the Indian Army, Indian Air Force, Indian Coast Guard, and Indo-Tibetan Border Police (ITBP).
- भारतीय प्रतिभागियों में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) शामिल होंगे।





Ques: How much Special Economic Package did India announce during the visit of Seychelles President Dr. Patrick Herminie?

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा के दौरान भारत ने कितने मूल्य का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया?

- A) USD 100 million
- B) USD 150 million
- C) USD 175 million
- D) USD 200 million
- E) USD 250 million

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- Patrick Herminie, President of Seychelles, visited India on his first official visit since assuming office in 2025. The visit coincided with the 50th anniversary of India–Seychelles diplomatic relations (1976–2026).
- सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा की। यह यात्रा भारत–सेशेल्स कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ (1976–2026) के अवसर पर हुई।
- India announced a USD 175 million Special Economic Package, including:
 - USD 125 million Line of Credit (low-interest loan)
 - USD 50 million Grant Assistance (free aid)
- भारत ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया, जिसमें:
 - 125 मिलियन डॉलर की रियायती ऋण सहायता
 - 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता शामिल है।
- Key assistance included 10 ambulances, 1,000 metric tonnes of grains & lentils, refit of petrol ship Zoraster, 10 utility vehicles, and 5 Laser Radial boats.
- प्रमुख सहायता में 10 एंबुलेंस, 1,000 मीट्रिक टन अनाज व दालें, पेट्रोल पोत Zoraster का निःशुल्क पुनर्निर्माण, 10 यूटिलिटी वाहन और 5 लेजर रेडियल नौकाएं शामिल हैं।
- Both nations adopted the India–Seychelles Joint Vision for Sustainability, Economic Growth and Security through Enhanced Linkages (SESEL Vision) to deepen cooperation in health, digital infrastructure, maritime security, environment, and





culture.

- दोनों देशों ने स्वास्थ्य, डिजिटल अवसंरचना, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु SESEL संयुक्त विजन को अपनाया।
- Seychelles also expressed support for India's MAHASAGAR (Maritime Heads for Active Security and Growth for All in the Region) initiative.
- सेशेल्स ने भारत की MAHASAGAR समुद्री पहल का समर्थन भी व्यक्त किया।



EXAM
Genius





Ques: From which date are bank loans to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) for on-lending to cooperative societies eligible for Priority Sector Lending (PSL) classification?

किस तिथि से सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

- A) 1 April 2025 / 1 अप्रैल 2025
- B) 1 July 2025 / 1 जुलाई 2025
- C) 19 January 2026 / 19 जनवरी 2026
- D) 1 April 2026 / 1 अप्रैल 2026
- E) 26 January 2026 / 26 जनवरी 2026

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, announced that loans sanctioned by banks to the National Cooperative Development Corporation for on-lending to cooperative societies will be eligible for Priority Sector Lending classification with effect from 19 January 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह घोषणा की कि सहकारी समितियों को ऑन-लेंडिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण 19 जनवरी 2026 से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में मान्य होंगे।
- This PSL classification applies to banks other than Regional Rural Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, and Local Area Banks.
- यह प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और लोकल एरिया बैंकों पर लागू नहीं होगा।
- Urban Cooperative Banks have been permitted to open new branches, and their housing loan limit has been enhanced from 10% to 25% of total loans and advances.
- शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी गई है तथा उनके आवास ऋण की सीमा कुल ऋण एवं अग्रिमों के 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।
- The Banking Regulation Act has been amended to increase the tenure of directors of Cooperative Banks from 8 years to 10 years.
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन कर सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10





वर्ष कर दिया गया है।

- The National Urban Co-operative Finance and Development Corporation Limited has been established as an umbrella organisation for Urban Cooperative Banks to provide IT infrastructure and operational support.
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी अवसंरचना और परिचालन सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है।
- A Shared Services Entity named Sahakar Sarthi has been set up to provide technological services to Rural Cooperative Banks, and these banks have been included under the Integrated Ombudsman Scheme of RBI.
- ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी सेवाएँ देने के लिए 'सहकार सारथी' नामक साझा सेवा इकाई स्थापित की गई है तथा इन्हें RBI की एकीकृत लोकपाल योजना में शामिल किया गया है।

EXAM
Genius





Ques : RBI has deferred implementation of Unique Transaction Identifier (UTI) for OTC derivatives till which date?

RBI ने OTC डेरिवेटिव्स के लिए UTI लागू करने की समयसीमा किस तिथि तक टाली है?

- A) January 1, 2026 / 1 जनवरी 2026
- B) July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026
- C) January 1, 2027 / 1 जनवरी 2027
- D) March 31, 2027 / 31 मार्च 2027
- E) December 31, 2026 / 31 दिसंबर 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has deferred the implementation of the Unique Transaction Identifier (UTI) for all Over-the-Counter (OTC) derivatives to January 1, 2027.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी OTC डेरिवेटिव्स के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी (UTI) लागू करने की समयसीमा 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है।
- The UTI system will help regulators obtain a comprehensive view of the OTC derivatives market and enhance transparency.
- UTI प्रणाली से नियामकों को OTC डेरिवेटिव्स बाजार की समग्र जानकारी प्राप्त होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- The mandate will apply to transactions entered into on or after January 1, 2027.
- यह अनिवार्यता 1 जनवरी 2027 या उसके बाद किए गए लेनदेन पर लागू होगी।
- Currently, OTC transactions are reported to the Trade Repository managed by Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR).
- वर्तमान में OTC लेनदेन की रिपोर्टिंग Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR) द्वारा संचालित ट्रेड रिपॉजिटरी में की जाती है।
- Covered instruments include rupee interest rate derivatives, forward contracts in government securities, foreign currency derivatives, foreign currency interest rate derivatives, and credit derivatives.
- इसमें रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स, सरकारी प्रतिभूतियों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स, विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स शामिल हैं।





Ques: DBS Bank Limited partnered with Visa to pilot agent-initiated payments under which innovative payment framework?

डीबीएस बैंक लिमिटेड ने एजेंट-इनिशिएटेड पेमेंट्स के पायलट के लिए वीज़ा के साथ किस नवोन्मेषी भुगतान ढांचे के तहत साझेदारी की है?

- A) Visa Secure Pay / वीज़ा सिक्क्योर पे
- B) Visa Token Service / वीज़ा टोकन सेवा
- C) Visa Intelligent Commerce (VIC) / वीज़ा इंटेलिजेंट कॉमर्स
- D) Visa Direct / वीज़ा डायरेक्ट
- E) Visa PayWave AI / वीज़ा पेवेव एआई

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- DBS Bank Limited, Southeast Asia's largest lender, entered into a strategic partnership with Visa to pilot agent-initiated payments under Visa Intelligent Commerce (VIC).
- दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे बड़े बैंक DBS बैंक लिमिटेड ने वीज़ा के साथ Visa Intelligent Commerce (VIC) के तहत एजेंट-इनिशिएटेड भुगतान के पायलट के लिए रणनीतिक साझेदारी की।
- With this initiative, DBS became the first issuer in the Asia-Pacific region to operationalise real-world agentic commerce use cases.
- इस पहल के साथ DBS एशिया-प्रशांत क्षेत्र का पहला जारीकर्ता बना जिसने वास्तविक दुनिया में एजेंटिक कॉमर्स उपयोग-मामलों को लागू किया।
- Visa Intelligent Commerce (VIC) is a payment framework that enables AI agents to securely initiate and complete transactions on behalf of consumers.
- Visa Intelligent Commerce (VIC) एक भुगतान ढांचा है जो उपभोक्ताओं की ओर से AI एजेंट्स को सुरक्षित रूप से लेन-देन शुरू करने और पूरा करने में सक्षम बनाता है।
- Under the pilot, AI agents completed food and beverage purchases using DBS/POSB credit and debit cards, with payments processed through secure, issuer-approved flows.
- इस पायलट के तहत AI एजेंट्स ने DBS/POSB क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके खाद्य एवं पेय पदार्थों की खरीद की, जिनके भुगतान सुरक्षित और जारीकर्ता-स्वीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से किए गए।
- Explicit customer consent was maintained throughout the transactions.





Ques: What is FiMI launched by NPCI?

NPCI द्वारा लॉन्च किया गया FiMI क्या है?

- A) A new UPI payment app / एक नया UPI पेमेंट ऐप
- B) A blockchain-based settlement system / ब्लॉकचेन आधारित सेटलमेंट सिस्टम
- C) A domain-specific AI language model for payments / भुगतान प्रणाली के लिए डोमेन-विशिष्ट AI भाषा मॉडल
- D) A new digital wallet / एक नया डिजिटल वॉलेट
- E) A credit scoring platform / एक क्रेडिट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- National Payments Corporation of India (NPCI) launched FiMI (Finance Model for India) at the India–AI Impact Summit 2026.
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने India–AI Impact Summit 2026 में FiMI (फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया) लॉन्च किया।
- FiMI is a domain-specific language model built specifically for India's payments ecosystem.
- FiMI एक डोमेन-विशिष्ट भाषा मॉडल है, जिसे भारत की भुगतान प्रणाली के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है।
- Developed in-house by NPCI, it addresses limitations of general-purpose LLMs in high-scale, high-trust payment workflows.
- इसे NPCI ने इन-हाउस विकसित किया है और यह सामान्य LLMs की सीमाओं को दूर करता है, खासकर उच्च-स्तरीय और भरोसेमंद भुगतान प्रक्रियाओं में।
- FiMI currently powers NPCI's UPI Help Assistant, an AI-powered conversational support system for UPI users.
- FiMI वर्तमान में NPCI के UPI हेल्प असिस्टेंट को संचालित करता है, जो UPI उपयोगकर्ताओं के लिए AI आधारित संवादात्मक सहायता प्रणाली है।
- It supports transaction dispute handling, mandate lifecycle management, and regulatory queries.
- यह लेन-देन विवाद समाधान, मंडेट प्रबंधन और नियामकीय प्रश्नों का समाधान करता है।
- The assistant currently supports English, Hindi, Telugu, and Bengali.





Ques: Which entity received RBI approval to acquire up to 9.95% stake in eight Indian banks?

किस संस्था को आठ भारतीय बैंकों में 9.95% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की मंजूरी मिली?

- A) HDFC Asset Management Company / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- B) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड
- C) ICICI Prudential Asset Management Company / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- D) Axis Asset Management Company / एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी
- E) Kotak Mahindra Asset Management Company / कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Prudential Asset Management Company, along with group entities of ICICI Bank, received approval from the Reserve Bank of India to acquire up to 9.95% of the paid-up share capital or voting rights in eight Indian banks.
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक समूह की इकाइयों के साथ आठ भारतीय बैंकों में 9.95% तक चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली।
- The banks covered under this approval are Bandhan Bank, City Union Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank, IDFC First Bank, HDFC Bank, Karur Vysya Bank, and RBL Bank.
- इस मंजूरी के तहत बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक और RBL बैंक शामिल हैं।
- The approval is valid for one year and requires completion of major shareholding within this period.
- यह मंजूरी एक वर्ष के लिए वैध है और इस अवधि में प्रमुख हिस्सेदारी पूरी करनी होगी।
- The aggregate holding must remain below 9.95% at all times.
- कुल हिस्सेदारी हर समय 9.95% से कम रखनी होगी।
- If the stake falls below 5% and is later increased again, fresh approval from RBI will be mandatory.





Ques: What is the minimum FD amount required to obtain IDFC First Bank's Hello Cashback Credit Card?

IDFC फर्स्ट बैंक के हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए न्यूनतम FD राशि कितनी है?

- A) ₹5,000
- B) ₹10,000
- C) ₹15,000
- D) ₹25,000
- E) ₹50,000

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- IDFC First Bank has launched the Hello Cashback Credit Card, an FD-backed credit card.
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो FD-आधारित क्रेडिट कार्ड है।
- The card is aimed at first-time users and customers with no credit history.
- यह कार्ड पहली बार क्रेडिट लेने वाले और बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों के लिए बनाया गया है।
- Customers need to open a minimum FD of ₹10,000 to get the card.
- ग्राहकों को कार्ड प्राप्त करने के लिए कम से कम ₹10,000 की FD खोलनी होगी।
- The credit limit is 100% of the FD amount.
- क्रेडिट लिमिट FD राशि का 100% होगी।
- The card is issued on the RuPay network.
- यह कार्ड RuPay नेटवर्क पर जारी किया गया है।
- Founded: October 2015 | Headquarters: Mumbai | CEO: V. Vaidyanathan.
- स्थापना: अक्टूबर 2015 | मुख्यालय: मुंबई | सीईओ: वी. वैद्यनाथन।





Ques: What was India's factory-gate inflation (Wholesale Price Index – WPI) in January 2026, as per data released by the Ministry of Commerce and Industry?

जनवरी 2026 में भारत की फैक्ट्री-गेट महंगाई (थोक मूल्य सूचकांक – WPI) कितनी रही, जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया?

- A) 0.95%
- B) 1.25%
- C) 1.81%
- D) 2.40%
- E) 3.20%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's factory-gate inflation, measured by the Wholesale Price Index (WPI), rose to 1.81% in January 2026, marking a 10-month high.
- भारत की फैक्ट्री-गेट महंगाई, जिसे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से मापा जाता है, जनवरी 2026 में बढ़कर 1.81% हो गई, जो 10 महीनों का उच्चतम स्तर है।
- The data was released by the Ministry of Commerce and Industry.
- यह आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।
- The rise in WPI inflation was mainly driven by:
 - Pickup in food prices
 - Sharp increase in core inflation
- WPI में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य कीमतों में तेजी और कोर महंगाई में तीव्र बढ़ोतरी रही।
- Food inflation increased to 1.4% in January 2026, after remaining flat on a year-on-year basis in December 2025.
- खाद्य महंगाई दिसंबर 2025 में स्थिर रहने के बाद जनवरी 2026 में बढ़कर 1.4% हो गई।
- Core inflation (excluding food and fuel) rose sharply to 3.2% in January 2026.
- कोर महंगाई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) जनवरी 2026 में तेजी से बढ़कर 3.2% हो गई।
- The current WPI base year is 2011–12, and the upcoming GDP series with base year 2022–23 will continue to use the existing WPI as deflators.
- वर्तमान WPI का आधार वर्ष 2011–12 है और आगामी 2022–23 आधार वर्ष वाली GDP श्रृंखला में भी WPI को डिफ्लेटर के रूप में उपयोग किया जाएगा।





Ques: India is conducting a joint in-situ air exercise with which country's air force?

भारत किस देश की वायु सेना के साथ संयुक्त इन-सीटू हवाई अभ्यास कर रहा है?

- A) Vietnam / वियतनाम
- B) Indonesia / इंडोनेशिया
- C) Thailand / थाईलैंड
- D) Malaysia / मलेशिया
- E) Philippines / फिलीपींस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या :

- The Indian Air Force (IAF) and the Royal Thai Air Force are conducting a joint in-situ air exercise to enhance operational coordination and interoperability.
- भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल थाई वायु सेना संयुक्त इन-सीटू हवाई अभ्यास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य परिचालन समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है।
- The exercise focuses on testing how well different aircraft systems and pilots coordinate and communicate during real missions.
- यह अभ्यास विभिन्न विमान प्रणालियों और पायलटों के बीच समन्वय और संचार क्षमता को परखने पर केंद्रित है।
- It also aims to strengthen the defence partnership between India and Thailand.
- इसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है।
- An "in-situ" exercise means training is conducted in real-world operational locations rather than simulators or isolated bases.
- "इन-सीटू" अभ्यास का अर्थ है कि प्रशिक्षण वास्तविक परिचालन स्थलों पर किया जाता है, न कि सिमुलेटर या अलग-थलग बेस पर।

About Thailand :

- Capital : Bangkok
- Prime Minister : Anutin Charnvirakul
- Currency : Thai Baht





Ques: In PM Modi's MANAV Vision for AI, what does 'N' stand for?

पीएम मोदी के MANAV विज़न में 'N' किसका प्रतिनिधित्व करता है?

- A) Neutral Systems / न्यूट्रल सिस्टम्स
- B) National Sovereignty / राष्ट्रीय संप्रभुता
- C) New Technology / नई तकनीक
- D) Network Governance / नेटवर्क गवर्नेंस
- E) Natural Intelligence / प्राकृतिक बुद्धिमत्ता

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Narendra Modi unveiled India's comprehensive "MANAV Vision" for Artificial Intelligence at the India AI Impact Summit 2026.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत का व्यापक 'MANAV विज़न' प्रस्तुत किया।
- The vision promotes a human-centric, ethical, accountable and inclusive AI framework.
- यह विज़न मानव-केंद्रित, नैतिक, जवाबदेह और समावेशी AI ढांचे को बढ़ावा देता है।
- M – Moral & Ethical Systems: AI should be guided by ethical principles.
- M – नैतिक प्रणाली: AI नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो।
- A – Accountable Governance: Transparent rules and strong oversight mechanisms.
- A – जवाबदेह शासन: पारदर्शी नियम और मजबूत निगरानी व्यवस्था।
- N – National Sovereignty: "Whose data, his right" – data ownership and sovereignty.
- N – राष्ट्रीय संप्रभुता: "जिसका डेटा, उसका अधिकार" – डेटा पर स्वामित्व।
- A – Accessible & Inclusive: AI should empower all, not create monopolies.
- A – सुलभ और समावेशी: AI सभी के लिए अवसर बढ़ाए, एकाधिकार न बनाए।
- V – Valid & Legitimate: AI systems must be lawful and verifiable.
- V – वैध और विधिसम्मत: AI प्रणाली कानूनी और सत्यापन योग्य हो।
- PM emphasized that welfare and happiness of all should be the benchmark for AI development.
- पीएम ने कहा कि AI विकास का मानक सभी का कल्याण और सुख होना चाहिए।





Ques: India has become the world's second-largest active installed base of smartphones, ranking just behind which country?

भारत स्मार्टफोन के सक्रिय इंस्टॉल्ड बेस के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है?

- A) United States / संयुक्त राज्य अमेरिका
- B) Japan / जापान
- C) South Korea / दक्षिण कोरिया
- D) China / चीन
- E) Germany / जर्मनी

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India has officially become the second-largest active installed base of smartphones in the world, standing just behind China.
- भारत आधिकारिक रूप से स्मार्टफोन के सक्रिय इंस्टॉल्ड बेस के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- India currently has over 740 million active smartphones in use.
- भारत में इस समय 740 मिलियन से अधिक सक्रिय स्मार्टफोन उपयोग में हैं।
- This indicates that more than half of India's population of about 1.45 billion people actively uses a smartphone.
- इसका अर्थ है कि भारत की लगभग 1.45 अरब की आबादी में से आधे से अधिक लोग सक्रिय रूप से स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।
- Indian users retain their smartphones for around 42 months on average, which is slightly lower than the global average of 47 months.
- भारतीय उपभोक्ता औसतन लगभग 42 महीनों तक स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जो वैश्विक औसत 47 महीनों से थोड़ा कम है।
- This shows that Indian consumers typically upgrade their smartphones roughly every 3.5 years.
- इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय उपभोक्ता लगभग हर 3.5 वर्ष में अपने स्मार्टफोन अपग्रेड करते हैं।





Ques: Where was the 23rd edition of BioAsia 2026 held?

बायोएशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ?

- A) Bengaluru / बेंगलुरु
- B) Mumbai / मुंबई
- C) Hyderabad / हैदराबाद
- D) Chennai / चेन्नई
- E) Pune / पुणे

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The 23rd edition of BioAsia 2026 was held in Hyderabad, Telangana at the Hyderabad International Convention Centre (HICC).
- बायोएशिया 2026 का 23वां संस्करण तेलंगाना के हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में आयोजित हुआ।
- The summit was inaugurated by A. Revanth Reddy.
- शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने किया।
- BioAsia is an annual international life sciences conference hosted by the Government of Telangana.
- बायोएशिया तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय जीवन विज्ञान सम्मेलन है।
- Theme: "TechBio Unleashed – AI, Automation, and Revolutionary Changes in Life Sciences."
- विषय: "टेकबायो अनलीशड – एआई, ऑटोमेशन और लाइफ साइंसेज में क्रांतिकारी बदलाव।"
- Focus areas included use of Artificial Intelligence (AI) in drug discovery, automation in biotechnology & healthcare innovation, and strengthening global collaboration in the life sciences sector.
- मुख्य फोकस क्षेत्रों में औषधि खोज में एआई का उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सेवा में ऑटोमेशन और जीवन विज्ञान क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना शामिल था।





Ques: Dubai-based telecom company du has partnered with Datawave Networks Limited to invest in which submarine cable system creating a direct East–West digital corridor?

दुबई स्थित टेलीकॉम कंपनी du ने डायरेक्ट ईस्ट–वेस्ट डिजिटल कॉरिडोर बनाने के लिए Datawave Networks Limited के साथ किस सबमरीन केबल सिस्टम में निवेश हेतु साझेदारी की है?

- A) SEA-ME-WE 6 Cable System / सी-मी-वी 6 केबल सिस्टम
- B) Asia-Africa-Europe (AAE-1) Cable / एशिया-अफ्रीका-यूरोप केबल
- C) Singapore-India-Gulf (SING) Cable System / सिंगापुर–भारत–गल्फ (SING) केबल सिस्टम
- D) India-Europe Express (IEX) Cable / इंडिया–यूरोप एक्सप्रेस केबल
- E) Bay of Bengal Gateway (BBG) Cable / बे ऑफ बंगाल गेटवे केबल

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Dubai-based telecom and digital services provider du (Emirates Integrated Telecommunications Company) entered into a strategic partnership with Datawave Networks Limited to land and invest in the Singapore–India–Gulf (SING) submarine cable system.
- दुबई स्थित टेलीकॉम और डिजिटल सेवा प्रदाता du ने Singapore–India–Gulf (SING) सबमरीन केबल सिस्टम में निवेश और लैंडिंग के लिए Datawave Networks Limited के साथ रणनीतिक साझेदारी की।
- The SING cable system will connect Kalba (UAE), Muscat (Oman), Mumbai and Chennai (India), Kedah (Malaysia), and Singapore, establishing a direct East–West digital corridor.
- SING केबल सिस्टम काल्बा (यूएई), मस्कट (ओमान), मुंबई और चेन्नई (भारत), केदाह (मलेशिया) और सिंगापुर को जोड़ेगा, जिससे एक सीधा ईस्ट–वेस्ट डिजिटल कॉरिडोर बनेगा।
- The design, manufacture, and deployment of the cable will be carried out by SubCom, which is owned by Cerberus Capital Management.
- इस केबल का डिज़ाइन, निर्माण और परिनियोजन SubCom द्वारा किया जाएगा, जो Cerberus Capital Management के स्वामित्व में है।
- The financing agreement for the project was signed in January 2026, and the cable system is targeted to be Ready for Service (RFS) by 2030.





Ques: Who developed the Ol Chiki script for the Santhali language?

संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का विकास किसने किया?

- A) Birsa Munda / बिरसा मुंडा
- B) Pandit Raghunath Murmu / पंडित रघुनाथ मुर्मु
- C) Jaipal Singh Munda / जयपाल सिंह मुंडा
- D) Raghunandan Prasad / रघुनंदन प्रसाद
- E) Shibu Soren / शिबू सोरेन

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- President Droupadi Murmu inaugurated the Centenary Celebration of the Ol Chiki script in New Delhi.
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।
- On the occasion, she released a commemorative coin and a postage stamp marking 100 years of the script.
- इस अवसर पर उन्होंने लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।
- Ol Chiki script was developed in 1925 by Pandit Raghunath Murmu specifically for the Santhali language.
- ओल चिकी लिपि का विकास 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मु द्वारा विशेष रूप से संथाली भाषा के लिए किया गया था।
- The script consists of 30 letters, designed to accurately represent Santhali phonetics.
- इस लिपि में 30 अक्षर हैं, जो संथाली उच्चारण को सटीक रूप से दर्शाते हैं।
- Santhali language was included in the Eighth Schedule of the Constitution in 2003.
- संथाली भाषा को 2003 में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- Ol Chiki is the official script of the Santhali language, widely spoken in Jharkhand, Odisha, West Bengal, Assam, and Bihar.
- ओल चिकी, संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है, जो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में व्यापक रूप से बोली जाती है।
- Recently, the President also released the Constitution of India in Santhali language, written in the Ol Chiki script.
- हाल ही में राष्ट्रपति ने ओल चिकी लिपि में लिखित संथाली भाषा में भारतीय संविधान भी जारी किया।





Ques: Where was the two-day International Conference on Dam Safety (ICDS) 2026, held on 13–14 February 2026, concluded?

13–14 फरवरी 2026 को आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन (ICDS) 2026 का समापन कहाँ हुआ?

- A) New Delhi / नई दिल्ली
- B) Hyderabad / हैदराबाद
- C) Bengaluru / बेंगलुरु
- D) Chennai / चेन्नई
- E) Pune / पुणे

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The two-day International Conference on Dam Safety (ICDS) 2026 concluded in Bengaluru on 13–14 February 2026.
- दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन (ICDS) 2026 का समापन 13–14 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में हुआ।
- The inaugural and plenary sessions highlighted India's evolving dam safety framework under the Dam Safety Act, 2021 and the Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP).
- उद्घाटन और पूर्ण सत्रों में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) के तहत भारत की विकसित होती बांध सुरक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया।
- Key themes of the conference included climate resilience in dam operations, coordinated reservoir management, institutional capacity building, and strengthening regulatory oversight.
- सम्मेलन के प्रमुख विषयों में बांध संचालन में जलवायु लचीलापन, समन्वित जलाशय प्रबंधन, संस्थागत क्षमता निर्माण और नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करना शामिल था।





Ques: As per DGCA's proposed amendments, airlines can directly impose a flying ban for up to how many days on unruly passengers?

DGCA के प्रस्ताव के अनुसार, एयरलाइंस अनुशासनहीन यात्रियों पर सीधे अधिकतम कितने दिनों का फ्लाईंग बैन लगा सकती हैं?

- A) 7 days
- B) 15 days
- C) 30 days
- D) 45 days
- E) 60 days

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has proposed stricter norms to deal with unruly passengers.
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अनुशासनहीन यात्रियों से निपटने के लिए सख्त नियम प्रस्तावित किए हैं।
- Airlines may be allowed to directly impose a flying ban of up to 30 days without referring the matter to an independent committee.
- एयरलाइंस को बिना स्वतंत्र समिति के पास मामला भेजे सीधे 30 दिनों तक का फ्लाईंग बैन लगाने की अनुमति दी जा सकती है।
- Proposed amendments are under the Civil Aviation Requirement (CAR) provisions.
- प्रस्तावित संशोधन सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत किए जाएंगे।
- Disruptive acts include smoking onboard, consuming alcohol on domestic flights, tampering with emergency exits, engaging in protests/sloganeering, and unruly behaviour due to intoxication.
- अनुशासनहीन कृत्यों में विमान में धूम्रपान, घरेलू उड़ानों में शराब सेवन, इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़, नारेबाजी/विरोध प्रदर्शन और नशे की हालत में दुर्व्यवहार शामिल हैं।
- Airlines must inform DGCA about bans and maintain a passenger database.
- एयरलाइंस को प्रतिबंध की जानकारी DGCA को देनी होगी और यात्रियों का डाटाबेस रखना होगा।
- However, such passengers will not automatically be added to the official No-Fly List.
- हालांकि, ऐसे यात्रियों को आधिकारिक नो-फ्लाई सूची में स्वतः शामिल नहीं किया जाएगा।





Ques: 'White Revolution 2.0', recently launched by the Ministry of Cooperation, aims to increase milk procurement by dairy cooperatives to what level by 2028–29?

सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'श्वेत क्रांति 2.0' के अंतर्गत 2028–29 तक डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध संग्रह को किस स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है?

- A) 850 lakh kg per day / 850 लाख किलोग्राम प्रतिदिन
- B) 900 lakh kg per day / 900 लाख किलोग्राम प्रतिदिन
- C) 950 lakh kg per day / 950 लाख किलोग्राम प्रतिदिन
- D) 1,007 lakh kg per day / 1,007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन
- E) 1,200 lakh kg per day / 1,200 लाख किलोग्राम प्रतिदिन

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

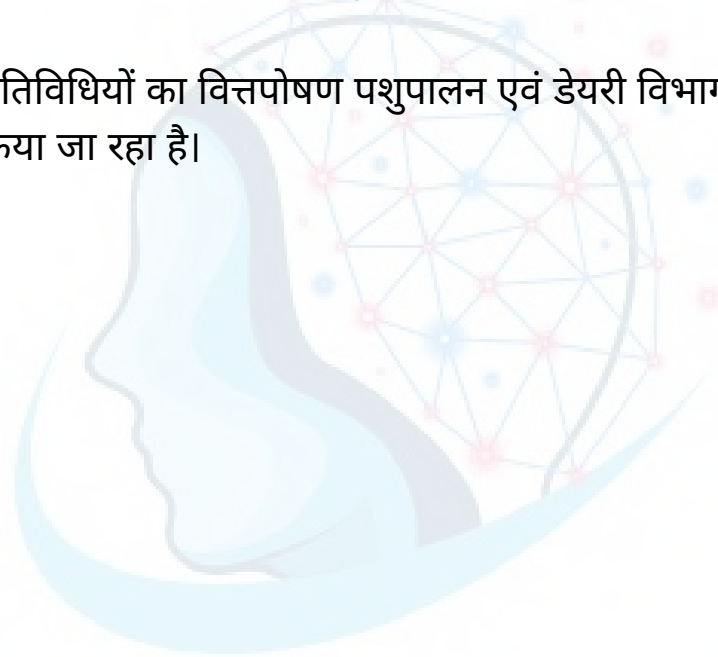
- Union Minister Amit Shah, Ministry of Cooperation, informed the Lok Sabha that the Ministry of Cooperation has launched a cooperative-led initiative called White Revolution 2.0.
- केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने 'श्वेत क्रांति 2.0' नामक सहकारी-नेतृत्व वाली पहल शुरू की है।
- Under this initiative, the target is to increase milk procurement by dairy cooperatives by 50% over the next five years, from 660 lakh kg per day to 1,007 lakh kg per day by 2028–29.
- इस पहल के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध संग्रह को 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 1,007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है।
- White Revolution 2.0 focuses on four priority areas: women's empowerment, enhancing local milk production, strengthening dairy infrastructure, and boosting dairy exports.
- श्वेत क्रांति 2.0 के चार प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं: महिला सशक्तिकरण, स्थानीय दूध उत्पादन में वृद्धि, डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना।
- The initiative aims to empower women milk farmers by strengthening women-led dairy institutions and Self-Help Group (SHG) linkages.
- इस पहल का उद्देश्य महिला दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाना तथा महिला-नेतृत्व वाली डेयरी संस्थाओं और





स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मजबूत करना है।

- It also includes setting up and strengthening around 1.20 lakh new and existing cooperative institutions and increasing India's share in global milk production from one-fourth to one-third by 2030.
- इसमें लगभग 1.20 लाख नई और मौजूदा सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा 2030 तक वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी एक-चौथाई से बढ़ाकर एक-तिहाई करना शामिल है।
- Activities under White Revolution 2.0 are funded through the National Dairy Development Programme 2.0 under the Department of Animal Husbandry and Dairying.
- श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत गतिविधियों का वित्तपोषण पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 के माध्यम से किया जा रहा है।



EXAM
Genius





Ques: Which city will host the 2027 AI Impact Summit?

2027 AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा?

- A) Zurich / ज्यूरिख
- B) Geneva / जिनेवा
- C) Bern / बर्न
- D) Paris / पेरिस
- E) Vienna / वियना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Guy Parmelin, President of Switzerland, announced that the 2027 AI Impact Summit will be held in Geneva.
- स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन ने घोषणा की कि 2027 AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन जिनेवा में होगा।
- He emphasized the need for good global governance of AI, ensuring it is not controlled by a few “big powers.”
- उन्होंने AI के वैश्विक सुशासन पर जोर दिया ताकि यह कुछ “बड़ी शक्तियों” तक सीमित न रहे।
- Parmelin met Narendra Modi for bilateral talks on AI innovation, multilateral cooperation, and trade ties.
- पारमेलिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से AI नवाचार, बहुपक्षीय सहयोग और व्यापार संबंधों पर द्विपक्षीय वार्ता की।
- Discussions included the India–EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) concluded in 2024.
- वार्ता में 2024 में संपन्न भारत–EFTA व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर भी चर्चा हुई।
- He called for smaller countries to organise together and build AI infrastructure.
- उन्होंने छोटे देशों से एकजुट होकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का आह्वान किया।
- The summit will focus on international legal aspects of AI governance.
- यह समिट AI के अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहलुओं पर केंद्रित होगा।
- The UAE will host the 2028 AI Summit after Geneva.
- जिनेवा के बाद 2028 AI समिट की मेजबानी UAE करेगा।





Ques: Where was the 13th edition of Exercise MILAN-2026 inaugurated?

MILAN-2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया?

- A) Mumbai / मुंबई
- B) Kochi / कोच्चि
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Visakhapatnam / विशाखापट्टनम
- E) Port Blair / पोर्ट ब्लेयर

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the 13th edition of Exercise MILAN-2026 at Visakhapatnam, Andhra Pradesh.
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में MILAN-2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया।
- MILAN is a premier multilateral naval exercise hosted by the Indian Navy.
- MILAN भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
- 74 nations are participating, making it the largest and most inclusive edition so far.
- इस बार 74 देशों की भागीदारी है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा और समावेशी संस्करण बनाती है।
- The exercise is being conducted under the Eastern Naval Command at Visakhapatnam.
- यह अभ्यास ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है।
- Aim to Enhance interoperability among navies, strengthen professional competence and deepen maritime cooperation.
- उद्देश्य: नौसेनाओं के बीच संचालन क्षमता (interoperability) बढ़ाना, पेशेवर दक्षता मजबूत करना और समुद्री सहयोग को गहरा करना।
- MILAN has evolved from a regional initiative to a prominent global naval engagement platform.
- MILAN एक क्षेत्रीय पहल से विकसित होकर वैश्विक स्तर का प्रमुख नौसैनिक मंच बन गया है।
- The exercise promotes mutual trust, coordinated responses, and maritime security cooperation.
- यह अभ्यास आपसी विश्वास, समन्वित प्रतिक्रिया और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।





Ques: Which company's 2-nanometer (2nm) semiconductor chip design was launched by Union Minister Ashwini Vaishnaw?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस कंपनी के 2-नैनोमीटर (2nm) सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन का शुभारंभ किया गया?

- A) Qualcomm / क्वालकॉम
- B) Nvidia / एनवीडिया
- C) Intel / इंटेल
- D) AMD / एएमडी
- E) Samsung / सैमसंग

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या :

- Union Minister Ashwini Vaishnaw, along with Karnataka Industries Minister M. B. Patil, inaugurated a world-class electronics manufacturing facility of Zetwerk Electronics at KIADB Hi-Tech, Bengaluru.
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल ने बेंगलुरु स्थित KIADB हाई-टेक में Zetwerk Electronics की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया।
- During the event, he also launched Qualcomm's 2-nanometer (2nm) semiconductor chip design.
- इस अवसर पर उन्होंने Qualcomm के 2-नैनोमीटर (2nm) सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन का भी शुभारंभ किया।
- "Nm" refers to the size of transistors. A smaller size (2nm vs 7nm) allows more transistors to fit on a chip, resulting in faster performance and lower power consumption.
- "Nm" ट्रांजिस्टर के आकार को दर्शाता है। छोटा आकार (2nm बनाम 7nm) अधिक ट्रांजिस्टर को एक चिप पर समाहित करने की अनुमति देता है, जिससे तेज प्रदर्शन और कम बिजली खपत संभव होती है।
- The 2nm chip is specifically designed for advanced AI computing, high-end smartphones, and edge devices.
- यह 2nm चिप उन्नत AI कंप्यूटिंग, हाई-एंड स्मार्टफोन्स और एज डिवाइसेज़ के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है।





Ques: Where was the 1st Meeting of BRICS Sherpas held, which was chaired by India's BRICS Sherpa Sudhakar Dalela?

ब्रिक्स शेरपाओं (BRICS Sherpas) की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर डलेला ने की?

- A) Beijing, China / बीजिंग, चीन
- B) Moscow, Russia / मॉस्को, रूस
- C) Brasília, Brazil / ब्रासीलिया, ब्राज़ील
- D) New Delhi, India / नई दिल्ली, भारत
- E) Cape Town, South Africa / केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The 1st Meeting of BRICS Sherpas was held in New Delhi.
- ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- The meeting was chaired by India's BRICS Sherpa Sudhakar Dalela, Secretary (Economic Relations).
- इस बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा और आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर डलेला ने की।
- This was the first edition of the BRICS Sherpas' meeting under India's leadership.
- यह भारत के नेतृत्व में आयोजित ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक थी।
- The theme of the meeting was "Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability."
- बैठक की थीम थी — "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।"





Ques: How many villages are covered under Vibrant Villages Programme–II (VVP–II)?

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–II (VVP–II) के तहत कितने गांव शामिल किए गए हैं?

- A) 1,500
- B) 1,800
- C) 1,954
- D) 2,100
- E) 2,500

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Union Home Minister Amit Shah launched Vibrant Villages Programme–II (VVP–II) in Nathanpur village, Assam at a cost of ₹6,839 crore.
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नाथनपुर गांव से ₹6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–II (VVP–II) की शुरुआत की।
- Under VVP–II, nearly ₹6,900 crore will be spent covering 1,954 villages across 334 blocks in 17 States.
- VVP–II के तहत लगभग ₹6,900 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें 17 राज्यों के 334 ब्लॉकों के 1,954 गांव शामिल हैं।
- In Assam alone, the scheme covers 9 districts, 26 blocks and 140 villages.
- केवल असम में यह योजना 9 जिलों, 26 ब्लॉकों और 140 गांवों को कवर करती है।
- States covered include Arunachal Pradesh, Bihar, Gujarat, Jammu & Kashmir, Ladakh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam.
- योजना में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं।
- The programme focuses on border villages adjoining international borders, improving infrastructure, connectivity, security and welfare saturation.
- यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की संतृप्ति पर केंद्रित है।
- Shri Amit Shah said border villages will no longer be called the “last village” but the





Ques: Where was the first CM Shri School inaugurated under Delhi's AI-driven model?

दिल्ली के AI-संचालित मॉडल के तहत पहला CM श्री स्कूल कहाँ उद्घाटित किया गया?

- A) Rohini / रोहिणी
- B) Lajpat Nagar / लाजपत नगर
- C) Sarojini Nagar / सरोजिनी नगर
- D) Dwarka / द्वारका
- E) Karol Bagh / करोल बाग

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Rekha Gupta inaugurated the first CM Shri School at Sarojini Nagar.
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरोजिनी नगर में पहले CM श्री स्कूल का उद्घाटन किया।
- Foundation laid for 75 such schools across Delhi.
- दिल्ली भर में 75 ऐसे स्कूलों की आधारशिला रखी गई।
- The model is AI-driven and focuses on modern digital learning infrastructure.
- यह मॉडल AI-संचालित है और आधुनिक डिजिटल शिक्षा ढांचे पर आधारित है।
- The event was attended by Dharmendra Pradhan.
- इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रहे।
- The project targets students from economically weaker, lower and middle-income families.
- यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के छात्रों पर केंद्रित है।
- Aim is to provide facilities comparable to top private schools.
- उद्देश्य है छात्रों को शीर्ष निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं प्रदान करना।





Ques: Who from Puducherry won the Chang–Crandall Humanitarian Award 2026 for exceptional contributions in cataract blindness prevention and visual disability care?

पुडुचेरी से किन व्यक्तियों को मोतियाबिंद अंधत्व निवारण और दृष्टि दिव्यांगता देखभाल में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 का चांग–क्रैंडल मानवीय पुरस्कार प्रदान किया गया?

- A) Dr. Aravind Prasad & Dr. Meena Rao / डॉ. अरविंद प्रसाद और डॉ. मीना राव
- B) Dr. Haripriya Aravind & Dr. R. Venkatesh / डॉ. हरिप्रिया अरविंद और डॉ. आर. वेंकटेश
- C) Dr. V. Shanmugam & Dr. K. Ramesh / डॉ. वी. शनमुगम और डॉ. के. रमेश
- D) Dr. R. Venkatesan & Dr. Harini Devi / डॉ. आर. वेंकटेशन और डॉ. हरिणी देवी
- E) Dr. S. Balakrishnan & Dr. N. Kavitha / डॉ. एस. बालकृष्णन और डॉ. एन. कविता

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Dr. Haripriya Aravind and Dr. R. Venkatesh from Puducherry won the Chang–Crandall Humanitarian Award 2026.
- पुडुचेरी से डॉ. हरिप्रिया अरविंद और डॉ. आर. वेंकटेश को 2026 का चांग–क्रैंडल मानवीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- They were honoured for their exceptional contributions in cataract blindness prevention and visual disability care.
- उन्हें मोतियाबिंद से होने वाली अंधता की रोकथाम और दृष्टि दिव्यांगता देखभाल में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- The award was presented at the American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) Foundation conference.
- यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रेक्टिव सर्जरी (ASCRS) फाउंडेशन सम्मेलन में प्रदान किया गया।
- The conference was held in Washington DC, United States of America.
- यह सम्मेलन वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ।
- The Chang–Crandall Humanitarian Award carries a prize money of USD 100,000.
- चांग–क्रैंडल मानवीय पुरस्कार के अंतर्गत 1,00,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।





Ques: VoicERA, recently launched at the India AI Impact Summit 2026, is related to which field?

India AI Impact Summit 2026 में लॉन्च किया गया VoicERA किस क्षेत्र से संबंधित है?

- A) Quantum Computing / क्वांटम कंप्यूटिंग
- B) Blockchain Governance / ब्लॉकचेन गवर्नेंस
- C) Voice AI Stack / वॉइस AI स्टैक
- D) Satellite Communication / सैटेलाइट कम्युनिकेशन
- E) Cyber Warfare / साइबर वारफेयर

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) unveiled VoicERA, an open-source, end-to-end Voice AI stack.
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने VoicERA नामक ओपन-सोर्स एंड-टू-एंड Voice AI स्टैक लॉन्च किया।
- It was launched at the India AI Impact Summit 2026.
- इसे India AI Impact Summit 2026 में लॉन्च किया गया।
- Initiative led by the Digital India BHASHINI Division under Digital India Corporation.
- यह पहल Digital India Corporation के तहत डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन द्वारा संचालित है।
- VoicERA is deployed on the BHASHINI National Language Infrastructure.
- VoicERA को BHASHINI राष्ट्रीय भाषा अवसंरचना पर तैनात किया गया है।
- It provides a national execution layer for multilingual Voice & Language AI.
- यह बहुभाषी Voice एवं Language AI के लिए राष्ट्रीय निष्पादन परत प्रदान करता है।
- Platform is open, modular, interoperable, cloud-deployable & on-premise ready.
- यह प्लेटफॉर्म ओपन, मॉड्यूलर, इंटरऑपरेबल, क्लाउड-डिप्लॉयबल और ऑन-प्रीमाइस तैयार है।
- Supports real-time speech systems, conversational AI & multilingual telephony.
- यह रियल-टाइम स्पीच सिस्टम, कन्वर्सेशनल AI और बहुभाषी टेलीफोनी को सपोर्ट करता है।
- Enables voice-enabled citizen services in areas like agriculture, education, grievance redressal & scheme discovery.
- कृषि, शिक्षा, शिकायत निवारण और योजनाओं की जानकारी जैसे क्षेत्रों में वॉइस-आधारित नागरिक सेवाओं को सक्षम बनाता है।

